न्यू देहली पोस्ट

वर्ष 13 ■ अंक 17 रविवार (साप्ताहिक) 4 मई 2025 ■ पृष्ठ 16 ■ मूल्य 5 रुपये

16

मिडल स्टंप पर सिक्का क्यों रखते थे गुरु रमाकांत आचरेकर?

अंदर विशेष

आंकड़ों के आईने में बीजेपी सरकार का सच
पृष्ठ 3 पर

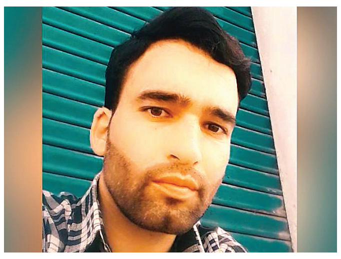

आतंकियों से लड़ते -लड़ते शहीद हो गए जांबाज आदिल हुसैन
पृष्ठ 6 पर

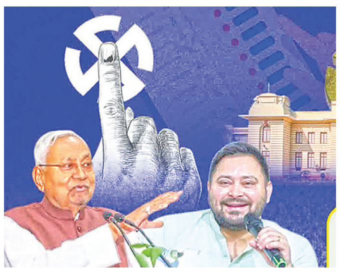

सितंबर में चुनाव आयोग कर सकता है चुनाव की घोषणा
पृष्ठ 8 पर

क्या कांच उद्योग ताजमहल की चमक को कर रहा धुंधला?
पृष्ठ 10 पर

आखिर किडनी काम करना क्यों बंद कर देती है?
पृष्ठ 13 पर

ड्रैगन की लूट का अड्डा बना नेपाल का पोखरा एयरपोर्ट
पृष्ठ 15 पर

योग गुरु या सामाजिक ज़हर का सौदागर ?

भगवा वस्त्रों की आड़ में एक चालाक व्यापारी, कोर्ट ने चेतावनी दी कि बार-बार माफी मांगने की संस्कृति अब स्वीकार्य नहीं होगी

रामदेव का भविष्य अब न केवल उनके व्यापार पर, बल्कि भारतीय समाज की एकता और न्याय व्यवस्था की साख पर भी निर्भर करता है। यह समय है कि देश तय करे—क्या वह एक ऐसे व्यक्ति को बख्शेगा, जो शरबत के नाम पर ज़हर घोल रहा है? 'शरबत जिहाद' विवाद पर एक तीखा विश्लेषण!

विशेष संवाददाता/नई दिल्ली

बाबा रामदेव, जिन्होंने योग और आयुर्वेद के नाम पर एक विशाल व्यापारिक साम्राज्य खड़ा किया, आज एक बार फिर विवादों के केंद्र में हैं। इस बार मुद्दा न केवल उनके भ्रामक विज्ञापनों या उत्पादों की गुणवत्ता का है, बल्कि एक ऐसी टिप्पणी का है, जिसने भारतीय समाज की एकता पर सीधा प्रहार किया है। उनकी 'शरबत जिहाद' वाली टिप्पणी ने न केवल सामाजिक समरसता को ठेस पहुंचाई, बल्कि यह सवाल भी खड़ा किया कि क्या रामदेव सचमुच एक योग गुरु हैं, या भगवा वस्त्रों की आड़ में एक चालाक व्यापारी, जो धर्म और राष्ट्रवाद को बेचने का धंधा कर रहा है? लेकिन अब सवाल यह है — क्या बार-बार का यह 'माफीनामा जुगाड़' उन्हें हमेशा बचा लेगा? क्या यह समय नहीं कि कानून और समाज इस 'भगवा बाबा' की असलियत को पहचाने और सख्त कार्रवाई करे?

दिल्ली उच्च न्यायालय की सख्ती- 'ज़हर घोलने की आज़ादी नहीं' : दिल्ली उच्च न्यायालय ने रामदेव की 'शरबत जिहाद' टिप्पणी को "अंतरात्मा को झकझोर देने वाला" और "सभ्य समाज के लिए अस्वीकार्य" करार दिया। रामदेव ने पतंजलि के गुलाब शरबत को बढ़ावा देने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से दावा किया था कि रूह अफजा जैसे उत्पादों से मदरसों और मस्जिदों को फंडिंग होती है। शेष १ पर

अब सवाल यह है

क्या रामदेव का बार-बार माफी मांगने का सिलसिला हमेशा चलता रहेगा?
क्या अदालत इस बार सख्त कार्रवाई करेगी, या फिर रामदेव एक बार फिर अपने 'माफीनामा जुगाड़' से बच निकलेंगे?
क्या भारतीय जनता इस 'भगवा चोले में छिपे चतुर बनिए' की असलियत को समझ पाएगी?

जनता का गुस्साः 'बाबा को अब बक्शा नहीं जाएगा'

सोशल मीडिया पर रामदेव और पतंजलि के खिलाफ गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैंः #BanPatanjali, #SharbatJihadExposed #ChaturBaniyaInBhagwa
लाखों लोगों ने रामदेव की गिरफ्तारी की मांग की है, और कई उपभोक्ता समूहों ने पतंजलि उत्पादों के बहिष्कार का आह्वान किया है। खासकर उन शहरों में, जहां अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी अधिक है, पतंजलि स्टोर्स पर बिक्री में कमी देखी गई है।

तो ये है पहलगाम आतंकी हमले का मास्टर माइंड !

न्यूज़ डेस्क

पाकिस्तानी आतंकियों ने एक बार फिर से भारत को ललकारते हुए जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमला कर 28 लोगों की जाने ले ली है। इनमे दो विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। भारत इस हमले का कितना बड़ा जवाब देगा ,पाकिस्तान इसकी कल्पना तक नहीं कर सकता। हालांकि पाकिस्तान ने इस हमले से खुद को अलग रख लिया है। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान और वहां की आतंकी संगठन भारत के खिलाफ बार -बार हमला करने से बाज नहीं आता। लेकिन भारत अबकी बार पाकिस्तानी आतंकियों को वह सबक सिखाने की तैयारी कर रहा है जिसकी कल्पना कभी पाकिस्तान की सरकार और उसकी ख़ुफ़िया एजेंसी आईएसआई ने भी नहीं की होगी। भारत अभी इस पुरे मामले की गंभीरता से जांच कर रहा है और अंजाम तक पहुँचते ही पाकिस्तान को कड़ा जवाब देगा। हालांकि जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम दिया गया है उससे ख़ुफ़िया एजेंसी के फेल होने की भी बात कही जा रही है। आखिर देश की तमाम ख़ुफ़िया एजेंसी को इस हमले की जानकारी क्यों और कैसे नहीं मिल पाई ?

उधर बड़ी बात यह है कि खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान स्थित आतंकी समूह लश्कर-ए-तैयबा के एक वरिष्ठ कमांडर सैफुल्ला कसूरी की पहचान इस हत्याकांड के पीछे के मास्टरमाइंड के रूप में की है, जिसे खालिद के नाम से भी जाना जाता है। सूत्रों ने बताया कि सैफुल्लाह खालिद पाकिस्तान के गुजरांवाला शहर से अपनी गतिविधियां चला रहा है। आतंकी खालिद ने कश्मीर नीति में पाकिस्तान की रणनीतिक बदलाव पर सार्वजनिक रूप से निराशा व्यक्त की थी, खासकर भारत द्वारा 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद। उसने कश्मीर में लश्कर के अभियानों को कम करने के पाकिस्तानी सरकार के फैसले की भी आलोचना की थी, और इसके लिए बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जैसे क्षेत्रों में बढ़ती हिंसा को जिम्मेदार ठहराया था।

शेष १ पर

पहलगाम में टीआरएफ आतंकी समूह का हमला, भारत की संप्रभुता पर चोट

विशेष संवाददाता

आखिर वही हुआ जिसकी सम्भावना दिख रही थी। मौका मिलते ही पाकिस्तानी आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम के भीड़भाड़ इलाके पर हमला किया और खबर लिखे जाने तक 27 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी। मरने वालों में दो विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं।

जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने शांत पहलगाम में पच्चास राउंड तक गोलियां चलाई है।जाँच एजेंसियों ने घटना स्थल से लगभग 60 गोलियों के खोखे बरामद किये हैं। बड़ी बात ये है कि आतंकी आधुनिक हथियार से लैश थे और उनके पास एम 4 अमेरिकी कार्बाइन से लेकर एके 47 जैसे आधुनिक हथियार भी थे। शुरूआती जांच से ये भी पता चलता है कि आतंकी खुद को सेफ करने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहन रखे थे। आतंकियों की इस तैयारी से पता चलता है कि वे बड़ी तैयारी के साथ घटना को अंजाम देने पहुंचे थे। जानकार मान रहे हैं कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक़ भले ही अभी तक 27 लोगों के मारे जाने की खबर है लेकिन मरने वालों की संख्या इससे कही ज्यादा बताई जा रही है। शेष १ पर

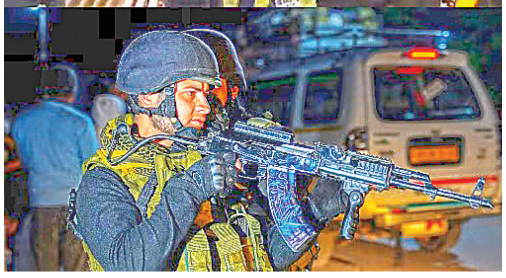

मोदी सरकार को...

यह बयान न केवल सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने का प्रयास था, बल्कि 100 साल पुराने एक लोकप्रिय ब्रांड को निशाना बनाकर बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने की चाल भी थी। न्यायमूर्ति अमित बंसल ने सख्त लहजे में कहाः "इस देश में व्यापार की स्वतंत्रता है, लेकिन सांप्रदायिक ज़हर घोलने की आज़ादी किसी को नहीं दी जा सकती।" कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि बार-बार माफी मांगने की संस्कृति अब स्वीकार्य नहीं होगी। यह पहली बार नहीं है जब रामदेव को अदालत की फटकार झेलनी पड़ी हो, लेकिन इस बार का मामला उनकी अब तक की सबसे गंभीर गलती माना जा रहा है।

ऐतिहासिक संदर्भ : धर्म और व्यापार का पुराना गठजोड़

रामदेव की रणनीति कोई नई बात नहीं है। भारतीय इतिहास में कई बार व्यापारियों ने धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए किया है। 1990 के दशक में, बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद, कुछ कंपनियों ने अपने उत्पादों को 'हिंदुत्व' या 'स्वदेशी' के साथ जोड़कर बाजार में जगह बनाई थी। रामदेव ने इस रणनीति को और परिष्कृत किया है। वह न केवल 'स्वदेशी' का नारा बुलंद करते हैं, बल्कि अपने उत्पादों को 'दिव्य' और 'पवित्र' बताकर उपभोक्ताओं की भावनाओं का दोहन करते हैं। वरिष्ठ इतिहासकार डॉ. रामचंद्र गुहा ने इस बारे में लिखा है:"रामदेव का मॉडल आधुनिक भारत में धर्म और व्यापार के खतरनाक गठजोड़ का प्रतीक है। वह योग और आयुर्वेद को बेचने की आड़ में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं।"

पतंजलि का विवादों से चोली-दामन का साथ

पतंजलि का इतिहास विवादों से भरा पड़ा है। चाहे वह भ्रामक विज्ञापन हों, उत्पादों में मिलावट हो, या फिर वैज्ञानिक दावों का खंडन—रामदेव और उनकी कंपनी हर बार सुर्खियों में रही है।

1. न्यायिक फटकार और माफीनामों का सिलसिला

2022-23: सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों पर कड़ा रुख अपनाया, जिसमें मधुमेह और उच्च रक्तचाप के 'चमत्कारी इलाज' के दावे शामिल थे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने आरोप लगाया कि पतंजलि एलोपैथी के खिलाफ गलत प्रचार कर रही है।तीन बार माफीः रामदेव को अब तक कम से कम तीन बार अदालत में सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ी है, लेकिन हर बार वह नए विवाद में कूद पड़ते हैं।

2. उत्पादों की गुणवत्ता पर सवाल

एफडीए रिपोर्ट्स (2021-23): पतंजलि के मधु, अश्वगंधा चूर्ण और अन्य उत्पादों में मिलावट पाई गई।राजस्थान ड्रग कंट्रोलः 'दिव्य फार्मा' की कुछ दवाओं में स्टेरॉयड डेक्सामेथासोन जैसे हानिकारक पदार्थ पाए गए। सीएसई अध्ययनः पतंजलि के टूथपेस्ट में मर्क्युरी और लेड की अत्यधिक मात्रा की पुष्टि हुई, जो उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है।

3. 'कोरोनिल' विवाद : वैज्ञानिक समुदाय की चुनौती : 2020 में, जब पूरा देश कोविड-19 की चपेट में था, रामदेव ने 'कोरोनिल' को कोरोना का 'रामबाण इलाज' बताकर सनसनी फैला दी। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) ने इस दावे को खारिज करते हुए इसे "गैर-जिम्मेदाराना" करार दिया। सरकार को मजबूरन सफाई देनी पड़ी कि कोरोनिल केवल एक "इम्यूनिटी बूस्टर" है, न कि इलाज। फिर भी, पतंजलि ने इस उत्पाद की बिक्री से करोड़ों रुपये कमाए।

'शरबत जिहाद': सांप्रदायिक ज़हर का नया अध्याय

रामदेव की 'शरबत जिहाद' टिप्पणी कोई तात्कालिक प्रतिक्रिया नहीं थी। समाजशास्त्रियों का मानना है कि यह एक सुनियोजित रणनीति थी, जिसके पीछे निम्नलिखित कारण हो सकते हैं:

बाजार हिस्सेदारी की जंगः अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा पतंजलि उत्पादों को कम खरीदे जाने से उत्पन्न रोष। रूह अफजा पर हमलाः 100 साल पुराने इस लोकप्रिय ब्रांड को निशाना बनाकर पतंजलि का गुलाब शरबत बाजार में लाना।धार्मिक ध्रुवीकरणः व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा को सांप्रदायिक रंग देकर उपभोक्ताओं को लुभाना। वरिष्ठ समाजशास्त्री प्रो. शफीक अंसारी ने कहा-"शरबत के नाम पर ज़हर घोलने वाला यह व्यक्ति सिर्फ व्यापारी नहीं, समाज का अपराधी है। यह सिर्फ रूह अफजा पर हमला नहीं, बल्कि भारत की साझा संस्कृति पर हमला है।"

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं: विपक्ष का आक्रोश, सत्ता पक्ष की चुप्पी

रामदेव के बयान पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, जबकि सत्ताधारी दल की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है।कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेतः "हर बार कोर्ट में माफी मांगता है, और फिर नए विवाद में कूद पड़ता है। यह माफीनामा उद्योग कब बंद होगा? सरकार की चुप्पी इसकी मिलीभगत को दर्शाती है।"सीपीएम नेता मोहम्मद सलीमः "बाबा अब केवल योग नहीं बेचते, अब ये धार्मिक उन्माद का डिस्ट्रीब्यूटर भी बन चुके हैं।"राजद नेता तेजस्वी यादवः "शरबत नहीं, ज़हर बेच रहा है ये बाबा। यह देशद्रोह है, और सरकार की मिलीभगत का परिणाम है।" एनसीपीआर अध्यक्ष प्रियंक कानूनगोः "बच्चों तक को भ्रमित करने वाले विज्ञापन और धार्मिक जहर पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।" भाजपा की चुप्पीः सत्ताधारी दल ने इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया, जिसे विपक्ष ने "मौन समर्थन" करार दिया है।

रामदेव की रणनीति : 'स्वदेशी' और 'साजिश' का खेल

हर विवाद के बाद रामदेव एक ही रणनीति अपनाते हैं:'अंतरराष्ट्रीय साजिश' का कार्डः वह दावा करते हैं कि वैश्विक दवा कंपनियां और 'पश्चिमी ताकतें' उनके खिलाफ साजिश रच रही हैं।

'स्वदेशी' की ढाल: अपने उत्पादों को 'भारतीय संस्कृति का हिस्सा' बताकर जनता की भावनाओं को भुनाना। योग गुरु की छविः योग और अध्यात्म की आड़ में अपने विवादास्पद बयानों को छिपाना। लेकिन इस बार जनता का धैर्य जवाब दे रहा है। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखाः "रामदेव का असली चेहरा अब सामने है। ये बाबा नहीं, एक चालाक बनिया है, जो भगवा कपड़ों की आड़ में देश को ठग रहा है।"

निष्कर्षः एक 'दिव्य' भ्रमजाल का अंत?

बाबा रामदेव का व्यक्तित्व और उनका व्यापारिक मॉडल एक जटिल विरोधाभास प्रस्तुत करता है। एक ओर वह योग और आयुर्वेद को वैश्विक मंच पर ले जाने का दावा करते हैं, दूसरी ओर उनके भ्रामक विज्ञापन, सांप्रदायिक बयान और वैज्ञानिक दावों का खंडन उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं। 'शरबत जिहाद' विवाद ने न केवल पतंजलि की व्यावसायिक नैतिकता को कटघरे में खड़ा किया है, बल्कि भारतीय समाज में बढ़ती सांप्रदायिक खाई को भी उजागर किया है।

जातीय हित के लिए...

कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि यह पुलवामा अटैक से भी बड़ा हमला था। लश्कर-ए-तैयबा के नए मोर्चे 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। खुफिया सूत्रों के अनुसार, आतंकियों ने इस हमले से पहले इलाके की रेकी की थी। इस हमले ने न केवल भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर भी चिंता बढ़ा दी है। सऊदी अरब के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना कार्यक्रम बदल लिया है और जल्द ही भारत लौट गए हैं। दिल्ली पहुँचते ही पीएम ने बड़े अधिकारियों के साथ एयरपोर्ट पर ही बैठक कर पुरे मामले की जानकारी ली है और आगे की रणनीति पर काम करने की बात कही है। घटनास्थल और आसपास के इलाकों में भारी सुरक्षाबल तैनात किए गए हैं। सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। रूस और अमेरिका के राष्ट्रपतियों ने भी इस घटना पर दुख जताया है।

पीएम मोदी लौटे भारत

पीएम नरेंद्र मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, "इस हमले के पीछे जो भी है, उसे बख्शा नहीं जाएगा।" भारत लौटने के बाद पीएम मोदी की अध्यक्षता में आतंकियों के सफाए को लेकर उच्च स्तरीय बैठक होने की संभावना है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने जताया शोक

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों की मौत पर शोक व्यक्त किया और इसकी कड़ी निंदा की। ट्रम्प ने अपने पोस्ट में लिखा, "कश्मीर से चिंताजनक खबर आई है। अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। हम मारे गए लोगों की आत्मा की शांति और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। पीएम मोदी और भारत के अद्भुत लोगों को हमारा पूर्ण समर्थन और गहरी संवेदना है।"

रूस ने भी की हमले की निंदा

रूस ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम हमले पर कड़ा ऐतराज जताया है। रूस के राजदूत डेनिस अलिपोव ने पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले पर भारत के लोगों और सरकार के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने ट्वीट कर कहा, "रूस भारत के साथ पूरी तरह खड़ा है।" जम्मू-कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हमले में निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाए जाने से लोगों में भारी आक्रोश है। देशभर में केंडल मार्च और विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोगों ने 'पाकिस्तान होश में आओ' जैसे नारों के साथ आतंकियों और उनके आकाओं के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला न केवल निर्दोष लोगों की जान लेने वाला कृत्य है, बल्कि यह भारत की संप्रभुता, कश्मीर की शांति और पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था पर सीधा हमला है। पूरे देश में इस घटना के खिलाफ एकजुटता देखने को मिल रही है। अब निगाहें केंद्र सरकार की ओर हैं कि वह इस हमले का क्या जवाब देती है और आगे की रणनीति क्या होती है।

'पर्यटन नहीं, भविष्य पर हमला'

सोशल मीडिया पर भी हमले को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एक उपयोगकर्ता युसरा इकबाल ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, पहलगाम में एक पर्यटक पर चलाई गई हर गोली कश्मीर की अर्थव्यवस्था, छवि और भविष्य पर चलाई गई गोली है। उन्होंने आतंकियों को मानवता और कश्मीर दोनों का दुश्मन बताया। भारतीय सेना की चिनार कोर ने ट्वीट किया, 22

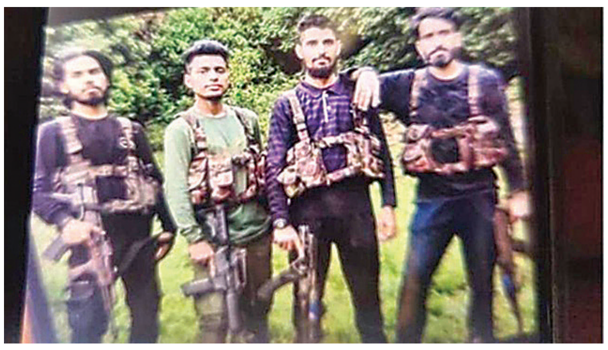

अप्रैल 2025 को, हिंसा की एक कायरतापूर्ण और दिल दहला देने वाली घटना में, आतंकवादियों ने निर्दोष पर्यटकों और स्थानीय लोगों पर गोलीबारी की। घटना के तुरंत बाद, संयुक्त बल स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। चिकित्सा दल को तुरंत तैनात किया गया और हताहतों को निकालने का काम शुरू किया गया। इस मूर्खतापूर्ण हिंसा और स्थानीय भावनाओं को आहत करने के जवाब में, स्थानीय लोगों द्वारा सोपोर, गंदेरबल, हंदवाड़ा, बांदीपोरा और कश्मीर के अन्य हिस्सों में कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। भारतीय सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा बैसरन, पहलगाम, अनंतनाग के सामान्य क्षेत्र में एक संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया गया है। तलाशी अभियान अभी जारी है, जिसमें हमलावरों को न्याय के कटघरे में लाने पर पूरा ध्यान केंद्रित किया गया है।

विपक्ष का हमला

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की और सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की। राहुल गांधी ने हमले को कायराना और दिल दहला देने वाला करार देते हुए कहा कि सरकार को अब जम्मू-कश्मीर में हालात सामान्य होने के खोखले दावों की जगह जवाबदेही लेनी चाहिए।

सभी दलों ने दिखाया एकजुटता का संदेश

महबूबा मुफ्ती, प्रमोद तिवारी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, एकनाथ शिंदे, लालू यादव जैसे तमाम नेताओं ने हमले की कड़ी निंदा की है। लालू यादव ने कहा कि केंद्र सरकार को त्वरित कार्रवाई कर सख्त संदेश देना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी भारतीय इस तरह की बर्बरता का शिकार न हो।

क्या है आतंकी 'द रेजिस्टेंस फ्रंट'

जानकारी के मुताबिक़ जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ का गठन किया गया था, जो शुरू में एक ऑनलाइन यूनिट के रूप में काम करता था। छह महीने के भीतर यह लश्कर-ए-तैयबा सहित विभिन्न गुटों के आतंकवादियों को इंटिग्रेट करके एक फिजिकल ग्रुप में विकसित हो गया। टीआरएफ की स्थापना को पाकिस्तान द्वारा एक रणनीतिक पैंतरेबाजी के रूप में देखा गया था, जो उस समय अपने आतंकी फंडिंग संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्य बल के दबाव का जवाब दे रहा था.

पाकिस्तान की आईएसआई ने किया निर्माण

माना जाता है कि टीआरएफ का निर्माण पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी आईएसआई द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य लश्कर-ए-तैयबा से अंतरराष्ट्रीय ध्यान हटाना था। खासकर 2018 में पाकिस्तान को वित्तीय कार्रवाई कार्य बल यानी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद। भारत ने आधिकारिक तौर पर 2023 में टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित किया था। 2019 में अपनी स्थापना के बाद से समूह ने कई हमलों को अंजाम दिया और खुद को इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खतरे के रूप में स्थापित किया।

टीआरएफ का संस्थापक है शेख सज्जाद गुल

शेख सज्जाद गुल, जिसे शेख सज्जाद के नाम से भी जाना जाता है, एक कश्मीरी आतंकवादी और प्रतिरोध मोर्चा का संस्थापक है। 14 जून 2018 को श्रीनगर में प्रमुख पत्रकार शुजात बुखारी और उनके दो निजी सुरक्षा अधिकारियों की हत्या के मामले में उसका नाम आया था। आतंकवाद में उसकी संलिप्तता के कारण भारतीय गृह मंत्रालय ने 2022 में गुल को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत आतंकवादी घोषित किया। टीआरएफ से जुड़े अन्य उल्लेखनीय आतंकवादियों में साजिद जट्ट और सलीम रहमानी शामिल हैं - सभी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हैं।

आतंकी संगठन की कार्यप्रणाली

पुलिस अधिकारी ने कहा कि टीआरएफ की रणनीति 2016 के बाद के उग्रवाद से अलग है। इसमें कोई फिदायीन हमलावर नहीं होता। कैडरों की बहुत कम तस्वीरें उपलब्ध हैं और वे जमीनी कार्यकर्ताओं के व्यापक आधार नेटवर्क के माध्यम से आसान टारगेट चुनते हैं। कार्यकर्ताओं की एक नई नस्ल तैयार की गई है जो सुरक्षा बलों के रडार पर नहीं हैं, जिससे उनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है और हमला करना आसान हो जाता है।

तकनीक प्रेमी आतंकवादी

रेजिस्टेंस फ्रंट जम्मू-कश्मीर के लोगों को सरकार के खिलाफ आतंकवादी संगठनों में शामिल होने के लिए उकसाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन में शामिल है। इस फेसलेस और तकनीक प्रेमी संगठन ने अपने मैसेज को प्रचारित करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। अधिकारियों का कहना है कि टीआरएफ ने कश्मीर में सीआरपीएफ और सेना पर हमलों को शूट करने के लिए गोप्रो जैसे बॉडी कैमरों का इस्तेमाल किया। टीआरएफ ने कश्मीरी पंडितों, सिखों, हिंदुओं और मुसलमानों सहित विभिन्न धार्मिक आधार पर लोगों को निशाना बनाया है। अप्रैल 2020: कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास 1 अप्रैल 2020 से शुरू हुई चार दिवसीय गोलीबारी की सूचना मिलने के बाद टीआरएफ का नाम पहली बार सामने आया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) से पांच घुसपैठियों ने केरन के दुर्गम इलाके में जमी बर्फ में पांच दिनों से अधिक समय तक कब्जा करके सुरक्षाकर्मियों को चौंका दिया।

जातीय हित के लिए...

माना जाता है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में स्थित दो अन्य गुर्गों ने भी हमले को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई थी। हमलावर प्रतिबंधित लश्कर की एक शाखा द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) के सदस्य थे, जिन्होंने कथित तौर पर दोपहर करीब 2:30 बजे निहत्थे पर्यटकों के एक समूह को निशाना बनाकर हमला किया। इस क्रूर हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बंदूकधारियों द्वारा अंधाधुंध गोलीबारी किए जाने के कारण अराजकता और भय का माहौल था।इन हत्याओं ने पूरे देश में आक्रोश और शोक की लहर फैला दी है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक, हमले में पांच से छह आतंकवादी शामिल थे, जिनमें से कई हाल ही में नियंत्रण रेखा पार करके घाटी में घुसे थे। सुरक्षा बलों ने तब से पहलगाम क्षेत्र में और उसके आसपास बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है, जिसमें अपराधियों का पता लगाने के लिए हवाई निगरानी और जमीनी अभियान चलाए जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने इस जघन्य हमले में शामिल तीन आतंकवादियों के स्केच जारी किए हैं। एनआईए जांच में शामिल हुई सूत्रों ने बताया कि एक महानिरीक्षक के नेतृत्व में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की एक टीम जम्मू-कश्मीर के आतंकवाद प्रभावित पहलगाम पहुंच गई है। यह दल स्थानीय पुलिस को सहायता प्रदान करेगा।

न्यू देहली पोस्ट
28 अप्रैल से 4 मई 2025
संपादकीय कार्यालय : मुद्रक व प्रकाशक आशीष कुमार द्वारा विभा पब्लिकेशन डी-160 बी, सेक्टर-7, नोएडा से मुद्रित एवं 262ए, सेक्टर-4, वैशाली गाजियाबाद से प्रकाशित। RNI NO. UPHIN/2013/49239
संपादक : आशीष कुमार, **प्रसार प्रबंधक** : दशरथ सिंह
Postal registration Number: UP/GBD-181/2013-15, **हमसे संपर्क करें** : postnewdelhi@gmail.com

न्यू देहली पोस्ट

संपादकीय

जहरीले पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त

पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों ने जिस तरह का कायराना हरकत करते हुए 28 से ज्यादा पर्यटकों की हत्या की है और हमारे सम्प्रभुता पर हमला किया है ,उसका जवाब तो भारत देगा ही लेकिन गोली बरसाते हुए आतंकियों ने जो बातें कही है वह ज्यादा ही डरावनी है और चुनौती भरा भी। आतंकियों की यह ऐसी चुनौती है जिससे यह भी पता चलता है कि पहलगाम में जो कुछ भी हुआ वह केवल आतंकियों का खेल नहीं था ,सच तो यही है कि पहलगाम में जो नरसंहार को अंजाम दिया गया वह पाकिस्तान ने ही किया। अंतर केवल यही है कि पाकिस्तान ने यह काम अपने सेना द्वारा अंजाम नहीं देकर अपने आतंकियों के जरिये कराया। विकास के पथ पर अग्रसर भारत और जम्मू कश्मीर में लौट रहे अमन चैन से पाकिस्तान को अभी जितनी खींज है ,शायद इससे पहले कभी नहीं थी। पाकिस्तान खुद ही गृह युद्ध की चपेट में है। पाकिस्तान के कई इलाके खुद को आजाद होने की लड़ाई लड़ रहे हैं। पाकिस्तानी सेना का भी वहां कोई बस नहीं चल रहा। फिर आर्थिक रूप से दरिद्र हो चुका पाकिस्तान को अब लग रहा है कि आखिर भारत पूरी दुनिया के साथ हाथ मिलाते हुए कैसे आगे बढ़ रहा है ? पाकिस्तान जानता है कि वह भारत से सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकता। वह वर्षों से भारत के साथ छद्म लड़ाई ही लड़ता रहा है और वह भी अपने आतंकी गुर्गो के जरिये। लेकिन अब पाकिस्तान की कई घटनाओं ने भारत के सब्र को भी ख़त्म कर दिया है।

पहलगाम हमले के दौरान एक आतंकी ने गोली मारने से पहले कई पर्यटकों से उिनके धर्म के बारे में भी पूछा। यह एक नयी बात थी और खतरनाक भी। और यह सब शायद इसलिए कि भारत की राजनीति में इन दिनों हिन्दू -मुसलमानो की राजनीति कुछा ज्यादा ही बढ़ गई है। जाहिर है आतंकियों ने जो धर्म की पहचान करके गोलियां चलाई है वह सब एक सोंची -समझी कहानी का हिस्सा है। सबसे डरावनी बात तो यह है कि आतंकियों ने गोली चलते हुए यह भी कहा कि ''जाओ मोदी को बता दो ''ने सरकार और बीजेपी के अंदरखाने में भी सनसनी पैदा कर दी है। पाक आतंकियों का यह बयान भारत के जन मानस को और भी भड़का दिया है। एक अत्यंत विश्वसनीय सूत्र के अनुसार, जब आतंकियों का यह कथन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचा, तो उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। हालांकि वे स्पष्ट रूप से क्रोधित थे, लेकिन वे शांत थे, तथापि पर्दे के पीछे से हमले की साजिश रचने वालों को जवाबदेह ठहराने के अपने संकल्प में अडिग थे।एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने टिप्पणी की, "देश नहीं झुकने देंगे! अब इस पंक्ति को कहने वाले लोग देखेंगे कि मोदी क्या करने में सक्षम हैं।" उन्होंने संकेत दिया कि भारत के पास जवाब देने के लिए सभी विकल्प खुले हैं, "जिस तरह की प्रतिक्रिया पाकिस्तान ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी।" अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक़ खुफिया रिपोर्टों ने पाकिस्तान की बढ़ी हुई सतर्कता और सीमा पर अपनी वायु सेना और सेना को तैनात करने की पुष्टि की, तो मोदी सरकार के कई मंत्रियों ने टिप्पणी कीः "यह डर दुश्मनों में रहना चाहिए। ''

बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर इसी समय पहलगाम हमले को अंजाम क्यों दिया गया, जिसे पुलवामा के बाद दूसरा सबसे बड़ा आतंकी हमला बताया जा रहा है? इसके कई कारण हैं। एक तो मुंबई हमले के षड्यंत्रकारी तहव्वुर राणा को भारत लाये जाने के बाद से पाकिस्तान की हवाइयां उड़ी हुई हैं कि पता नहीं, वह इस्लामाबाद के कौन-से रहस्य पर से पर्दा उठा दे। राणा को भारत लाये जाने के बाद इस्लामाबाद ने खुद-ब-खुद यह कहा कि राणा का पाकिस्तान से कोई लेना-देना नहीं है। और राणा ने भी कई दशक से अपने पाकिस्तानी दस्तावेजों का नवीकरण नहीं कराया है, जबकि इस्लामाबाद से किसी ने सफाई नहीं मांगी थी। जाहिर है पाकिस्तान जानता है कि भारत बड़ी कार्रवाई कर सकता है इसलिए वह पहले से ही अपनी सफाई भी दे रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान चाहे जो भी सफाई दे उसे सबक सिखाने की जरूरत है। इस जरुरत को अंजाम देने के लिए देश के सभी राजनीतिक पार्टियों को एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ हल्लाबोल करने की जरूरत है। एक ऐसा हल्लाबोल जो पाकिस्तान के तमाम आतंकी खेल को ही ख़त्म कर दे। और बड़ी बात यह भी है कि भारत को भी अपने ख़ुफ़िया तंत्र को और भी मजबूत करने की जरुरत है। पहलगाम की घटना से हमारे ख़ुफ़िया तंत्र की भी कलई खुल गई है।

भारत-पाकिस्तान में बढ़ा रार

पाकिस्तान ने कहा सिंधु जल संधि निलंबन 'युद्ध की कार्रवाई' जैसा

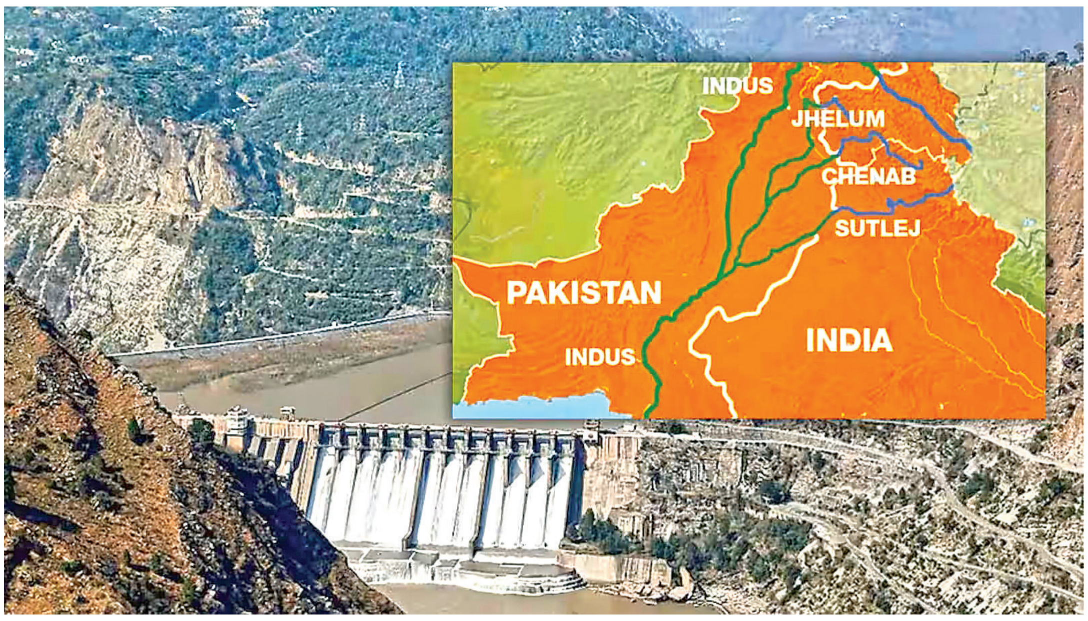

न्यूज़ डेस्क

पाकिस्तान ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए घातक आतंकवादी हमले के प्रतिशोध के रूप में 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित करने के भारत के फैसले को "पुरजोर तरीके से खारिज" किया। भारत की इस कार्रवाई पर देश की प्रतिक्रिया तैयार करने के लिए प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद, पाकिस्तान ने कहा कि सिंधु जल संधि के निलंबन से "240 मिलियन पाकिस्तानियों की जीवन रेखा" अवरुद्ध हो जाएगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा, "पाकिस्तान की संप्रभुता और उसके लोगों की सुरक्षा के लिए किसी भी खतरे का सभी क्षेत्रों में दृढ़ पारस्परिक उपायों से सामना किया जाएगा। भारत को अपने संकीर्ण राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए पहलगाम जैसी घटनाओं का अपने प्रतिशोधी दोषारोपण और सनकी ढंग से वंचित, प्रबंधित शोषण से बचना चाहिए।" बयान में कहा गया है, "सिंधु जल संधि के अनुसार पाकिस्तान के पानी के प्रवाह को रोकने या मोड़ने और निचले तटवर्ती लोगों के अधिकारों के हनन के किसी भी प्रयास को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा और राष्ट्रीय शक्ति के पूरे स्पेक्ट्रम में पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा।"

एक अन्य महत्वपूर्ण घोषणा में, पाकिस्तान ने कहा कि वह "भारत के साथ सभी द्विपक्षीय समझौतों को स्थगित रखने के अधिकार का प्रयोग करेगा, जिसमें शिमला समझौता भी शामिल है, लेकिन तब तक सीमित नहीं रहेगा जब तक कि भारत पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा देने, अंतरराष्ट्रीय हत्याओं और कश्मीर पर अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का पालन न करने के अपने स्पष्ट व्यवहार से बाज नहीं आता।" इस्लामाबाद ने भारतीय एयरलाइनों के लिए हवाई क्षेत्र को अवरुद्ध कर दिया और वाघा सीमा क्रॉसिंग को बंद कर दिया, जो एक दिन पहले भारत द्वारा उठाए गए कदमों के जवाब में था। इसने भारत के साथ 'सभी व्यापार' मार्गों को भी निलंबित कर दिया, जिसमें तीसरे देशों के माध्यम से आने वाले मार्ग भी शामिल हैं। पाकिस्तान ने कहा है की "पाकिस्तान वाघा सीमा चौकी को तत्काल प्रभाव से बंद कर देगा। इस मार्ग से भारत से सभी सीमा पार पारगमन को बिना किसी अपवाद के निलंबित कर दिया जाएगा। जो लोग वैध अनुमोदन के साथ सीमा पार कर चुके हैं, वे तुरंत उस मार्ग से वापस आ सकते हैं, लेकिन 30 अप्रैल 2025 से पहले नहीं।" इधर पीएमओ ने कहा, "एसवीईएस के तहत वर्तमान में पाकिस्तान में मौजूद भारतीय नागरिकों को 48 घंटे के भीतर बाहर निकलने का निर्देश दिया गया है, सिख तीर्थयात्रियों को छोड़कर।" इस बीच, भारत ने गुरुवार को 27 अप्रैल से तत्काल प्रभाव से पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को निलंबित करने की घोषणा की है।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी मौजूदा वैध वीजा 27 अप्रैल से रद्द कर दिए गए हैं। इसने कहा कि पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए मेडिकल वीजा केवल 29 अप्रैल तक वैध होंगे।मंत्रालय ने कहा कि वर्तमान में भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी नागरिकों को अपने वीजा की अवधि समाप्त होने से पहले देश छोड़ देना चाहिए।उसने भारतीय नागरिकों को पाकिस्तान की यात्रा करने से बचने की भी सख्त सलाह दी और वर्तमान में पड़ोसी देश में रहने वालों को जल्द से जल्द घर लौटने की सलाह दी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बुधवार को कहा, "इस आतंकवादी हमले की गंभीरता को समझते हुए सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने निम्नलिखित उपायों पर निर्णय लिया है। 1960 की सिंधु जल संधि तत्काल प्रभाव से स्थगित रहेगी, जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को त्याग नहीं देता।" प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ दंडात्मक उपायों पर भी निर्णय लिया गया है ।

पूर्व पीएम मनमोहन सिंह से सवाल पूछने वाले पीएम मोदी सवालों के घेरे में

राजनीतिक डेस्क

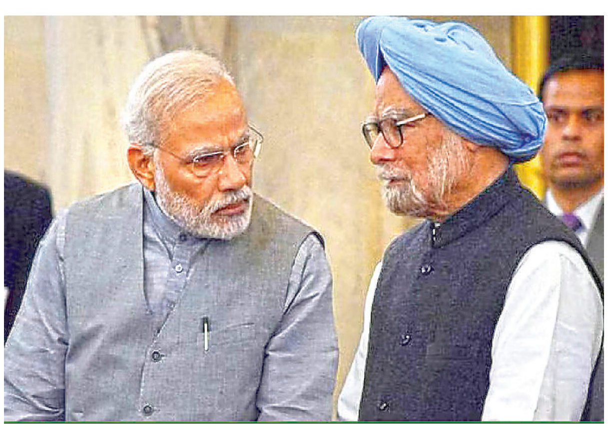

मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि इन आतंकियों को और इस हमले की साजिश करने वालों को उनकी कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर रहेगी। अब आतंकियों की बची-खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छाशक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़कर रहेगी।' बिहार के मधुबनी की एक सभा को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ये बातें कहीं हैं। निश्चित रूप से देश के मूड को देखते हुए भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है क्योंकि सभी विपक्षी पार्टियां भी इस मुद्दे पर सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलकर खड़ी है। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि जो मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले जो बड़ी -बड़ी बातें आतंकवाद के खिलाफ कर रहे थे और इसके लिए मनमोहन सिंह की सरकार को घेर रहे थे ,आज उसी आतंकवाद ने उनकी सरकार को भी घेरे में ला खड़ा किया है।

गुजरात के सीएम रहते हुए आतंकवाद को लेकर मोदी जी जो कहते रहे उसका वीडियो आज खूब वायरल हो रहा है। उस वीडियो में मोदी कह रहे हैं कि ''मैंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कई सवाल किये लेकिन किसी का जवाब नहीं मिलते। मोदी ने कहा कि ये जो आतंकवादी और नक्सलवादी है उनके पास शस्त्र और बारूद कहाँ से आते हैं ?वे सब तो विदेशी धरती से ही आते हैं। जब देश की सभी सीमाएं सरकार के कब्जे में हैं और सीमा सुरक्षा बल भी आपके कब्जे में ही है तब ये सब कैसे हो रहा है ? ''मैंने मनमोहन सिंह से पूछा कि आतंकियों के पास धन कहाँ से आते हैं ?मनी ट्रांसफर कहाँ से आते हैं ?जब आरबीआई से लेकर सभी बैंक सरकार के कब्जे में हैं फंडिंग की जांच क्यों नहीं होती ?क्या प्रधानमंत्री इतनी निगरानी भी नहीं रख सकते? '' ''मैंने तीसरा सवाल यह भी पूछा कि विदेशों से जो घुसपैठ हो रहे हैं और वे आतंकी घटना करके भाग जाते हैं यह सब कैसे संभव है ? जब सारी एजेंसियां आपके हाथ में हैं ,सभी सेनाएं आपके हाथ में हैं फिर घुसपैठिये आकर भाग कैसे जाते हैं ?''

''मैंने प्रधानमंत्री से यह भी पूछा कि जब देश के सारे कम्युनिकेशन आपके हाथ में हैं तब कोई विदेशी आतंकी कैसे कोई संचार प्रणाली का उपयोग करता है और आप उस पर निगरानी भी नहीं रख सकते ? फिर विदेश में जो आतंकी बैठे हैं उसे प्रत्यर्पण कानून के जरिये यहाँ लाकर आप दंडित क्यों नहीं करते ? ये पांच सवाल ऐसे हैं जिसपर प्रधानमंत्री अमल करें तो आतंकवाद जड़ से ख़त्म हो जाएगा। ' अब देश की जनता मोदी से भी यही सवाल कर रही है। जनता भी पूछ रही है कि आप 11 सालों से सत्ता चला रहे हैं और आतंकवाद ख़त्म क्यों नहीं हो रहा हैं ? जाली करेंसी क्यों छप रही है ? देश के कई भागों में घुसपैठ क्यों हो रहे हैं। कश्मीर में लगातार हमले क्यों हो रहे हैं ? विदेश भागे आतंकी और भगोड़े को आप क्यों नहीं वापस ला रहे हैं ? इसके अलावा रुपये की कीमत डॉलर की तुलना में क्यों गिरती जा रही है ? हमारे सभी पडोसी देश हमसे दूर क्यों होते जा रहे हैं। महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है ? देश के भीतर अंधभक्ति का क्यों माहौल है और हिन्दू -मुसलमान की राजनीति क्यों जारी है? और ऐसे बहुत से सवाल और भी हैं। खैर , पहलगाम हमले के बाद देश के आक्रोश को देखते हुए सरकार की तरफ से बहुत कुछ कहे जा रहे हैं। गुरूवार शाम को सर्वदलीय बैठक भी हुई है जिसमे कई तरह के फैसले लिए गए हैं। लेकिन सर्वसम्मति यही बनी है कि चूँकि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया है इसलिए उसे कड़ी सजा देने की जरुरत है ताकि भविष्य में वह भारत के साथ ऐसा खेल नहीं कर सके।

सूत्रों के मुताबिक राजनाथ के साथ सीडीएस व तीनों रक्षा सेवाओं के प्रमुखों की बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ उठाए जा सकने वाले सैन्य कदमों पर चर्चा हुई है । बाद में राजनाथ ने इन कदमों की जानकारी सीसीएस बैठक में पीएम मोदी व अन्य मंत्रियों के साथ साझा की है । राजनयिक कदमों के अलावा पाकिस्तान को जल्द ही किसी सैन्य कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। इसी बीच गुरुवार को कांग्रेस कार्यसमिति की भी बैठक हुई है जिसमे कई तरह के प्रस्ताव भी पारित किये गए । कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, 'कांग्रेस कार्यसमिति 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भयावह आतंकी हमले पर गहरा शोक और कड़ी निंदा व्यक्त करती है। इस जघन्य हमले में 26 निर्दोष पर्यटक मारे गए और 20 से अधिक गंभीर रूप से घायल हो गए। कांग्रेस कार्यसमिति शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करती है और इस गहन पीड़ा की घड़ी में उनके साथ पूरी तरीके से एकजुटता के साथ खड़ी है। यह कायराना और सुनियोजित आतंकी हमला जिसकी साजिश पाकिस्तान के द्वारा रची गई, हमारे गणराज्य के मूल्यों पर सीधा हमला है। हिंदू नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाना, पूरे देश में भावनाएं भड़काने की एक सोची समझी साजिश थी। हम इस गंभीर उकसावे के बावजूद शांति बनाए रखने की अपील करते हैं और संकट की इस घड़ी में हमारी सामूहिक शक्ति को दोहराते हैं।'

भारत की कड़ी कार्रवाई की सम्भावना को देखते हुए पाकिस्तान में डर का माहौल है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक बुलाई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तान की सेना ने युद्धाभ्यास भी शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने एक बार फिर गीदड़भभकी दिखाते हुए पाकिस्तान के पास एटमी बम होने की बात कही है।

उपराष्ट्रपति ने फिर की सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी, कहा 'संसद ही सर्वोच्च'

राजनीतिक डेस्क

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर दोहराया है कि संसद ही सुप्रीम होगा, क्योंकि संसद में चुनकर आए जन प्रतिनिधी ही संविधान तय करेंगे और संविधान के बारे में किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि संवैधानिक प्राधिकारी द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द सर्वोच्च राष्ट्रहित से प्रेरित होता है। उन्होंने हाल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर की गई अपनी टिप्पणी पर सवाल उठाने वाले आलोचकों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश के खिलाफ काम करने वाली ताकतों द्वारा संस्थाओं की आलोचना करने तथा उन्हें बर्बाद करने के प्रयासों को खत्म किया जाना चाहिए। जगदीप धनखड़ दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा कि, ''संविधान में संसद से ऊपर किसी प्राधिकार की कल्पना नहीं की गई है। संसद सर्वोच्च है... मैं आपको बता दूं कि यह उतना ही सर्वोच्च है जितना कि देश का प्रत्येक व्यक्ति।''

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने हाल में राज्यपालों द्वारा रोक कर रखे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति की मंजूरी के वास्ते उन पर फैसला लेने के लिए तीन महीने की समयसीमा तय की थी। कोर्ट के इस निर्देश पर धनखड़ ने कहा था कि न्यायपालिका ''सुपर संसद'' की भूमिका नहीं निभा सकती और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में नहीं आ सकती। उपराष्ट्रपति के इस बयान के बाद देश में एक बहस छिड़ गई कि मौजूदा दौर में आखिर यह ससब क्या हो रहा है ? आखिर देश की संवैधानिक संस्थाएं आपस में क्यों लड़ रही है ? दिल्ली विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में अपने भाषण में उन्होंने कहा कि संवैधानिक पदाधिकारी द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द राष्ट्र के सर्वोच्च हित से प्रेरित होता है। उन्होंने कहा, ''मुझे यह बात समझ में आती है कि कुछ लोगों ने हाल में यह विचार व्यक्त किया है कि संवैधानिक पद औपचारिक और रस्मी हो सकते हैं। इस देश में हर किसी की भूमिका - चाहे वह संवैधानिक पदाधिकारी हो या नागरिक - के बारे में गलत समझ से बढ़कर कोई भूल नहीं हो सकती।''

उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक की अपनी भूमिका होती है। उन्होंने कहा, ''लोकतंत्र की आत्मा प्रत्येक नागरिक में बसती है और धड़कती है। लोकतंत्र फूलेगा-फलेगा। इसके मूल्य और ऊंचे उठेंगे। जब नागरिक सतर्क होगा तो नागरिक योगदान देगा और नागरिक जो योगदान देता है, उसका कोई विकल्प नहीं हो सकता।'' धनखड़ ने यह भी कहा कि संविधान में संसद से ऊपर किसी भी प्राधिकार की कल्पना नहीं की गई है। उन्होंने जोर देकर कहा, ''संसद सर्वोच्च है।'' बता दें कि धनखड़ राज्यसभा के सभापति भी हैं। उन्होंने रेखांकित किया, '''हम लोग' का हिस्सा लोकतंत्र में एक अणु हैं और उस अणु में परमाणु शक्ति है। वह परमाणु शक्ति चुनाव के दौरान परिलक्षित होती है और इसीलिए हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं।'' राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा निर्धारित करने वाले हाल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चिंता व्यक्त करते हुए धनखड़ ने पिछले शुक्रवार को कहा था कि भारत ने ऐसे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की थी जहां न्यायाधीश कानून बनाएंगे, शासकीय कार्य करेंगे और ''सुपर संसद'' के रूप में कार्य करेंगे। इस महीने की शुरुआत में उच्चतम न्यायालय ने पहली बार यह तय किया था कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए रोक कर रखे गए विधेयकों पर उन्हें संदर्भ प्राप्त होने की तिथि से तीन महीने के भीतर निर्णय लेना होगा।

धनखड़ ने कहा, ''हाल में एक फैसले में राष्ट्रपति को निर्देश दिया गया है... हमने इस दिन के लिए लोकतंत्र की कभी कल्पना नहीं की थी। राष्ट्रपति को समयबद्ध तरीके से निर्णय लेने के लिए कहा गया है और अगर ऐसा नहीं होता है, तो यह (विधेयक) कानून बन जाएगा।'' राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लेने की समयसीमा निर्धारित किए जाने पर न्यायपालिका से सवाल उठाने के लिए उपराष्ट्रपति की आलोचना की गई। आलोचकों ने कहा कि यह ''असंवैधानिक'' है। धनखड़ की ''सुपर संसद'' संबंधी टिप्पणी पर परोक्ष रूप से प्रतिक्रिया देते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने कहा कि ''हम पर संसदीय और शासकीय कार्यों का अतिक्रमण करने का आरोप लगाया गया है।'' पीठ की अध्यक्षता न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने की। पीठ में न्यायमूर्ति बी. आर. गवई भी शामिल थे। पीठ ने एक अन्य मामले में भी इसी तरह की टिप्पणी की। एक मामला पश्चिम बंगाल में वक्फ (संशोधन) कानून के विरोध में हाल में हुई हिंसा से संबंधित था, जबकि दूसरी याचिका में केंद्र को ओटीटी और सोशल मीडिया मंच पर यौन रूझान वाली और अश्लील सामग्री की 'स्ट्रीमिंग' पर रोक लगाने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। ऑनलाइन सामग्री संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति गवई ने कहा, ''इसे कौन नियंत्रित कर सकता है? इस संबंध में विनियमन तैयार करना केंद्र (सरकार) का काम है।'' गवई अगले प्रधान न्यायाधीश बनने वाले हैं। इसी क्रम में राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने बीते मंगलवार को कहा कि शीर्ष अदालत ने जो कुछ भी कहा वह देश के संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप है और राष्ट्रीय हित से प्रेरित है। सिब्बल की यह टिप्पणी धनखड़ के इस बयान के तुरंत बाद आई है कि एक संवैधानिक पदाधिकारी द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द सर्वोच्च राष्ट्रीय हित से निर्देशित होता है।

आंकड़ों के आईने में बीजेपी सरकार का सच

न्यूज़ डेस्क

दलित उत्पीड़न से जुड़े ये कुछ आंकड़े हैं जिसे देखने के बाद यह तो पता चलता ही है कि भले ही देश की चुनावी राजनीति में दलितों को लेकर बहुत सी बातें कही जाती है और लगभग हर पार्टियां दलितों को अपने पास लाने के लिए बड़े -बड़े ऐलान भी करती हैं लेकिन आजादी के 76 साल बाद भी दलितों की हालत में कोई बड़ा सुधार नहीं आता। उन्हें हर दिन हत्पीडन का शिकार होना पड़ता है और उन्हें आज भी दोयम दर्जे का नागरिक ही माना जाता है। बड़ी बात तो यह है कि दलित उत्पीड़न के मामले में सबसे ज्यादा शिकार दलित महिलायें और बेटियां होती है।

ये कुछ हालियां आंकड़े हैं जो कई राज्यों से जुड़े हुए हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि उत्तरप्रदेश में 15368 दलित उत्पीड़न के मामले हाल के महीनो में दर्ज हुए हैं। इस उत्पीड़न में कुछ ऐसी दलित महिलाओं से जुड़े मामले भी हैं जिन्हे जानकार देश स्तब्ध रहा गया। राजस्थान में दलित उत्पीड़न के 8752 मामले दर्ज हुए हैं जबकि मध्यप्रदेश में 7733 मामले दलित उत्पीड़न के सामने आये हैं। बिहार भी दलित उत्पीड़न के मामले में पीछे नहीं है। वहां भी 6509 मामले दर्ज हुए हैं। इसी तरह ओडिशा में 2909 और महाराष्ट्र में 2743 मामले हाल के दिनों में सामने आये हैं। इसमें अहम बात यही है कि ये सभी राज्य बीजेपी शाषित हैं और जहाँ बीजेपी का सीधा शासन नहीं है वहां वह गठबंधन के जरिये सरकार चला रही है। जैसे कि बिहार राज्य। बिहार में बीजेपी लम्बे समय से जदयू के साथ गठबंधन में सरकार चला रही है अजर वह यह नहीं कह सकती कि बिहार में जो हो रहा है उससे उसे कोई मतलब नहीं है। और बड़ी बात तो यह भी है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह को भी यह सब पता है क्योंकि अपराध से जुड़े हर मामलों की वे समीक्षा भी करते रहते हैं। ऐसे में वह भी इन आंकड़ों को झुठला नहीं सकते।

इन आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि दलित उत्पीड़न के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे हैं। ये आंकड़े उस प्रदेश के हैं जहाँ योगी आदित्यनाथ की सरकार कहल रही है और वे हमेशा यही कहते हैं कि उनके राज में सब कुछ सही है ,अमन चैन है अजर सूबे के लोग सुरक्षित भी हैं। अगर योगी के बयान को सही भी मान लिया जाए तो जो आंकड़े सामने हैं क्या वे गलत हैं ? और गलत नहीं है तो उनके बयानों के क्या मायने हैं ? इधर सपा प्रमुख आखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरते हुए योगी सरकार पर बड़ा हमला किया है और कहा है कि उत्तर प्रदेश न सिर्फ दलित उत्पीड़न के मामले में सबसे आगे है बल्कि जातीय आधार पर भी पीडीए के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। यादव ने एक उदहारण देते हुए कहा कि "आगरा में कुल पोस्टिंग हैं 48, पीडीए 15 बाकी सब सिंह भाई। मैनपुरी में 15 पोस्टिंग हैं, पीडीए तीन, सिंह भाई 10 हैं। प्रयागराज का भी इसी तरह का आंकड़ा होगा।" उन्होंने कहा कि दो चीजें हम लोगों को पता हैं, एक तो डीजीपी कार्यवाहक होगा, दूसरा सिंह होगा। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने अपने हालिया सोशल मीडिया पोस्ट में भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने चुनावी धांधलियों और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए लंबी फेहरिस्त पेश की है। अखिलेश ने भाजपा पर अनैतिकता का आरोप भी लगाया और कहा कि इस पार्टी में आंतरिक गुटबाजी और सत्ता के दुरुपयोग जैसी चीजें भी आम हैं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट में लिखा, "जिसको उसी के तथाकथित अपने दल ने ये कहकर खारिज कर दिया हो कि उसका विचार व्यक्तिगत है और इस लायक नहीं कि उसकी पुष्टि या समर्थन किया जाए, वो एक सेवानिवृत्त संवैधानिक पद को सफलतापूर्वक सुशोभित कर चुके उच्चाधिकारी के बारे में मुंह न खोले, उसी में उसकी इज्जत है।"

अखिलेश ने पोस्ट में आगे एक लंबी लिस्ट शेयर करते हुए कहा- कुछ भी कहने-लिखने से पहले भाजपाई अपनी निम्नलिखित चंद चुनावी वारदातों पर निगाह डाल लें-2022 के यूपी विधानसभा में वोटर लिस्ट के द्वारा धांधली और लगभग 90 सीटों के परिणामों पर घपला।चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के सीसीटीवी के सामने वोट की धांधली की वीडियो रिकॉर्डिंग और बाद में सुप्रीम कोर्ट की डांट।2024 के लोकसभा चुनावों में कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मदद से झूठी गिनती के आधार पर कई सीटों पर सर्टिफिकेट में हेराफेरी के 'फर्रुखाबाद कांड' जैसे अनेक गैरकानूनी इलेक्शन रिजल्ट हेराफेरी कांड। अखिलेश यादव आगे लिखा उत्तर प्रदेश के मीरापुर उपचुनाव में कुछ भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की मदद से वोटरों को पिस्तौल से धमकाकर वोट न डालने देने की घटना और उसकी विश्वविख्यात तस्वीर।लोकसभा चुनाव में मप्र में भाजपा प्रत्याशी के विरुद्ध खड़े हुए प्रत्याशियों को उठाकर ले जाने और चुनावी पर्चे वापस करवाने की घटना और तथाकथित निर्विरोध चुनाव जीतने का लोकतांत्रिक पाप।महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक बड़े भाजपाई नेता के नोट बांटते पकड़े जाने की घटना।हरियाणा व महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अचानक वोटरों की संख्या या आखिरी घंटे में कई प्रतिशत वोट बढ़ जाने की घटना। सपा नेता ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर उपचुनाव में किसी 'मुख्य कार्यालय' से चुनावी तंत्र को झूठे वोट डलवाने का टारगेट देने का अपराध और झूठे वोटरों का इस्तेमाल, एक मतदाता द्वारा भाजपा के पक्ष में 6 वोट डालने का टीवी पर खुद स्वीकार किया जाना।

महाराष्ट्र चुनाव में एक पुलिस अधिकारी को 10 लाख रुपए देकर ईवीएम की धांधली को नजरअंदाज करने का दबाव बनाना और न जाने ऐसी कितनी और चुनावी धांधलियाँ हैं, जो भाजपा के चुनावी दामन के कभी भी न धुलने वाले दाग हैं। अखिलेश ने आगे लिखा, "भाजपाइयों की नैतिक स्मृति न तो कभी थी और न ही होगी फिर भी याद दिलाना तो बनता ही है। 'साइड-लाइन' किए जा रहे लोग अपने विवादित बयानों से 'मेन-लाइन' में आने की कोशिश न करें। भाजपावाले किसी के क्या, खुद के भी सगे नहीं हैं। अब ये सोशल मीडिया पर एक-दूसरे पर छींटाकशी कर रहे हैं। भाजपा की अंदरूनी गुटबाजी चरम पर है। भाजपा की 'भ्रष्टाचार-मंडली' की सर-फुटव्वल आपस में ही एक-दूसरे के राज खोल रही है। भाजपा का मुखौटा उतर गया है और उनका अहंकार जनता उतार देगी। इतिहास गवाह रहा है कि नकारात्मक सत्ताओं के विकास में ही उनका पतन निहित होता है।" वहीं, एक अन्य पोस्ट में अखिलेश यादव ने भाजपा शासित राज्यों में दलितों, खासकर दलित महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों को लेकर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियां और संगठनात्मक ढांचा गरीब, वंचित, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और महिलाओं के लिए अपमानजनक है।

अखिलेश ने लिखा, "दलितों पर अत्याचार के मामले में भाजपा सरकार के समय में यूपी नंबर वन बन गया है। सवाल ये है कि दलितों पर हमलों और दलितों के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराधों में, वो भी खासतौर से दलित महिलाओं के उत्पीड़न और दुर्व्यवहार की वारदातों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र जैसे वो ही राज्य क्यों हैं, जो भाजपा शासित हैं। भाजपा मूलतः परंपरागत प्रभुत्ववादियों की पार्टी है और वर्चस्ववादी भाजपाइयों की बुनियादी सोच सामंतवादी है, जिसमें गरीब, वंचित, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, आधी आबादी (महिलाओं) और आदिवासियों के लिए सिर्फ अपमान और जलालत के अलावा और कुछ नहीं है। मन, मानस और आचरण में भाजपाई आजादी से पहले की ही सोच में जी रहे हैं। इसलिए भाजपाई संविधान के भी विरोधी हैं क्योंकि भाजपा में संगठन और सरकार के प्रमुख पदों पर हमेशा ही केवल कुछ खास लोग ही विराजमान रहते हैं और बाकी दौड़-भाग, डंडा-झंडा, बैनर-दरी के काम औरों को दे दिए जाते हैं। उन्होंने आगे लिखा कि भाजपा के अंदर पदनाम भले किसी दलित, पिछड़े को मिल जाए पर 'पदमान' कभी नहीं मिलता। उनके नाम से चुनाव लड़े जाते हैं लेकिन मुख्यमंत्री की तो छोड़ो, उन्हें और भी कोई कुर्सी नहीं दी जाती है। अगर सच में कोई अपने ज़मीर की आवाज़ सुने तो वो ऐसे लोगों के हाथ न तो उत्पीड़ित हो और न ही अपमानित, ये बात अलग है कि वो अपने स्वार्थ और लालच की वजह से समझौता कर रहा है। संभव है कि अखिलेश यादव के ये सभी पोस्ट आगामी चुनाव को देखते हुए बीजेपी को ग्रिल करने को लेकर हो लेकिन एक बात तो तय है कि बीजेपी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उसे सच्चाई के नजदीक भी हैं। बीजेपी इस पर कोई सफाई नहीं देती। शायद सत्ता का खेल ऐसे ही चलता है।

न्यू देहली पोस्ट

क्या अनुराग का गुस्से में ऐसा बोलना ठीक था?

न्यूज़ डेस्क

प्रियंका चतुर्वेदी और मनोज मुंतशिर जैसे लोग मानते हैं कि अनुराग का गुस्सा, भले ही उकसावे से आया हो, पूरे समुदाय को निशाना बनाने को जायज़ नहीं ठहराता। "गुस्से में मर्यादा भूल गया" को कमज़ोर बहाना माना जा रहा है, क्योंकि इससे जातीय संवेदनशीलता भड़की। कुछ लोग मानते हैं कि अनुराग की प्रतिक्रिया इंसानी थी और ट्रोल्स द्वारा उकसाई गई। उनका इरादा पाखंड की आलोचना करना था, न कि भावनाएँ आहत करना, लेकिन शब्दों का चयन गलत था। सोशल मीडिया पर ज्यादातर लोग अनुराग की निंदा कर रहे हैं। अनमोल शुक्ला जैसे यूजर्स उनकी टिप्पणी को "ज़हरीला" मानते हैं और कहते हैं कि उन्होंने भारतीय संस्कृति में योगदान देने वाले समुदाय का अपमान किया। कुछ लोग इसे चुनिंदा आक्रोश मानते हैं, जब अन्य लोग ऐसी टिप्पणियाँ करते हैं तो चुप्पी रहती है।

क्या अनुराग ने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया?

पायल घोष और गेहना वशिष्ठ का आरोप है कि अनुराग ने अपनी फिल्म फुले के लिए ध्यान खींचने के लिए ब्राह्मणों को बदनाम किया। उनकी टिप्पणी का समय, जब फिल्म सर्टिफिकेशन के मुद्दों से जूझ रही थी, आलोचकों को लगता है कि यह प्रचार के लिए था। अनुराग के समर्थक, जैसे सेन बैजनाथ कहते हैं कि उनकी टिप्पणी ट्रोल्स के जवाब में थी, न कि सुनियोजित कदम। उनकी माफी, जिसमें उन्होंने अपनी बात को मुद्दे से भटकाने की गलती मानी, इस दृष्टिकोण का समर्थन करती है। फिर भी, समर्थक मानते हैं कि उनकी भाषा भड़काऊ थी। लेकिन डॉ. शालिनी वर्मा कहती हैं, "अनुराग की विवादों में रहने की आदत है, लेकिन इस बार उन्होंने गलत अनुमान लगाया। भारत में जातीय भावनाओं के साथ खिलवाड़ आग से खेलने जैसा है।"

विवादों से पुराना नाता है अनुराग कश्यप का

मीटू आरोप (2020)- पायल घोष ने अनुराग पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, जिससे सार्वजनिक विवाद हुआ। अनुराग ने आरोपों को खारिज किया, लेकिन उनकी

छवि को नुकसान पहुँचा। तांडव विवाद (2021)- उनकी शेल्व्ड प्रोजेक्ट मैक्सिमम सिटी को तांडव विवाद से जोड़ा गया, जिसमें हिंदू भावनाओं को ठेस पहुँचाने का आरोप लगा था।

बॉलीवुड और राजनीति पर टिप्पणियाँ

अनुराग ने बॉलीवुड को "टॉक्सिक" कहा और द केरल स्टोरी को प्रोपेगैंडा करार देते हुए इसके बैन का विरोध किया। ये बयान हमेशा ध्रुवीकरण करते हैं। पहले जातीय विवादः 2020 में एक्स पर पोस्ट्स में अनुराग पर हिंदू-विरोधी टिप्पणियों का आरोप लगा, जैसे योगी आदित्यनाथ को "मिलिटेंट" और हिंदुओं को "आतंकवादी" कहना। ये दावे असत्यापित हैं, लेकिन उनकी उकसाने वाली छवि को दर्शाते हैं।

अनुराग की माफी पर प्रतिक्रियाएँ

अनुराग ने इंस्टाग्राम पर माफी माँगीः "मैं गुस्से में किसी को एक जवाब देने में अपनी मर्यादा भूल गया। और पूरे ब्राह्मण समाज को बुरा बोल डाला मैं तहे दिल से माफी मांगता हूं अब आगे से ऐसा न हो, मैं अपने गुस्से पर काम करूंगा।" सकारात्मक प्रतिक्रियाः कुछ नेटिज़न्स ने उनकी ज़िम्मेदारी लेने की तारीफ की। एक इंस्टाग्राम यूजर ने लिखा, "ऐसी माफी माँगना आपका बड़प्पन है।" एक अन्य ने लिखा, "आत्मनिरीक्षण का साहस सराहनीय है।" अनमोल शुक्ला जैसे यूजर्स ने माफी को "डैमेज कंट्रोल" करार दिया, कहते हुए कि "नुकसान तो हो चुका।" अनिल चतुर्वेदी ने कहा, "यह माफी सिर्फ कानून से बचने की औपचारिकता है।"शिव बीएचयू ने एक्स पर लिखा, "अनुराग का इरादा ठीक था, लेकिन भाषा अनैतिक थी। ऐसी टिप्पणियाँ अगर सामान्य हो गईं, तो जातीय तनाव बढ़ेगा।"

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं

प्रियंका चतुर्वेदी, शिवसेना (यूबीटी) सांसदः "ब्राह्मण समाज को गाली देना अब कुछ लोगों के लिए फैशन बन गया है। अनुराग कश्यप के बेकार बयान से एक समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुँची है। बोलने की आज़ादी का मतलब अपमान करने की छूट नहीं।" सतीश चंद्र दुबे, केंद्रीय मंत्रीः "अनुराग कश्यप एक घटिया इंसान हैं, जो कला की आड़ में ज़हर उगलते हैं। ब्राह्मणों पर उनकी गंदी टिप्पणी भारतीय संस्कृति का अपमान है। उन्हें कानूनी सजा मिलनी चाहिए।" तेजस्वी यादव, राजद नेता (काल्पनिक, विपक्ष के रुख के आधार पर) : "अनुराग का बोलना गलत था, लेकिन ये गुस्सा चुनिंदा क्यों? जब कुछ लोग सांप्रदायिक ज़हर फैलाते हैं, तब ये आक्रोश कहाँ होता है?"

फिल्म इंडस्ट्री और सार्वजनिक हस्तियां

मनोज मुंतशिर, गीतकार : "अनुराग कश्यप, तुम्हारी आय और जानकारी दोनों सीमित हैं। अगर हिम्मत नहीं है अपने शब्दों को सही ठहराने की, तो जीभ पर लगाम दो। तुम जैसे नफरत फैलाने वालों का अंत ब्राह्मणों के गौरव से पहले हो जाएगा।" पायल घोष, अभिनेत्रीः "अनुराग कश्यप घृणित इंसान हैं। जिसने एक महिला पर जबरदस्ती की, उससे किसी समुदाय के सम्मान की उम्मीद कैसे की जाए? बॉलीवुड और समाज को उनका बहिष्कार करना चाहिए।" गेहना वशिष्ठ, अभिनेत्रीः "उनकी टिप्पणी सिर्फ आपत्तिजनक नहीं, बल्कि ब्राह्मणों को बदनाम करने की साजिश है। ऐसे आदतन अपराधी को रोकने के लिए कानूनी कार्रवाई ज़रूरी है।" अनाम फिल्म इंडस्ट्री हस्ती (काल्पनिक, इंडस्ट्री के मूड को दर्शाते हुए): "अनुराग हमेशा से उकसाने वाले रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने हद पार कर दी। पूरे समुदाय का अपमान करके माफी से बात खत्म नहीं होती।"

सोशल मीडिया और जनता की राय

अनमोल शुक्ला एक्स पर:लिखते हैं "अनुराग कश्यप की गंदी सोच अब सबके सामने है। एक समुदाय के खिलाफ उनका ज़हर खतरनाक है। अगर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, तो उनकी जहरीली विचारधारा समाज में फैलेगी।"जबकि श्री नीति कहते हैं "अनुराग का ब्राह्मणों पर टिप्पणी करना शर्मनाक है। वे समाज के प्रति गैर-जिम्मेदार हैं। गाली देना हक नहीं देता कि दूसरे भी उनके स्तर पर उतरें।" नीरज झा एक्स पर कहते हैं "अनुराग कोई नेता या सुधारक नहीं हैं। उनकी प्रतिक्रिया भद्दी थी, लेकिन उकसाने वालों की भी जिम्मेदारी है। समाज को हर बोलने वाले पर नैतिक दबाव नहीं डालना चाहिए।" अनाम इंस्टाग्राम यूजर (खबरों से): "उनकी माफी से लगता है कि अब डर गए हैं, लेकिन नुकसान हो चुका है। भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके 'सॉरी' बोलना कोई खेल नहीं है।"

विश्लेषकों की राय

डॉ. शालिनी वर्मा, समाजशास्त्रीः "अनुराग का गुस्सा आवेग में था, लेकिन पूरे समुदाय को निशाना बनाना गलत था। उन्होंने अपनी ही बात को कमज़ोर कर लिया। भावनाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ खतरनाक है।" अनिल चतुर्वेदी, जयपुर एफआईआर के शिकायतकर्ताः "कश्यप की टिप्पणी सिर्फ अपमानजनक नहीं, बल्कि ब्राह्मण गौरव पर सुनियोजित हमला थी। उनकी माफी केवल कानूनी कार्रवाई से बचने की औपचारिकता है।"रवि शंकर, राजनीतिक विश्लेषक (काल्पनिक, सामान्य रुख पर आधारित) : "अनुराग की टिप्पणी उनकी उकसाने की पुरानी आदत का हिस्सा है। लेकिन एक समुदाय को ठेस पहुँचाकर उन्होंने अपनी विश्वसनीयता को ही नुकसान पहुँचाया।"

चंद्रबाबू जल मिशन धन के बदले बीजेपी को देंगे राज्यसभा की सीट

राजनीतिक डेस्क

आंध्र प्रदेश के सीएम नायडू ने भाजपा को राज्यसभा सीट देने पर सहमति जताई है। आंध्र प्रदेश में राज्य सभा की एक सीट खाली है और बीजेपी की की चाहत रही है कि टीडीपी यह सीट बीजेपी को दे। विदेशी दौरे से लौटे चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को दिल्ली में चार केंद्रीय मंत्रियों से मिले और फिर उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई।

दिल्ली में नायडू ने सबसे पहले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल से मुलाकात की और जल जीवन मिशन के लिए केंद्रीय निधि के आवंटन पर चर्चा की। योजना को व्यापक रूप से लागू करने के राज्य के इरादे को व्यक्त करते हुए, मुख्यमंत्री ने समय पर धन जारी करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को प्रस्तावित पोलावरम-बनकाचरला लिंक परियोजना के बारे में भी जानकारी दी, जिसका उद्देश्य आंध्र प्रदेश को सूखा मुक्त बनाना है, और इस पहल के लिए समर्थन का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने परियोजना के लाभों और इसके महत्व को रेखांकित किया। माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रियों से सहमति मिलने के बाद नायडू और अमित शाह की मुलाकात हुई जिसमे राज्य सभा सीट को लेकर चर्चा की गई। भाजपा सूत्रों के अनुसार, अमित शाह ने राज्य से एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए भाजपा उम्मीदवार को मैदान में उतारने की इच्छा जताई है और नायडू ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई है। इस संबंध में आधिकारिक घोषणा इस सप्ताह के अंत तक होने की संभावना है।

टीडीपी द्वारा राज्यसभा में खाली होने वाली एक सीट को अपने सहयोगी दल भाजपा को देने के लिए राजी होने के बाद, तमिलनाडु में अटकलें लगाई जा रही हैं कि के अन्नामलाई, जिन्होंने हाल ही में तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, राज्यसभा से उस सीट पर चुने जा सकते हैं। हालांकि, अन्नामलाई के करीबी सूत्रों ने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है और फिलहाल यह ज्यादातर अफवाहें हैं। अटकलों पर, तमिलनाडु के भाजपा के राष्ट्रीय सह-प्रभारी पोंगुलेटी सुधाकर रेड्डी ने टीएनआईई से कहाः "अगर ऐसा होता है, तो यह अच्छा है। लेकिन पार्टी आलाकमान का निर्णय सर्वोच्च है क्योंकि इसमें कई कारक शामिल हैं।"

उधर , नाम न बताने की शर्त पर एक वरिष्ठ राष्ट्रीय स्तर के नेता ने कहा, अन्नामलाई का आंध्र प्रदेश से चुना जाना फिलहाल केवल अटकलें हैं, हालांकि यह निश्चित है कि उन्हें जल्द ही पार्टी संगठन या संसद में एक महत्वपूर्ण पद पर बैठाया जाएगा। उन्होंने कहा, "आंध्र प्रदेश में अलग-अलग राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए, कई संभावनाएं हैं। यहां तक कि उस राज्य से उच्च सदन के लिए एक मुस्लिम उम्मीदवार भी चुना जा सकता है।" बता दें कि 25 जनवरी को वाईएसआरसीपी के राज्यसभा सदस्य वी विजयसाई रेड्डी के इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हो गई थी और चुनाव आयोग ने उपचुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा की है। हालांकि विजयसाई रेड्डी का राज्यसभा कार्यकाल 21 जून, 2028 तक था, लेकिन उन्होंने सांसद पद छोड़ दिया और वाईएसआरसीपी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। कार्यक्रम के अनुसार, 29 अप्रैल नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। नामांकन की जांच 30 अप्रैल को होगी और 2 मई को उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख है।

यदि आवश्यक हुआ तो 9 मई को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। उसी दिन शाम 5 बजे मतों की गिनती की जाएगी। हालांकि, टीडीपी-जेएसपी-बीजेपी गठबंधन की ताकत को देखते हुए उपचुनाव सर्वसम्मति से होने की संभावना है, जिसके पास विधानसभा में कुल 175 में से 164 विधायक हैं।

राज -उद्धव के एकीकरण से कितनी बदलेगी महाराष्ट्र की राजनीति?

महाराष्ट्र में नयी राजनीति की आहट, उद्धव शिवसेना और मनसे का हो सकता है एकीकरण, दोनों दलों की मज़बूरी ,बीजेपी और शिंदे की बढ़ेंगी मुश्किलें

राजनीतिक डेस्क

मनसे नेता राज ठाकरे ने पॉडकास्ट पर एक बयान क्या दिया ,महाराष्ट्र की राजनीति अचानक गरमा गई। हलचल होने लगी। यह हलचल कब जाकर शांत होगी यह किसी को पता नहीं लेकिन जानकार अब कह रहे हैं कि भले ही राज ठाकरे की मनसे महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बड़ा काम नहीं किया हो लेकिन अगर दोनों भाई यानी उद्धव और राज एक हो जाते हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति फिर नयी धार के साथ आगे बढ़ेगी और फिर इस राजनीति में कई घायल भी होंगे और कई बाहर भी हो जाएंगे। लोगों का यह इशारा बीजेपी अजर शिंदे की तरफ है। जो बीजेपी बालासाहेब ठाकरे के समय शिवसेना के पीछे रहने में ही अपनी भलाई समझती थी अब वही बीजेपी महाराष्ट्र की बड़ी पार्टी बन गई है और जो शिंदे शिवसेना के भीतर एक आम नेता की हैशियत में थे ,सीएम भी बने ,पार्टी को तोड़ा भी और अब शिवसेना को हड़प कर सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं। ऐसे समय में राज और उद्धव के एकीकरण से मराठी मानुष को बड़ा सुकून तो मिल्गा ही।

19वीं सदी में जर्मन चांसलर ओटो वॉन बिस्मार्क ने लिखा था, "राजनीति संभव और प्राप्त करने योग्य की कला है - अगले सर्वश्रेष्ठ की कला।" पिछले कुछ वर्षों में, इसका मतलब "असंभव की कला" बन गया है। इसे महाराष्ट्र में दो अलग-अलग रह रहे ठाकरे चचेरे भाइयों- उद्धव और राज के संभावित साथ आने पर सबसे अच्छे ढंग से लागू किया जा सकता है। शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की विरासत को विरासत में पाने के लिए वे दो दशकों से अधिक समय से एक-दूसरे से भिड़ रहे हैं। इसलिए, जब राज ने बीते शनिवार को एक पॉडकास्ट के दौरान महाराष्ट्र के व्यापक हित के लिए अपने मतभेदों को अलग रखने की पेशकश की, तो यह एक धमाकेदार घटना की तरह था। उद्धव ने जवाब दिया कि वे राज के साथ काम कर सकते हैं, बशर्ते राज अपने 'संदिग्ध' दोस्तों को छोड़ दें।

दोनों के बीच तेजी से आगे-पीछे होना एक योजना के अनुसार नपे-तुले लग रहे थे। मेल-मिलाप के कदम तार्किक प्रतीत होते हैं। महाराष्ट्र की राजनीतिक चाल में दोनों क्षेत्रीय नेताओं को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। विलियम शेक्सपियर ने द टेम्पेस्ट में कहा था, "दुख आदमी को अजीब साथियों से मिलवाता है।" राज ठाकरे ने 2006 में शिवसेना छोड़ दी थी, जब उनके चाचा बाल ठाकरे ने अपने तेजतर्रार भतीजे की बजाय अपने बेटे, साधारण उद्धव को अपना उत्तराधिकारी बनाने का समर्थन किया था। राज को परिवार द्वारा संचालित पार्टी में कोई भविष्य नहीं दिखाई दिया और उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया। हालांकि, मनसे हमेशा से ही असफल रही। पिछले नवंबर के विधानसभा चुनावों में राज को एक भी सीट नहीं मिली और यहां तक कि उनके बेटे अमित भी हार गए।

उद्धव के लिए भी यह सफर का अंत है। शिवसेना, जो कभी भाजपा के साथ गठबंधन में वरिष्ठ भागीदार थी और जिसने तीन मुख्यमंत्रियों के साथ राज्य पर शासन किया था, आज सिमट कर रह गई है। अलग हुए एकनाथ शिंदे खेमे की सरकार है दूसरी ओर, कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से मूल शिवसेना के हिंदुत्व और 'भूमिपुत्रों' की विचारधारा कमजोर हो जाती है। अब, अवसर की एक खिड़की है। सरकार के भीतर, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच विरोधाभास हैं। बाहर, तीन-भाषा सूत्र और हिंदी के खिलाफ आवाज उठ रही हैं। 1966 के मूल बाल ठाकरे के 'मराठी अस्मिता' या आत्म-सम्मान के आह्वान को पुनर्जीवित करने से गति मिल सकती है। आने वाले मुंबई नगर निगम चुनाव एक नए क्षेत्रीय सत्ता खेल के लिए परीक्षण हो सकते हैं।

अब ऐसे में कई सारे सवाल खड़े हो रहें है कि आखिरकार लगभग 20 साल बाद ठाकरे बंधुओं को एक साथ आने कि जरूरत क्यों पड़ गई। क्या महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन के रिकॉर्ड प्रदर्शन से ठाकरे बंधुओं को अपनी बनी बनाई विरासत खोने का डर सताने लगा है, या फिर आगामी बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के चुनाव में दोनों भाई एक साथ चुनाव लड़कर भाजपा को करारा जवाब देने की ताक में है।

विधान सभा चुनाव में दोनों पार्टियों का प्रदर्शन ख़राब

बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना (यूबीटी) और मनसे का प्रदर्शन बेदह खराब रहा। फलस्वरूप महायुति गठबंधन की रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई, जिससे महाराष्ट्र में भाजपा ने अपना एक मजबूत पक्ष को दर्शाया। अब ऐसी स्थिति में ठाकरे बंधुओं के साथ आने का दो मुख्य कारण हो सकते है। पहला तो ये कि महाराष्ट्र में दिन-प्रतिदिन भाजपा लगातार रूप से मजबूत होती हुई जा रही है, जो कि एमवीए और ठाकरे परिवार के लिए सकारात्मक संकेत नहीं है। वहीं दूसरी ओर आगामी बीएमसी चुनावी रण में उद्धव गुट के शिवसेना के लिए अकेले ही भाजपा का विजयी रथ रोकना थोड़ा कठिन है। इस स्थिति में दोनों भाई साथ आकर चुनावी रण में भाजपा को रोकने का पूरी प्रयास कर सकते है।

गठबंधन या एकीकरण की जरूरत क्यों ?

राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, जो कभी एक-दूसरे के बहुत करीबी थे, अब दो दशकों बाद फिर से एक साथ आने के संकेत दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ कि अब इन्हें एक-दूसरे की जरूरत महसूस हो रही है? पहले तो ये बात साफ हो चुकी है कि राज ठाकरे की मनसे राजनीतिक रूप से कमजोर हो चुकी है। दूसरी बात ये है कि एकनाथ शिंदे का अलग होकर अलग शिवसेना बनाना उद्धव के लिए झटका हैं। तीसरी बात ये है कि बीते चुनावों में भाजपा और शिंदे की बढ़ती ताकत ठाकरे बंधुओं के लिए चिंता का विषय के रूप में सामने आई है। चौथी और सबसे मुख्य कारण आगामी बीएमसी चुनाव में भाजपा को मात देने की तैयारी है, जिसके लिए दोनों भाई अपनी आपसी दुश्मनी को खत्म करने के लिए तैयार हो सकते हैं।

कैसे साथ आ सकते हैं दोनों भाई?

महाराष्ट्र में भाजपा की मजबूत स्थिति और शिवसेना (यूबीटी) तथा मनसे की कमजोर स्थिति को देखते हुए, विपक्षी एकजुटता की जरूरत बन रही है। दोनों भाई मिलकर भाजपा के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन बना सकते हैं, जो उन्हें आगामी चुनावों में सत्ता वापसी में मदद कर सकता है। इसके अलावा, राकांपा और कांग्रेस जैसे पार्टियां भी इस गठबंधन में शामिल हो सकती हैं, जिससे वे विधानसभा और लोकसभा चुनावों में बीजेपी के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बना सकें।

हाल ही में अलग-अलग कार्यक्रमों में बोलते हुए दोनों नेताओं ने कहा कि मराठी भाषा और संस्कृति को बचाना आपसी राजनीतिक लड़ाई से ज्यादा जरूरी है। राज ठाकरे ने साफ कहा कि उनके और उद्धव के बीच जो भी मतभेद हैं, वे मामूली हैं और राज्य के हित में उन्हें भुलाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र चाहता है कि हम साथ आएं तो हम अहंकार को बीच में नहीं लाएंगे। उधर उद्धव ठाकरे ने पुनर्मिलन की संभावना पर कहा कि वह व्यक्तिगत विवाद भुलाने को तैयार हैं, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि हम रोज पाला नहीं बदल सकते। जो महाराष्ट्र के खिलाफ काम करेगा, उसे मैं स्वीकार नहीं करूंगा अब ऐसे में एक सवाल ये भी है कि राज और उद्धव ठाकरे के साथ आने की अटकलें राजनीतिक जरूरत और व्यक्तिगत मजबूरियों की वजह से तेज हो गई हैं। यह गठबंधन बीजेपी और शिंदे गुट के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा तैयार कर सकता है, और ठाकरे परिवार की राजनीतिक धरोहर को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। हालांकि अब देखना यह होगा कि ये अटकलें सच होती हैं या सिर्फ चुनावी रणनीति का हिस्सा हैं।

एकता में कौन होंगे सहयोगी ?

ठाकरे बंधु के साथ आने की अटकलों के बीच एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि अगर दोनों भाई साथ आते हैं तो इस गठबंधन को जोड़ने कौन-कौन से नेताओं की अहम भूमिका होगी। इस बात को ऐसे समझते है कि राज और उद्धव ठाकरे के संभावित गठबंधन में प्रमुख नेतृत्व वाले चेहरे उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, संजय राउत, आदित्य ठाकरे और राज के करीबी सहयोगी होंगे, जबकि कांग्रेस और राकांपा जैसे पार्टियों का समर्थन भी इसे और ताकतवर बना सकता है। यह गठबंधन दोनों पक्षों के लिए एक राजनीतिक मजबूरी बन सकता है, ताकि वे भाजपा और शिंदे गुट के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बना सकें।

आतंकियों से लड़ते -लड़ते शहीद हो गए जांबाज आदिल हुसैन

न्यूज़ डेस्क

पहलगाम हमले की कहानी बहुत कुछ कह रही है। इस हमले ने भारत को तो झकझोड़ ही दिया है ,दुनिया को भी बता दिया है कि पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है ? भारत इसका भरपूर जवाब देगा जो पाकिस्तानी को लम्बे समय तक याद भी रहेगा। लेकिन उसी पहलगाम में जब धर्म पूछकर पर्यटकों को आतंकी गोली मार रहा था तब वही का एक स्थानीय सच्चा राष्ट्रवादी मुस्लिम युवक आदिल हुसैन शाह जो पेशे से टट्टू चलकर अपने माता -पिता का भरण पोषण करता था ,आतंकियों से लड़ गया। वह बार -बार आतंकियों को पहले गोली चलाने से रोकता रहा और आतंकियों से गाली सुनता रहा। आतंकियों ने उसे मुस्लिम होने की बात कहते हुए हैट जाने को कहता रहा लेकिन आदिल हुसैन रुकने को तैयार नहीं था। वह बार -बार आतंकियों के घातक हथियार को पकड़ लेता था ताकि हिन्दू भाइयों की मौत का खेल रुक जाए।

वह कहता जा रहा था ये हिन्दू हमारे भाई हैं,हमारे लोग हैं ,हमारे अतिथि हैं और सबससे बड़ी बात कि ये

हमारे आय के स्त्रोत भी हैं। लेकिन आतंकी मानने को तैयार नहीं हुए। पहले एक धक्का मारा और फिर तीन गोलिया उसके सीने में दाग दी आतंकियों ने। आदिल हुसैन वही ढेर हो गया। अपने वतन पर आतंकियों से

लड़ते लड़ते कुर्वान हो गया। आज पूरा देश आदिल हुसैन पर गर्व कर रहा है ,उसे सलाम कर रहा है।

पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों में आदिल शाह इकलौते मुस्लिम थे। वह रोज की तरह ही बीते मंगलवार सुबह अपने घर से निकले थे। परिवार को मंगलवार शाम को आदिल की मौत के बारे में पता चला। जब बुधवार को आदिल का शव हापतनार गांव पहुंचा तो लोगों का हुजूम उमड़ा पड़ा। आदिल के परिवार में पत्नी, माता-पिता, दो भाई और तीन बहनें हैं। आदिल के पिता सैयद हैदर शाह (60) ने कहा कि वह घर का अकेला कमाने वाला सदस्य था। वह टट्टू वाले के तौर पर काम करने के लिए 30 किलोमीटर दूर बैसरन जाता था। वह हर दिन 600 से 1000 रुपये कमा लेता था।

शाह के छोटे भाई सैयद नौशाद शाह, जो बैसरन में हमले के समय पहलगाम में थे, ने कहा कि जब मैंने हमले के बारे में सुना तो मैंने अपने भाई को फोन करना शुरू किया। किसी ने जवाब नहीं दिया। शाम 5 बजे स्थानीय टट्टू वालों ने मुझे उसकी मौत के बारे में बताया।आदिल के साथ आई एक महिला पर्यटक ने बताया कि जब मेरे भाई ने पर्यटकों को मरते देखा, तो उसने आतंकवादियों से मुकाबला किया और आतंकवादियों ने उसे तीन बार गोली मारी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हम न केवल अपने भाई की मौत से बल्कि 25 निर्दोष पर्यटकों की मौत से भी दुखी हैं।

न्यू देहली पोस्ट

क्या निशिकांत दुबे पर चलेगा आपराधिक अवमानना का मामला?

राजनीतिक डेस्क

देश में जो भी गृह युद्ध हो रहा है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। अगर हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो संसद और विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, इसे बंद कर देना चाहिए। ये शब्द हैं झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के। ये वही दुबे हैं जिन्होंने संसद के भीतर बिना किसी प्रमाण के चिल्लाते रहते हैं जबकि खुद उनकी डिग्री के बारे में आज भी संदेह है और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने उनकी डिग्री की सच्चाई को संसद में एक्सपोज कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई के बारे में दुबे द्वारा की गई टिप्पणी से मुकर गई है। पार्टी अध्यक्ष जे पी नड्डा ने कहा है कि दुबे के बयान को बीजेपी स्वीकार नहीं करती। यह उनका व्यक्तिगत बयान है। लेकिन सवाल है कि आखिर बीजेपी ने दुबे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की ? क्या इसी तरह के बयान कोई और विपक्षी सांसद दिए होते तो क्या बीजेपी और दुबे स्थिर रहते ?सच तो यही है कि दुबे ने जो कहा आंतरिक तौर पर वह बीजेपी का ही बयान था। क्योंकि बीजेपी अब तक यही चाहती रही है कि उसकी और उसकी सरकार के फैसले को आखिर चुनौती कौन दे सकता है ?

इसके बाद, उत्तर प्रदेश से बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने भी सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी की। उन्होंने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट पर दिए गए बयान को लेकर कहा कि, "जब बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान बनाया था, तो उसमें उन्होंने विधायिका और न्यायपालिका के अधिकारों का स्पष्ट रूप से वर्णन किया है।" उन्होंने कहा कि, "भारत के संविधान के अनुसार, कोई भी लोकसभा और राज्यसभा को निर्देशित नहीं कर सकता है और राष्ट्रपति ने पहले ही इस पर अपनी सहमति दे दी है. कोई भी राष्ट्रपति को चुनौती नहीं दे सकता क्योंकि राष्ट्रपति सर्वोच्च हैं।" बीजेपी सांसदों के इन बयानों के बाद देश की राजनीति गर्म हो गई है और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप -प्रत्यारोप शुरू गए हैं। इस बीच देश के सीजेआई ने अभी तक कोई श्यापपणी नहीं की है लेकिन जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट बीजेपी सांसदों के इस बयान से मर्माहित तो हुआ ही है। इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस बी आर गवई ने न्यायपालिका को हाल में निशाना बनाए जाने का परोक्ष रूप से संकेत देते हुए कहा ''हम पर संसदीय और कार्यपालिका के कार्यों में अतिक्रमण

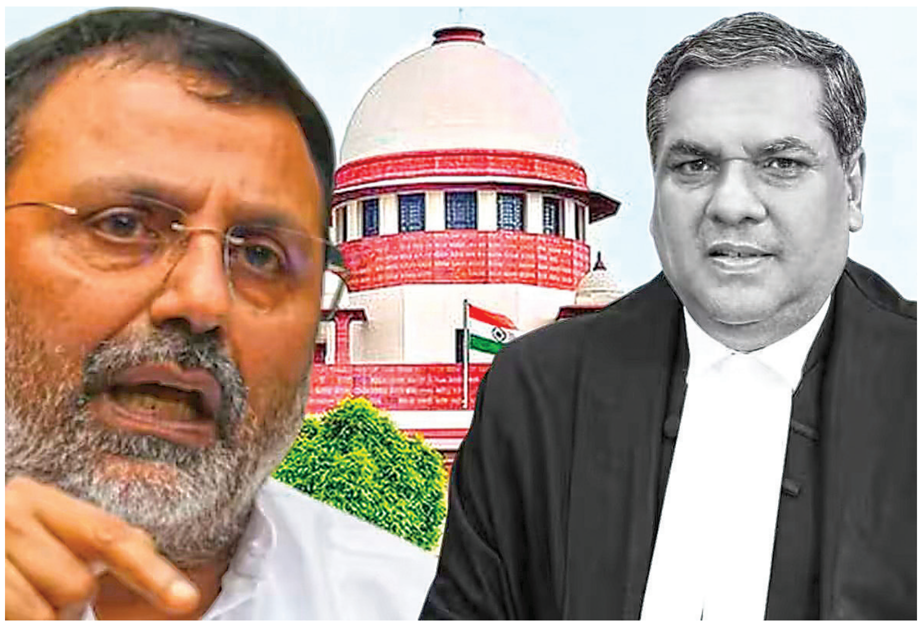

करने का आरोप'' लगाया जा रहा है। जस्टिस गवई ने यह टिप्पणी पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हाल में हुई हिंसा की जांच कराए जाने का अनुरोध करने वाली एक नई याचिका पर सुनवाई के दौरान की। इस पीठ में न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह भी शामिल हैं। यह भी बता दें कि वर्तमान सीजेआई खन्ना के बाद जस्टिस गवई ही अगले महीने सीजेआई बनने वाले हैं।

न्यायमूर्ति गवई ने एक अन्य मामले में भी इसी तरह की टिप्पणी की। दूसरा मामला उस याचिका से जुड़ा है जिसमें केंद्र को ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्लील सामग्री की स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति गवई ने कहा, ''इस पर कौन नियंत्रण कर सकता है? इस संबंध में नियम तैयार करना केंद्र का काम है।'' जस्टिस बी आर गवई ने मामले में पक्ष रख रहे अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन से कहा, ''हमारी आलोचना की जा रही है कि हम कार्यपालिका के कामकाज में, विधायिका के कामकाज में हस्तक्षेप कर रहे हैं।' जैन ने कहा, ''यह बहुत गंभीर मामला है''। इसके बाद पीठ ने सुनवाई अगले सप्ताह के लिए सूचीबद्ध कर दी।

ध्यान दिला दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने पिछले सप्ताह न्यायपालिका के खिलाफ निंदात्मक टिप्पणियां की थीं। धनखड़ ने राष्ट्रपति के फैसला करने की समयसीमा तय करने और ''सुपर संसद'' के रूप में काम को लेकर न्यायपालिका पर सवाल उठाते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट लोकतांत्रिक ताकतों पर ''परमाणु मिसाइल'' नहीं दाग सकता। इसके बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ही कानून बनाना है तो संसद और विधानसभाओं को बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा था कि देश में जारी गृह युद्धों को लिए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जिम्मेदार हैं। निशिकांत दुबे की टिप्पणी से बीजेपी ने किनारा करते हुए कहा कि यह उनकी व्यक्तिगत राय है, लेकिन न्यायविदों और विपक्षी दलों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया जताई है। उनका कहना है कि यह सुप्रीम कोर्ट का अपमान है और अवमानना का मामला है।

इस बाबत एक वकील ने देश के अटॉर्नी जनरल को पत्र लिखकर निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना का मामला चलाए जाने की इजाजत मांगी है। बीजेपी सासंद निशिकांत दुबे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लेटर पिटिशन दाखिल की गई है। लेटर पिटिशन दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेकर आपराधिक अवमानना का मामला चलाने की मांग की गई। ये मांग सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र मिश्रा की तरफ से दाखिल की है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की सुप्रीम कोर्ट को लेकर की गई टिप्पणी पर विवाद बढ़ता जा रहा है। अधिवक्ता अनस तनवीर ने इस मामले में देश के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि को चिट्ठी लिखकर बीजेपी सांसद के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की इजाजत मांगी है। बता दें कि नियम के तहत कंटेप्ट मामले के लिए अटॉर्नी जनरल से इजाजत लेनी होती है।

याचिकाकर्ता की ओर से वक्फ अधिनियम मामले में पैरवी कर रहे सुप्रीम कोर्ट के वकील अनस तनवीर ने आरोप लगाया है कि निशिकांत दुबे ने 'बेहद अपमानजनक' और सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को कम करने के उद्देश्य से टिप्पणी की है। याचिकाकर्ता के आवेदन में कहा गया है कि निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर तीखा हमला करते हुए कहा था कि अगर कानून सुप्रीम कोर्ट को ही बनाना है, तो संसद और राज्य विधानसभाओं को बंद कर देना चाहिए। उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना पर भी निशाना साधा था और उन्हें देश में गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया। पत्र में कहा गया है कि दुबे की टिप्पणी 'गंभीर रूप से अपमानजनक' और 'खतरनाक रूप से भड़काऊ' हैं। वहीं इससे पहले कांग्रेस ने बीजेपी के सांसदों निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा द्वारा उच्चतम न्यायालय की आलोचना किए जाने के बाद पार्टी को खुद से इससे अलग करने की कवायद को ''डैमेज कंट्रोल'' करार दिया था और जानना चाहा था कि दोनों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई।

समाजवादी पार्टी नेता एस टी हसन ने निशिकांत दुबे के बयान पर कहा है कि ये लोग वोट हासिल करने के लिए हिंदू-मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि, "देश में अराजकता फैलाने के लिए यही लोग जिम्मेदार हैं। ये लोग अजान का विरोध करते हैं, हिजाब का विरोध करते हैं, मदरसों पर बुलडोजर चलाते हैं... यही लोग देश में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा कर रहे हैं, न कि सुप्रीम कोर्ट...सुप्रीम कोर्ट तो देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम कर रहा है।"

इस बीच सीपीआई नेता बिनॉय विश्वम ने भी निशिकांत के बयान की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि देश में सांप्रदायिकता भड़काने के लिए बीजेपी और आरएसएस ही जिम्मेदार हैं। निशिकांत दुबे के बयान पर न्यायविदों ने भी चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने निशिकांत दुबे के बयान को बेहद गैरजिम्मेदाराना करार दिया है। उन्होने कहा कि संविधान में, सभी संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका तय है। अगर संसद कोई कानून बनाता है, तो फिर राष्ट्रपति की उस पर मंजूरी ली जाती है तभी वह लागू होता है। उन्होंने कहा कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर संसद के बनाए कानून को राष्ट्रपति मंजूरी न दें तो क्या वह वैध होगा? ऐसे में इस तरह के बयान देना बेहद गैरजिम्मेदाराना हैं।

क्या पश्चिम बंगाल में जल्द लग सकता है राष्ट्रपति शासन?

राजनीतिक डेस्क

अब इस बात की सम्भावना ज्यादा बढ़ गई है कि पश्चिम बंगाल में जल्द ही राष्ट्रपति शासन का ऐलान हो जाए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जिस तरह की घटनाएं घटी और हिंसा हुई है उसके बाद सूबे के राज्यपाल जिस अंदाज में ट्रेन से मुर्शिदाबाद पहुंचकर सीधे प्रभावित जनता से पुलिसिया अंदाज में रिपोर्ट ले रहे थे वह इस बात की तस्दीक करती है है ममता की सरकार के समय अब ख़त्म हो गए। अगले साल वहां विधान सभा चुनाव होने हैं और इस चुनाव में बीजेपी किसी भी तरह से ममता की सरकार को पैदल करने की रणनीति पर काम कर रही है। मुर्शिदाबाद की हिंसा अब बीजेपी के लिए ममता सरकार को ख़त्म करने का एक बड़ा बहाना मिलता दिख रहा है। बीजेपी इस खेल के जरिये हिंदू वोटरों में अपना आधार बढ़ाने की कोशिश करेगी।

मुर्शिदाबाद की घटना के बाद बीजेपी के लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अब उन्हें एक बड़ा मौक़ा मिल गया है और इस मौके का सही इस्तेमाल कर लिया गया तो प्रदेश की राजनीति में उसकी पहुँच और भी तेज होगी और टीएमसी की सरकार को ख़त्म किया जा सकता है। मुर्शिदाबाद पहुंचकर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने लोगों से मुलाकात की और यह भी कहा कि उन्हें बताया गया कि महिलाओं को धमकाया गया और बदमाश उनके घरों में घुस गए थे। उन्होंने यह भी कहा कि वे निश्चित रूप से इस मामले में कोई कदम उठाएंगे। उधर घटनास्थल से लौटने के बाद राज्यपाल की तबियत ख़राब

हो गई और उन्हें सीने में दर्द की शिकायत की वजह से तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। ममता बनर्जी ने उनका हालचाल भी पूछा और अपने सचिव को यह भी कहा कि राज्यपाल के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाए।

बता दें कि मुर्शिदाबाद जिले के कई इलाकों में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ 11 और 12 अप्रैल को हुए प्रदर्शनों के दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी। इसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी। हिंसा को देखते हुए कई परिवारों ने पड़ोसी जिले मालदा में पलायन किया था। पुलिस ने दंगा करने और तोड़फोड़ में शामिल होने के आरोप में अब तक 274 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हिंसा प्रभावित इलाकों में अर्धसैनिक और पुलिस बल के जवानों को तैनात किया गया है। लेकिन असली बात तो राज्यपाल के घटना स्थल के दौरे को लेकर है। जब किसी प्रदेश का शासन प्रमुख अर्थात् राज्यपाल ट्रेन से सफर कर राज्य के किसी घटना स्थल पर पहुंचे और एक पुलिस अधिकारी की तरह घटनास्थल पर पीड़ितों के बयान ले और स्वयं उसी जगह यह घोषणा भी करें कि वे राष्ट्रपति जी को शीघ्र ही इसकी रिपोर्ट भेजेंगे, इसका सीधा-सीधा तात्पर्य तो यही हुआ कि वह गैर भाजपा शासित राज्य है और वहां अगले साल राष्ट्रपति शासन के दौरान विधानसभा चुनाव कराने है। अब माना जा रहा है कि अगले कुछ ही दिनों में राज्यपाल महोदय की रिपोर्ट पर केन्द्र सरकार पश्चिम बंगाल की सरकार बर्खास्त करवाकर राष्ट्रपति शासन लगा सकती हैं।

यहां यह स्मरणीय है कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार एक लम्बे समय से केन्द्र की मोदी सरकार की आंख की किरकिरी बनी हुई है, और मोदी जी व उनकी भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। इसलिए मोदी सरकार लम्बे समय से उन वैधानिक व संवैधानिक कारणों की तलाश में रही है, जिनके आधार पर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सके। अब इस प्रदेश के मुर्शिदाबाद में घटी घटना ने ममता विरोधियों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी है तथा राज्यपाल के तुरंत-फुरत दौरे और उनकी रिपोर्ट के बाद अब पश्चिम बंगाल में कभी भी ममता सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है, जबकि इस प्रदेश में अगले वर्ष विधानसभा के चुनाव होना है और भाजपा इस प्रदेश पर भी अपना वर्चस्व कायम करना चाहती है। अब देश के विभिन्न हिस्सों में जो कुछ भी घटित हो रहा है, वह सबसे अहम् चिंता का विषय है, 2026 में होने वाले चुनावों से पहले तमिलनाडु में उत्तर-दक्षिण की दरारें गहरा रही है और मुर्शिदाबाद के बाद पश्चिम बंगाल में साम्प्रदायिक धुरवीकरण की संभावना बढ़ रही है, ये दोनों ही परिदृष्य देश की भावी राजनीति के लिए चिंताजनक बने हुए है। अब एक ओर जहां देश राजनीतिक दृष्टि से खतरनाक मोड़ पर खड़ा है, वहीं उप-राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कई नए संवैधानिक सवाल खड़े कर दिए है, वह भी न्यायपालिका और विधायिका के अधिकारों को लेकर।

सितंबर में चुनाव आयोग कर सकता है चुनाव की घोषणा

बिहार में चुनाव की तैयारी शुरू, सितंबर में हो सकता है चुनाव की घोषणा

न्यूज़ डेस्क

बिहार विधान सभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी भी आगे बढ़ रही है इसके साथ ही सूबे की सभी पार्टियां भी जनता के बीच पहुँच रही है। कई पार्टियां बड़े स्तर पर सांगठनिक इकाइयों को मजबूत कर रही है और सदस्यता अभियान भी चला रही है। बिहार में इस बार भी मुख्य मुकाबला एनडीए और इंडिया के बीच है हालांकि कुछ नयी पार्टियां भी चुनावी मैदान में उतरने जा रही है और इन पार्टियों को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता क्योंकि इन नयी पार्टियों के पास भी अपने जातीय वोट हैं और युवाओं की ताकत भी। फिर भी मुकाबला एनडीए और इंडिया के बीच ही होना है।

इधर सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि चुनाव आयोग भी बिहार चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है और उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी तीन चरणों में ही चुनाव हो सकते हैं। सूत्र के मुताबिक चुनाव आयोग सितम्बर के पहले सप्ताह में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। निर्वाचन आयोग के सूत्रों के मुताबिक, पिछली बार की तरह इस बार भी बिहार की सभी 243 सीटों पर तीन फेज में चुनाव होने की संभावना है।

पिछली बार कोविड की वजह से हुई थी देरी

बता दें, पिछली बार कोविड महामारी की वजह से 25 सितंबर 2020 को निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा की थी। जबकि, 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा 9 सितंबर को हो गई थी। वर्तमान में प्रदेश में स्थिति सामान्य है। ऐसे में आयोग तय समय पर चुनाव की घोषणा करने की तैयारी में जुटा है। 2020 में बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त हो रहा था, जबकि इस बार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। इस वजह से भी चुनाव की घोषणा पहले होने की संभावना है। साल 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव तीन फेज में हुआ था और 10 नवंबर को परिणाम आए थे। वहीं, 2015 में पांच चरणों में चुनाव संपन्न हुए थे।

सीएम फेस को लेकर मारामारी

इस चुनाव में सीएम फेस को लेकर भी मारामारी है। इंडिया गठबंधन में सीएम का चेहरा कौन होगा। अभी तय नहीं हुआ है। राजद की तरफ से तेजस्वी यादव का नाम सीएम फेस के रूप में पेश किया जा रहा है हालांकि कांग्रेस ने अभी तक इस पर अपनी सहमति नहीं दी है। कांग्रेस इस बार भी राजद और बाकी महागठबंधन के दलों के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ने को तैयार है लेकिन सीएम फेस को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं ले पायी है। कांग्रेस चाहती है कि चुनाव परिणाम के बाद सीएम का चुनाव किया जा सकता है। लेकिन इस बात की सम्भावना बढ़ रही है कि अंततः तेजस्वी यादव के नाम पर सहमति बन सकती है। कांग्रेस इसके लीयूए कुछ शर्तें भी रख सकती है। कांग्रेस की इच्छा यही है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो एक मुस्लिम और एक दलित को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए।

उधर एनडीए के भीतर भी अभी बहुत कुछ साफ़ नहीं है। कहने को तो यही कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की अगुवाई में ही एनडीए चुनाव लड़ेगा लेकिन चुनाव के बाद क्या कुछ होता है इस पर कायदे से अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता ? बीजेपी की इच्छा यही है कि सत्ता उसके हाथ आये और वह अभी सम्राट चौधरी के साथ ही किसी और चेहरे पर दाव खेलने को तैयार है।

उधर प्रशांत किशोर की पटना रैली भले ही फेल हो गई है लेकिन एक बात साफ़ है कि जन सुराज के पास भी कुछ वोट बैंक तैयार हो गया है और इसका असर चुनाव पर पड़ना तय माना जा रहा है। प्रशांत किशोर जिस तरह से सीएम फेस के रूप में आगे बढ़ते जा रहे हैं उससे तो यही लगता है कि इस बार का बिहार चुनाव बड़ा परिवर्तन कारी हो सकता है।

सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में बढ़ी रार

न्यूज़ डेस्क

बिहार एनडीए में सीटों को लेकर रार मची है। सामने से कोई कुछ भी नहीं कह रहा है लेकिन पीछे से एनडीए का हर घटक दल बहुत कुछ कह रहा है। सभी घटक दल बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। बिहार के कई इलाकों में घटक दल बैठक कर रहे हैं। कहीं जीतन राम मांझी की बैठक हो रही है तो कही उपेंद्र कुशवाहा अपने लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं। उधर चिराग पासवान भी बहुत कुछ कह रहे हैं। फिर उनकी पार्टी के नेता भी बोल रहे हैं। चिराग पासवान की इच्छा भी सूबे का सीएम बनने की है। भला हो भी क्यों नहीं ? जब झारखंड में एक सीट जीतकर कोई सीएम बन सकता है तो बिहार में क्यों नहीं ? जब बीजेपी के लोग सीएम बन सकते हैं तो बाकी घटक दल के सीएम क्यों नहीं बन सकते ? शर्त एक ही होती है। वह शर्त है दर्जन भर सीटें छोटी पार्टियों की झोली में पहुंच जाए। इस बार के चुनाव बिहार में यही सब होना है।

चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने चिराग के विधानसभा का चुनाव लड़ने और उनके मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा का ऐलान किया है। वे प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी के साथ अपनी नजदीकी भी दिखा रहे हैं। माना जा रहा है कि सीटों की संख्या बढ़वाने के लिए वे दबाव की राजनीति कर रहे हैं। भले ही चिराग पासवान खुद को मोदी का हनुमान कहते हों लेकिन राजनीति में कोई किसी का परमानेंट साथी नहीं होता और नहीं कोई किसी का दुश्मन ही होता है। समय के साथ विचार भी बदल जाते हैं। आस्था भी बदल जाती है और गठबंधन के स्वरूप भी बदल जाते हैं। इसलिए चुनाव से पहले और बाद में चिराग भी बदल जाएँ इसकी कोई गारंटी नहीं। समीकरण बदले तो राजनीति भी बदल जायेगी। उधर हम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के समय उनको दो सीट और एक राज्यसभा देने का वादा किया गया था लेकिन एक ही लोकसभा सीट मिली। इसलिए वे विधानसभा की 30 सीटें लेंगे। पिछली बार उनको विधानसभा की सात सीटें मिली थीं लड़ने के लिए इस बार वे 30 की बात कर रहे हैं। अब वे केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। इन्हे भी अपना जनाधार बढ़ाना है। दलितों के बीच पैठ बढ़ानी है। सीटें बढ़ानी है ताकि चुनाव परिणाम के बाद सीएम की कुर्सी की दावेदारी कर सकें। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा 26 अप्रैल से वाल्मिकीनगर में अपना अधिवेशन करने वाले हैं।

बिहार एनडीए में सीटों को लेकर मारामारी

घटक दलों को चाहिए ज्यादा सीटें, बीजेपी की बढ़ रही मुश्किलें

बिहार चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश को घेरा

जातिगत सर्वे और भूदानी जमीन पर की श्वेत पत्र की मांग

राजनीतिक डेस्क

बिहार चुनाव से पहले जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला करते हुए जातिगत सर्वेक्षण और भूदानी जमीन पर श्वेत पत्र की मांग की है और कहा है कि सरकार अगर ऐसा नहीं करती है तो जन सुराज राज्यव्यापी आंदोलन करेगी और लोगों को इस सरकार की सच्चाई बताएगी। चुनाव से पहले प्रशांत किशोर का यह बयान नीतीश सरकार के गले की फांस बन सकती है और बड़ी बात तो यह है कि अगर नीतीश कुमार ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें भी जुमलेबाज नेता के रूप में बदनाम किया जा सकता है। बता दें कि जातिगत सर्वे कराते समय नीतीश कुमार ने बिहारी दसमाज से यही कहा था कि इस सर्वे के बाद सभी वर्गों को उनकी आबादी के मुताबिक आरक्षण दिया जाएगा जो अभी तक संभव नहीं हो सका। इससे पहले सीएम नीतीश ने दलितों से महादलित समाज को अलग करते हुए भूमिहीन लोगों को घर बनाने के लिए तीन डिसमिल जमीन देने की बात कही थी। लेकिन यह भी सच सावित नहीं हुआ। अब प्रशांत किशोर इसी मुद्दे को आगे बढ़ा कर नीतीश की राजनीति पर हमला करने को तैयार हैं।

गौरतलब है कि प्रशांत किशोर ने जातिगत जनगणना, भूमि सर्वेक्षण और दलितों और महादलितों को घर बनाने के लिए तीन-तीन डिसमिल जमीन आवंटित करने को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना की।किशोर ने मीडिया से कहा कि जाति आधारित सर्वेक्षण के नाम पर बिहार के लोगों को बेवकूफ बनाया गया है, क्योंकि राज्य सरकार लगभग 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने में विफल रही है, जिनकी मासिक आय सर्वेक्षण रिपोर्ट में 5,000 रुपये से कम दिखाई गई थी।

चुनाव से पहले जन सुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर का सीएम पर बड़ा हमला

जातिगत सर्वे और भूदानी जमीन पर की श्वेत पत्र की मांग

उन्होंने पूछा, "मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकार को सौंपी गई जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट के तुरंत बाद घोषणा की थी कि 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपये दिए जाएंगे, जिनकी आय 5,000 रुपये प्रति माह से कम है। लेकिन सीएम के वादे का क्या हुआ?"

इसी तरह, नीतीश ने 39 लाख दलित और महादलित परिवारों को तीन-तीन डिसमिल जमीन आवंटित करने का वादा किया था, जिनके पास अपना घर बनाने के लिए अपनी जमीन नहीं थी। उन्होंने कहा कि सरकारी रिपोर्टों के अनुसार, अब तक केवल 1.20 लाख परिवारों को इस योजना के तहत कवर किया गया है। बता दें कि 2006 में दलितों और महादलितों के उत्थान के लिए दलित विकास मिशन की स्थापना की गई थी। उनमें से केवल 2.34 लाख लोगों को तीन डिसमिल जमीन आवंटित की गई। केंद्र सरकार द्वारा गठित देशपाल समिति की टीम ने पटना का दौरा किया। समिति ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया कि 1.20 लाख लोगों को सिर्फ कागजों पर जमीन आवंटित की गई। उन्होंने कहा, "इन 1.20 लाख परिवारों के पास राज्य सरकार द्वारा दी गई जमीन का मालिकाना हक नहीं है। जन सुराज पार्टी अब जानना चाहती है कि शेष 48 लाख लोगों को अपनी जमीन पर घर बनाने के लिए तीन डिसमिल जमीन कब दी जाएगी।"

जन सुराज पार्टी के संस्थापक ने कहा कि बिहार में 2013 में भूमि सर्वेक्षण शुरू हुआ, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। दूसरी ओर, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिणी राज्यों ने समय-सीमा के भीतर भूमि सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया। किशोर ने कहा कि बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण के नाम पर भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण शुरू किया। लेकिन अंचल कार्यालय और उप विकास आयुक्त के अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और भूमि सर्वेक्षण से संबंधित कार्यों को रोक रहे हैं। उन्होंने कहा, "राज्य की केवल 20 प्रतिशत आबादी ने ही डिजिटलीकरण और उसके बाद भूमि सर्वेक्षण के लिए अपनी भूमि के अभिलेख प्रस्तुत किए हैं। शेष 80 प्रतिशत लोग अंचल अधिकारियों और डीसीएलआर के कार्यालयों में भ्रष्टाचार के कारण भूमि के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके।" प्रशांत किशोर ने सरकार से भूदान भूमि और भूमि सीलिंग अधिनियम के तहत जब्त की गई भूमि के बारे में भी जानना चाहा। किशोर ने जोर देकर कहा, "भूमि कहां है? लाभार्थी कौन हैं? सरकार को लोगों को जानकारी प्रदान करनी चाहिए।"

बता दें कि जन सुराज पार्टी 11 मई को राज्य के करीब 40 हजार राजस्व गांवों में बैठक कर लोगों से हस्ताक्षर कराएगी। बैठक के बाद एक करोड़ से अधिक लोगों के हस्ताक्षर वाला ज्ञापन मुख्यमंत्री और राज्यपाल को सौंपा जाएगा। इसके अलावा पार्टी अपनी मांग को लेकर दबाव बनाने के लिए अंतिम सत्र में विधानसभा का घेराव करेगी। किशोर ने बताया कि उन्होंने एक महीने के अंदर जाति जनगणना पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की, अन्यथा जन सुराज पार्टी आंदोलन करेगी।

न्यू देहली पोस्ट

छत्तीसगढ़ महादेव ऐप कांड

ईडी ने की 573 करोड़ की संपत्तियां जब्त

न्यूज़ डेस्क

छत्तीसगढ़ में हुए महादेव एप कांड को लेकर अभी भी कार्रवाई जारी है। अभी हाल में ईडी ने कई सट्टेबाजों के यहाँ कार्रवाई की और करीब 573 करोड़ की सम्पत्तियाँ जब्त की है। यह ईडी की बड़ी कार्रवाई है। जांच में पता चला कि सट्टेबाजी से कमाए गए पैसे को विदेश भेजा गया और फिर उसे एफपीआई के नाम पर भारतीय शेयर बाजार में लगाया गया। यह कार्रवाई दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में की गई। एजेंसी का कहना है कि इस मामले में कुछ लोगों ने मिलकर छोटे और मध्यम उद्योगों के शेयरों की कीमत बढ़ाई, ताकि आम निवेशकों को धोखा दिया जा सके।

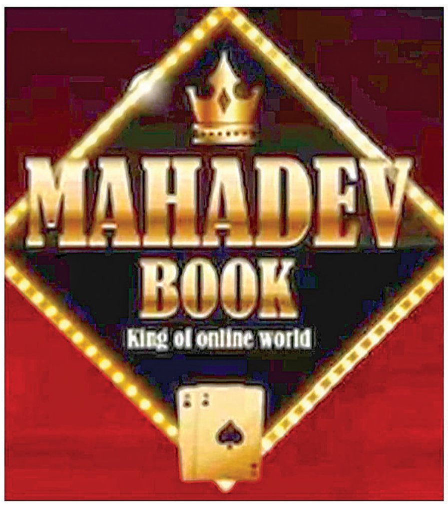

ईडी की छापेमारी

ईडी ने 16 अप्रैल को दिल्ली, मुंबई, इंदौर, अहमदाबाद, चंडीगढ़, चेन्नई और संबलपुर में छापेमारी की। इस दौरान 3.29 करोड़ रुपए नकद भी जब्त किए गए। ईडी ने एक बयान में कहा कि तलाशी कार्रवाई के परिणामस्वरूप 3.29 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की गई, 573 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की प्रतिभूतियों, बांड और डीमैट खातों पर रोक लगा दी गई। इसके अलावा विभिन्न दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी जब्त किए गए।

महादेव बेटिंग ऐप का मामला

महादेव बेटिंग ऐप का मामला कुछ साल पहले सामने आया था। तब एजेंसी ने कहा था कि छत्तीसगढ़ के कुछ नेता और अफसर इस ऐप के अवैध काम और पैसे के लेनदेन में शामिल हैं। इस ऐप को सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल नाम के दो लोगों ने शुरू किया था। दोनों छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। जांच एजेंसी ईडी का कहना है कि कुछ कंपनियों ने मिलकर एसएमई सेक्टर के शेयरों की कीमत बढ़ाई। ऐसा इसलिए किया गया ताकि आम निवेशकों को नुकसान हो। ईडी के अनुसार, कुछ लोग शेयरों की कीमत में हेरफेर करके गलत तरीके से पैसा कमा रहे थे।

अब तक 13 गिरफ्तार

ईडी ने इस मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। 74 आरोपियों के खिलाफ पांच आरोपपत्र भी दाखिल किए गए हैं। इसके अलावा, 3,002 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त की गई है। ईडी का अनुमान है कि इस मामले में लगभग 6,000 करोड़ रुपए का अपराध हुआ है। वहीं, ईडी इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस घोटाले में और कौन-कौन शामिल है और पैसे का इस्तेमाल कहां-कहां किया गया।

उज्जैन सिंहस्थ की तैयारी शुरू ,बन रहे हैं होल्डिंग जोन

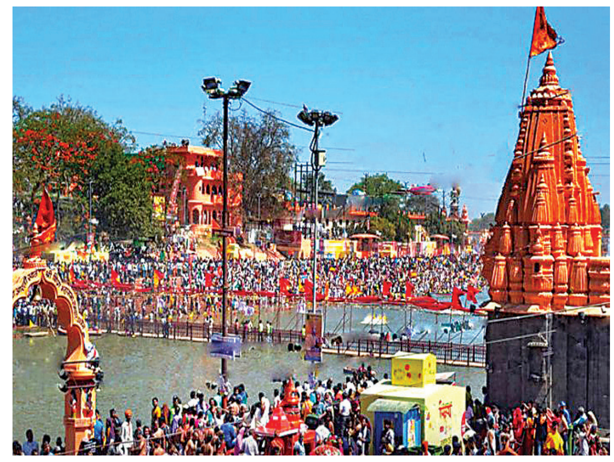

न्यूज़ डेस्क

प्रयागराज के बाद अब उज्जैन में सिंहस्थ की तैयारी चल रही है। यहाँ 2028 में सिंहस्थ का आयोजन होना है। तैयारी सुरक्षित और भव्य हो इसको लेकर सरकार बड़े स्तर पर तैयारी कर रही है ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी नहीं हो। इंदौर शहर में अलग-अलग जगह होल्डिंग जोन बनाने का प्रस्ताव है, ताकि उज्जैन में भीड़ बढ़ने पर बाहरी लोगों को यहां रोका जाए। जमीन हासिल करने के बाद सभी विभाग यहां हर तरह की सुविधा का इंतजाम करेंगे। पुलिस ने बल व अन्य संसाधनों के साथ हाई-वे चौकियां, सहायता केंद्र व इंट्रीग्रेटेड कमांड सेंटर स्थापित करने की अनुमति मांगी है।

एक-दो दिन तक रोकने की रहेगी व्यवस्था

होल्डिंग जोन बनाने के लिए कुछ जगह चिन्हित की है। यहां 50 हजार से ज्यादा लोगों को रोकने के लिए विश्राम स्थल, कुर्सियां, सुविधा गृह, पंखे, कूलर, पेयजल आदि की व्यवस्था की जाएगी। उज्जैन में भीड़ अधिक होने पर बाहरी लोगों को यहां ठहराया जाएगा। एक-दो दिन तक रोकने की व्यवस्था रहेगी। एडिशनल कमिश्नर मनोज श्रीवास्तव के मुताबिक, लवकुश चौराहे पर लेफ्ट साइड की खाली जमीन, रिंग रोड पर रोबोट चौराहे के पास आइडीए की जमीन, मांगलिया व तेजाजी नगर में भी होल्डिंग एरिया के लिए जमीन मांगी है। उज्जैन में हुई बैठकों में कई प्रस्ताव मंजूर हो चुके हैं।

भोपाल में एक मंच पर इकट्ठा हुए पत्नियों से सताए पति

न्यूज़ डेस्क

पिछले दिनों भोपाल में एक मंच पर पत्नी से प्रताड़ित पतियों का एक समूह एक मंच पर इकट्ठा हुए और अपनी आपबीती से लोगों को परिचय कराया। सताए पतियों की बात सुनकर लोग दंग रह गए। लीगल वाच नामक संस्था के मंच पर इकट्ठा हुए सताए पतियों की कहानी काफी भावुक भी थी और परेशानी भरा भी। लीगल वाच संस्था की प्रमुख भी एक महिला ही है। उनका नाम है चांदना अरोड़ा। अरोड़ा कहती हैं कि ऐसा नहीं है कि समाज में सिर्फ पुरुष ही महिलाओं पर जुल्म करते हैं। हमारे समाज मढे बहुत सी महिलाएं भी पुरुषों को सताने से बाज नहीं आती और चुकी हमारा समाज महिलाओं के प्रति ज्यादा सद्भाव रखता है इसलिए दाम्पत्य जीवन से लेकर पारिवारिक कलह के लिए सिर्फ पुरुषों को ही जिम्मेदार मानता है। लेकिन ऐसा है नहीं। सच तो यह है कि पति भी प्रताड़ित होते हैं और इसके लिए पूरा रैकेट काम करता है। अब इस बात की भी जरुरत है कि महिला आयोग की तरह ही पुरुष आयोग भी बने। क्योंकि आज परिवार में जो हो रहा है वह वैवाहिक आतंकवाद से कम नहीं है।

अरोड़ा कहती हैं कि ''जो पति प्रताड़ित हैं उनमें से ज्यादातर सरकारी या अच्छी नौकरियों में हैं, जिन्हें उनकी पत्नियों और उनके घर वालों की तरफ से प्रताड़ित किया जा रहा है. पुरुष होने की वजह से एक विशेष नजर से हम लोगों को देखा जाता है और कई मामलों में इन्हें न्याय भी नहीं मिल पाता है, नतीजा है कि ऐसे लोग मानसिक, सामाजिक, और आर्थिक तौर पर प्रताड़ित हो रहे हैं।'' इसी मंच से कुछ सताए पतियों ने अपनी आपबीती भी सुनाई। भोपाल के रहने वाले आफताब अली ने बताया, "साल 2009 में मेरी शादी हुई थी। 2017 से शादी के बाद मुझ पर मामले दर्ज होने शुरू हुए, जो 2019 से केस लगे. गोधरा गुजरात में मेरे खिलाफ केस लगाया। पहले केस लगाया कि मारपीट करके मैंने पत्नी को निकाल दिया। फिर मेंटेनेंस का केस लगाया. दूसरा मामला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में लगाया। जबकि जिस दिन मारपीट के आरोप मुझ पर लगाए गए हैं, उस दिन मैं भोपाल में था। ''

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, ''उनकी एक ही मांग थी कि घर वालों से अलग हो जाओ. ये मंजूर नहीं किया, तो डिवोर्स दे दिया। हमारी अरैंज मैरिज थी। अब ये हालत हैं कि मैं अदालत की पेशी के लिए गुजरात से उत्तर प्रदेश भागता रहता हूं। आप सोचिए जिसे दिखाई नहीं देता, जो सहारा लेकर चलता हो, वो कैसे किसी को मार सकता है, लेकिन मारपीट की धाराएं लगी हैं। अब कोर्ट में मामला अटका है. तारीख पर बार-बार जाना वकील की फीस सब भुगत रहा हूं। पुलिस ने भी बिना जांचे मुझ पर एफआईआर कर दी।" एक अन्य सताये पति वाल्मीक अहीरे ने बताया, ''शादी के बाद से ही उनकी पत्नी का उन पर अत्याचार कर रही है। पत्नी लगातार उनकी मां को वृद्धाश्रम भेजने की मांग करती रही। मैंने अपने परिवार को बचाने

बागेश्वर धाम के हिन्दू गांव पर क्यों भड़क गए शंकराचार्य?

न्यूज़ डेस्क

मध्यप्रदेश के जबलपुर प्रवास पर पहुंचे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद इन दिनों बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर काफी भड़क रहे हैं। अविमुक्तेश्वरानंद ने धीरेंद्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र बनाने के विचार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी से मिलने के बाद धीरेंद्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की जगह हिंदू गांव क्यों बना रहे हैं? शंकराचार्य ने कहा कि यह तो ऐसा ही है जैसे कोई हाथी बनाने निकला था, लेकिन चूहा बना रहा है। उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री से सवाल पूछा कि जिस गांव में बागेश्वर धाम है, क्या वह हिंदू गांव नहीं है? उन्होंने पूछा कि धीरेंद्र शास्त्री किस आधार पर अपने गांव को हिंदू गांव मानने से इनकार कर रहे हैं।

शंकराचार्य ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार जिस संविधान की बात करती है, उसी के खिलाफ कानून बना रही है। उन्होंने गौ हत्या के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार गौ हत्या रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। शंकराचार्य ने कहा कि अगर कोई उनकी मां (गौ माता) को काटेगा या चोट पहुंचाएगा, तो वे चुप नहीं बैठेंगे। वे बल का प्रयोग करके अपनी मां की रक्षा करेंगे। कानून के भरोसे गौ माता को मरने नहीं देंगे।

सनातन बोर्ड पर कोई बात नहीं ?

शंकराचार्य ने बंगाल हिंसा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद राष्ट्रपति शासन की बात तो हो रही है, लेकिन लगाया नहीं जा रहा है। उन्होंने बंगाल हिंसा पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने सनातन बोर्ड के गठन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सनातन बोर्ड का स्वरूप कैसा होगा, यह कोई बताने को तैयार नहीं है। उन्होंने आशंका जताई कि अगर सरकार ने सनातन बोर्ड बनाया तो उसका हाल भी वक्फ बोर्ड जैसा ही होगा। उन्होंने कहा, "हम अपना गला क्यों सरकार को पकड़ाएं। "

छत्तीसगढ़ की 70 वर्षीय महिला ने लिखा खून से राष्ट्रपति को पत्र

छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले की 70 वर्षीय महिला ओम बाई बघेल ने न्याय की गुहार लगाते हुए राष्ट्रपति को अपने खून से पत्र लिखा है। मामला जमीन विवाद से जुड़ा है। न्याय नहीं मिलने से निराश होकर महिला ने यह कदम उठाया।छुरा ब्लॉक निवासी ओम बाई गंभीर बीमारी टीबी से पीड़ित हैं और लंबे समय से अपनी पुरतैनी जमीन को लेकर गांव के संतोष सारडा के साथ उनका विवाद है। महिला का कहना है कि इस जमीन पर उनके पूर्वजों की परंपरागत समाधि (मठ) बनी थी, जिसे संतोष सारडा ने जबरन तोड़कर जमीन पर कब्जा कर लिया। ओम बाई का आरोप है कि मठ तोड़ते समय महिलाओं के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया और उन्हें लगातार प्रताड़ित किया गया। प्रशासन से कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अंततः वह एक पैथोलॉजी लैब गई, वहां से खून निकाल कर उसी खून से राष्ट्रपति को पत्र लिखा।

उत्तर प्रदेश में सपा की राजनीति से क्यों भयभीत हो रही है बीजेपी ?

राजनीतिक डेस्क

उत्तरप्रदेश में चुनाव तो 2027 में होने हैं लेकिन जिस राह पर सपा की राजनीति आगे बढ़ रही है उससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ठीक उसी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं जो बीजेपी सपा के खिलाफ करती रही है और उसका लाभ भी बीजेपी को मिलता रहा है। अखिलेश यादव की जब सरकार थी तब बीजेपी सपा सरकार पर यह आरोप लगाती थी कि सपा यादवों की सरकार है और सपा सरकार में सिर्फ यादवों की ही चलती है। बीजेपी ने ऐसा प्रचार करके सपा को नुकसान भी पहुँचाया ,बदनाम भी किया और सपा की सरकार को हटाया भी। अब अखिलेश यादव बीजेपी के इसी खेल को उसी पर लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। सपा ,बीजेपी के इसी खेल को पटखनी देने की रणनीति बना रहे हैं। साल 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने प्रदेश में सरकार चला रही समाजवादी पार्टी पर यादववाद का आरोप लगाया था। पीएम नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने आरोप लगाया था कि सपा सरकार ने 56 यादव एसडीएम की नियुक्ति की है। इन आरोपों का असर पड़ा और सपा को अपनी सरकार गंवानी पड़ी थी। अब विधानसभा चुनाव से दो साल पहले से सपा प्रमुख अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर ठाकुर परस्ती का आरोप लगा रहे हैं। इस तरह से अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव का टोन सेट करने की कोशिश कर रहे हैं।

अभी हाल में हुए करणी सेना विवाद पर अखिलेश यादव काफी तल्ख़ हुए। करणी सेना ने राणा सांगा पर सपा सांसद रणजी लाल सुमन के बयान को आड़े हाथ लेते हुए बवाल किया। सुमन के घर पर हमला किया और देश भर में प्रदर्शन भी किया। करणी सेना ने आगरा में बड़ा प्रदर्शन किया और कानून को अपने हाथ में लेते हुए सपा नेता के खिलाफ कई तरह की बातें भी कही। उधर अखिलेश यादव ने करणी के इस उपद्रव के लिए सूबे की योगी सरकार को घेरा और कहा कि प्रदेश में ठाकुवाद की राजनीति चल रही है और इस राजनीति को प्रदेश सरकार बढ़ा रही है। बाद में अखिलेश यादव ने करणी सेना के खेल को दलित अस्मिता से जोड़ दिया। अखिलेश यादव ने करणी सेना को बीजेपी की सेना बताते हुए बीजेपी को दलित विरोधी करार दिया। फिर अखिलेश यादव 19 अप्रैल को आगरा पहुंचे। फिर वहां से प्रयागराज गए और वहां उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई जिलों में थानेदारों की नियुक्ति में ठाकुरों को वरीयता दी गई है और पीडीए की अनदेखी की गई है। यह वही बात है जिस तरह की कहानी 2017 से पहले सपा पर बीजेपी आरोप लगाती थी।

इस तरह से सपा प्रमुख ने उत्तर प्रदेश पुलिस की तैनाती में राजपूतों के वर्चस्व को राजनीतिक मुद्दा बना दिया है. इससे वो प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को दलित और ओबीसी विरोधी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सत्ता में बीजेपी की वापसी में इन्हीं वर्गों का हाथ माना जाता है। बीजेपी पिछले दो चुनावों से यूपी में शानदार जीत दर्ज कर रही है। लेकिन अखिलेश यादव 2027 में उसे तीसरी बार जीतने से रोकने की रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। इसी रणनीति के तहत वो दलित सांसदों को आगे कर बसपा का वोट बैंक हथियाने में जुटे हुए हैं. उन्होंने पहले लोकसभा सामान्य सीट फैजाबाद से जीते दलित समुदाय के अवधेश प्रसाद को अपने साथ प्रमुखता से रखा तो अब वो अपने राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के साथ मजबूती से खड़े दिखाई दे रहे हैं। समुन राणा सांगा पर दिए विवादित बयान के बाद से करणी सेना के निशाने पर हैं। इस तरह से अखिलेश यादव ने जाटव और गैर जाटव दोनों वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। सपा उत्तर प्रदेश में पीडीए का मजबूत करने के साथ-साथ ब्राह्मणों को भी अपने साथ करना चाहती है। यही वजह है कि अखिलेश यादव ब्राह्मणों से जुड़े मामले भी उठाते रहते हैं। कानपुर में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में विकास दुबे की मौत के बाद सपा ने इस मामले को जोर-शोर से उठाया था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भगवान परशुराम की सबसे बड़ी मूर्ति लगवाने की घोषणा की थी। उन्होंने अपने सरकार में परशुराम जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था। पंडित हरिशंकर तिवारी पूर्वांचल की राजनीति का एक बड़ा चेहरा थे। उनके बेटे विनय शंकर तिवारी को प्रवर्तन निदेशालय ने सात अप्रैल को एक कथित धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार कर लिया था।

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे तैयार, उद्घाटन की तैयारी

पूर्वांचल को जोड़ने वाले इस हाई-स्पीड कॉरिडोर से लाखों लोगों को मिलेगा लाभ, यातायात की तस्वीर बदलेगी, राज्य के विकास में जुड़ेगा नया अध्याय

न्यूज़ डेस्क

उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। यह हाई-स्पीड एक्सप्रेसवे गोरखपुर के सहजनवां से शुरू होकर आजमगढ़ जिले के सलारपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ता है, जिससे गोरखपुर और लखनऊ के बीच की दूरी महज़ साढ़े तीन से चार घंटे में तय की जा सकेगी। यह लिंक एक्सप्रेसवे राज्य सरकार की रणनीतिक सोच का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य है पिछड़े जिलों को मुख्यधारा से जोड़ना, व्यापार और निवेश के लिए बेहतर वातावरण तैयार करना, और आम नागरिकों को तेज, सुरक्षित व सुगम यात्रा का अनुभव देना।

15 मई तक काम पूरा होने की संभावना

सूत्रों के अनुसार, निर्माण कार्य 15 मई तक पूरा किया जा सकता है। इसके साथ ही मई के दूसरे पखवाड़े में उद्घाटन समारोह की भी तैयारी की जा रही है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के हाथों इसका लोकार्पण होने की संभावना जताई जा रही है। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी उपस्थिति रहेगी।

कम्हरिया घाट पर बन रहे पुल का निरीक्षण

बीते मंगलवार को गोरखपुर में घाघरा नदी के ऊपर कम्हरिया घाट पर बन रहे पुल का निरीक्षण मंडलायुक्त अनिल ढींगरा और जिलाधिकारी कृष्णा करूणेश ने किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को बताया गया कि निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और इसे जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। खास तौर पर नदी के पास धारा मोड़ने और संरचना को मजबूत करने का काम तेजी से चल रहा है, ताकि उद्घाटन से पहले पूरा ढांचा तैयार हो सके।

लागत और लंबाई

यह एक्सप्रेसवे 91.35 किलोमीटर लंबा है और इसे तैयार करने में 7283 करोड़ रुपये की लागत आई है। यह रकम केवल सड़क निर्माण पर ही नहीं, बल्कि पुल, अंडरपास, सर्विस रोड, सुरक्षात्मक ढांचों और अन्य सहायक सुविधाओं पर भी खर्च हुई है। एक्सप्रेसवे के निर्माण से जहां लोगों को यात्रा में समय की बचत होगी, वहीं औद्योगिक माल की ढुलाई भी तेज और आसान हो सकेगी।

राज्य में एक्सप्रेसवे क्रांति

उत्तर प्रदेश में बीते वर्षों में एक्सप्रेसवे निर्माण को लेकर क्रांतिकारी काम हुआ है।दिल्ली-आगरा यमुना एक्सप्रेसवे, जो दिल्ली और ताजमहल के शहर आगरा को जोड़ता है, ने दो शहरों के बीच यात्रा को 6 घंटे से घटाकर 2.5 घंटे कर दिया है। इसकी कुल लंबाई 165 किमी है और यह परियोजना करीब 11,000 करोड़ में बनी। लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे ने राजधानी लखनऊ से पश्चिमी यूपी को जोड़ा। यह 302 किमी लंबा है और

इसकी लागत 13,200 करोड़ रही।इसके बाद बना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो लखनऊ से गाजीपुर तक फैला है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा बन चुका है। यह एक्सप्रेसवे 22,500 करोड़ में बना और इसकी लंबाई 340 किमी है।

इन परियोजनाओं ने केवल दूरी कम नहीं की, बल्कि लाखों लोगों के जीवन को सीधे प्रभावित किया है—चाहे वह नौकरी की तलाश में निकला युवा हो, व्यापार करने वाला कारोबारी हो या ज़रूरतमंद मरीज।

पुलों और संपर्क मार्गों ने बदली तस्वीर

सिर्फ एक्सप्रेसवे ही नहीं, राज्य सरकार ने रेलवे ओवर ब्रिज (ROB), फ्लाईओवर, और नदी पुलों के निर्माण पर भी विशेष ध्यान दिया है।बीते 5 वर्षों में यूपी में 120 से अधिक नए पुलों और फ्लाईओवर का निर्माण हुआ है।इन पुलों ने न केवल ट्रैफिक को नियंत्रित किया, बल्कि गांवों और कस्बों को ज़िलों के मुख्यालयों से जोड़ने में भी मदद की।कम्हरिया घाट, बलिया-घाघरा पुल, और वाराणसी के रिंग रोड पुल जैसे प्रोजेक्ट्स ने क्षेत्रीय आवागमन की तस्वीर ही बदल दी है।

आम जनता को होगा सीधा फायदा

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद गोरखपुर, आजमगढ़, अंबेडकरनगर और संतकबीरनगर जिलों के लाखों लोगों को आवागमन में आसानी होगी। छात्रों को विश्वविद्यालयों तक, मरीजों को बड़े अस्पतालों तक, और किसानों को मंडियों तक कम समय में, कम खर्च पर, सुरक्षित तरीके से पहुँचने का लाभ मिलेगा।

पूर्वांचल की आर्थिक गति को मिलेगा बल

यह एक्सप्रेसवे सिर्फ सड़क नहीं, विकास की धड़कन है। इसके शुरू होते ही क्षेत्र में नई इंडस्ट्रीज, वेयरहाउसिंग हब, परिवहन केंद्र, और होटल उद्योग को गति मिलेगी। इससे न सिर्फ क्षेत्रीय विकास को बल मिलेगा, बल्कि निवेश और रोज़गार के नए द्वार भी खुलेंगे।

क्या कांच उद्योग ताजमहल की चमक को कर रहा धुंधला ?

पर्यावरणीय संकट की आशंका के बीच सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सख्त कदम, ताजमहल के आसपास प्रदूषण फैलाने वाले कांच उद्योगों के मूल्यांकन का आदेश

न्यूज़ डेस्क

सदियों से मोहब्बत की निशानी ताजमहल अपनी खूबसूरती से दुनिया को मोहित करता रहा है, लेकिन अब इसका सौंदर्य संकट में है। सुप्रीम कोर्ट ने इस ऐतिहासिक धरोहर के आसपास के कांच उद्योगों से होने वाले संभावित प्रदूषण पर गंभीर चिंता जताई है। मंगलवार को अदालत ने इस विषय पर राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (NEERI) को मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि ये उद्योग ताजमहल के लिए खतरा बनते दिखे, तो उन्हें स्थानांतरित करने में कोई हिचक नहीं की जाएगी। यह निर्णय देश की सबसे प्रतिष्ठित विरासत को बचाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

ताजमहल की सेहत पर मंडरा रहा खतरा?

सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ, जिसमें जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भूइयां शामिल हैं, ने सुनवाई के दौरान यह सवाल उठाया कि आगरा में सक्रिय कांच उद्योगों से कितना प्रदूषण फैल रहा है, और वह ताजमहल को किस हद तक प्रभावित कर रहा है? कोर्ट का यह रुख तब सामने आया जब कुछ याचिकाकर्ताओं ने ताजमहल के निकट बढ़ते

औद्योगिक गतिविधियों को लेकर चिंता व्यक्त की। अदालत ने स्पष्ट किया कि वह इस मुद्दे पर केवल अनुमान के आधार पर फैसला नहीं करेगी, बल्कि वैज्ञानिक विश्लेषण और तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालेगी। इसके लिए NEERI से रिपोर्ट मांगी गई है, जिसमें यह बताया जाना अनिवार्य होगा कि मूल्यांकन कार्य कब तक पूरा हो सकता है।

सभी एजेंसियों को सहयोग का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि इस कार्य में NEERI को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित सभी सरकारी एजेंसियों से पूरा सहयोग मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी एक विशेष टीम गठित करने को कहा गया है, जो राज्य सरकार द्वारा चिन्हित कांच उद्योगों का निरीक्षण करेगी और यह देखेगी कि प्रदूषण का स्तर क्या है। इस टीम को उद्योगों से निकलने वाले उत्सर्जन और वायु गुणवत्ता पर प्रभाव का अध्ययन करना होगा, जिससे कि अदालत एक अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर जरूरी निर्देश जारी कर सके।

क्या ये उद्योग होंगे स्थानांतरित?

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट संकेत दिया कि यदि मूल्यांकन से यह साबित होता है कि ये उद्योग ताजमहल को नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो उन्हें तुरंत किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने का आदेश दिया जा सकता है। अदालत ने कहा, "अगर ये उद्योग वाकई प्रदूषण फैला रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करना हमारी जिम्मेदारी है।" यह एक कड़ा संदेश है कि अब कोई भी औद्योगिक गतिविधि पर्यावरणीय जिम्मेदारियों से बचकर नहीं निकल सकती, विशेषकर तब जब वह भारत की सांस्कृतिक धरोहरों पर असर डाल रही हो।

पहले भी उठ चुका है संरक्षण का सवाल

यह पहला मौका नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल की सुरक्षा को लेकर सख्ती दिखाई है। इससे पहले भी कोर्ट ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन (TTZ) प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा चुका है। कोर्ट ने तल्ख लहजे में कहा था, "क्या इस स्मारक की सुरक्षा केवल एक दिखावा बनकर रह गई है?" साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया था कि मौजूदा उपाय इस विश्वविख्यात इमारत की रक्षा के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

विरासत की रक्षा, केवल शब्दों से नहीं, नीतियों से हो

भारत की पहचान का प्रतीक बना ताजमहल केवल एक स्मारक नहीं, बल्कि देश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक आत्मा है। इसकी रक्षा करना न सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार, बल्कि पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी है। कांच उद्योग जैसे विकास के प्रतीक अगर संवेदनशील पर्यावरणीय क्षेत्रों में स्थापित होते हैं, तो उनके प्रभावों की समय रहते जांच और सुधार बेहद आवश्यक है।

न्यू देहली पोस्ट

स्कूल की गलती और अनुसूचित जाति की छात्रा पर गिरी गाज

न्यूज़ डेस्क

तमिलनाडु स्कूल शिक्षा विभाग की लापरवाही की एक चौंकाने वाली घटना सामने आयी है। नीलगिरी में अनुसूचित समुदाय से ताल्लुक रखने वाली पहली पीढ़ी की छात्रा के लिए स्कूल की गलती महंगी साबित हो गई है।जानकारी के मुताबिक़ वर्ष 2022 में कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में तीन विषयों में अनुत्तीर्ण होने के बावजूद छात्रा को कक्षा 11 और 12 में प्रवेश दिया गया तथा दोनों सार्वजनिक परीक्षाएँ देने की अनुमति दी गई, जिसमें वह उत्तीर्ण हो गई । यह विसंगति तब सामने आई जब लड़की ने कॉलेज में प्रवेश के लिए आवेदन किया, जिससे उसकी हाई स्कूल की दो वर्ष की शिक्षा अमान्य हो गई तथा उसे कक्षा 8 के अंकों के आधार पर वायरमैन कोर्स के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा।

बता दें कि लड़की ने नीलगिरी जिले के अरावेनु में एक सरकारी हाई स्कूल में कक्षा 10 की पढ़ाई की थी। वर्ष 2022 में आयोजित सार्वजनिक परीक्षा में वह तीन विषयों गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में अनुत्तीर्ण हो गई। हालांकि, मानदंडों का उल्लंघन करते हुए कोटागिरी में सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका ने पूरक परीक्षाएँ लिखने से पहले ही उसे व्यावसायिक स्ट्रीम (कार्यालय प्रबंधन और सचिव) में कक्षा 11 में प्रवेश दे दिया। अगस्त 2022 में आयोजित पूरक परीक्षा में छात्रा गणित में तो उत्तीर्ण हो गई, लेकिन अन्य दो पेपरों में फिर से अनुत्तीर्ण हो गई।फिर भी, मार्च 2023 में, उसने अपनी कक्षा 11 की सार्वजनिक परीक्षा दी और 600 में से 310 अंक प्राप्त किए। अगले वर्ष, उसने कक्षा 12 की परीक्षा दी और 600 में से 306 अंकों के साथ उत्तीर्ण हुई।

स्कूल ने 6 मई, 2024 को कक्षा 11 और 12 के लिए उसकी मार्कशीट जारी की। सभी चार मार्कशीट- कक्षा 10, पूरक परीक्षा, कक्षा 11 और 12- पर सरकारी परीक्षा निदेशालय के तहत राज्य विद्यालय परीक्षा बोर्ड के सदस्य सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे।छात्रा ने बताया कि उसने अरावेनु स्कूल में अपने शिक्षक के निर्देशों के आधार पर कक्षा 10 की पूरक परीक्षा के लिए आवेदन किया था। जब उसने कोटागिरी के सरकारी स्कूल में कक्षा 11 में प्रवेश मांगा, तो तत्कालीन प्रधानाध्यापिका ने आवेदन पत्र भरने में एक शिक्षक की सहायता ली थी । छात्रा ने कहा कि "मुझे अपनी कक्षा 10 की मार्कशीट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट जमा करने के बाद कक्षा 11 में शामिल होने के लिए कहा गया था। इसके बाद, मैंने पूरक परीक्षा लिखीं, और फिर मैंने उनके बारे में नहीं सोचा। एचएम और शिक्षकों ने भी उन परीक्षाओं की स्थिति के बारे में नहीं पूछा।'' छात्रा ने बताया कि "कक्षा 12 पूरी करने के बाद, मैंने एक सरकारी कॉलेज में बीकॉम की सीट पाने का प्रयास किया, लेकिन मेरा आवेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि मैं कक्षा 10 में फेल हूँ। तभी मुझे समझ में आया कि कक्षा 11 और 12 की पढ़ाई के लिए कक्षा 10 की परीक्षा पास करना जरूरी है। उसके बाद मुझे अपनी पूरक परीक्षा की मार्कशीट मिली। अगर एचएम ने मुझे ठीक से मार्गदर्शन किया होता, तो मैं दो साल नहीं खोती।'' इस बारे में पूछे जाने पर स्कूल शिक्षा निदेशक एस कन्नप्पन ने कहा कि वे मामले की जांच करेंगे। हालांकि, उन्होंने दावा किया कि गलती केवल एचएम की नहीं थी, बल्कि छात्रा की भी थी, जो अपने परिवार में स्कूल जाने वाली पहली छात्रा थी। स्कूल शिक्षा सचिव बी चंद्रमोहन ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। बाल अधिकार कार्यकर्ता ए देवनयन ने इस स्थिति के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने पूछा, "नियमों के अनुसार, एचएम को उसे कक्षा 10 पास करने के बाद ही कक्षा 11 में दाखिला देना चाहिए था। मुझे नहीं पता कि यह कैसे हुआ। उसके कक्षा 10 के अंकों पर विचार किए बिना डीजीई ने उसके रजिस्टर नंबर और मार्कशीट कैसे तैयार कर दिए।" उन्होंने राज्य सरकार से मामले की जांच करने और एचएम, जिला और विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ डीजीई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए एक समिति बनाने का आग्रह किया।

प्रतिकात्मक

तेलंगाना में 1.3 लाख लोग एचआईवी से पीड़ित

न्यूज़ डेस्क

देश के दक्षिणी राज्य तेलंगाना में एचआईवी दसे पीड़ित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और जनवरी 2025 तक तेलंगाना में कुल 1,37,426 व्यक्ति एचआईवी से पीड़ित हैं.ये सभी लोग एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी यानी एआरटी प्राप्त कर रहे हैं। इनमें से 69,940 महिलाएं और 60,640 पुरुष हैं, जबकि 781 ट्रांसजेंडर हैं। भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी "भारत में महिला और पुरुष 2024" शीर्षक से 75वें राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, बाल चिकित्सा आबादी में 2,232 लड़के और 2,046 लड़कियां शामिल हैं, जो बाल चिकित्सा एचआईवी देखभाल में निरंतर समर्थन की महत्वपूर्ण आवश्यकता का संकेत देती हैं। रिपोर्ट ने विभिन्न राज्यों के लिंग-विशिष्ट संकेतकों की भी तस्वीर पेश की है। रिपोर्ट के अनुसार, तेलंगाना में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के वयस्कों में तम्बाकू का सेवन पुरुषों और महिलाओं के बीच एक बड़ा लिंग अंतर दिखाता है, जिसमें 22.3% पुरुष और 5.6% महिलाएं तम्बाकू उत्पादों का उपयोग करती हैं।

रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि उत्साहजनक रूप से, तेलंगाना के युवाओं (15-24 वर्ष की आयु) में साक्षरता सार्वभौमिकता के करीब पहुंच रही है। पुरुष युवा साक्षरता दर 98.16% है, जबकि महिला साक्षरता दर 95.48% है, जिससे कुल साक्षरता दर 96.88% हो जाती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कार्यात्मक साक्षरता का आकलन करते समय - जिसे समझ के साथ छोटे, सरल कथनों को पढ़ने और लिखने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है - 82.8% पुरुष योग्य हैं, जबकि केवल 67.9% महिलाएं योग्य हैं। कुल आंकड़ा 75.4% है, जो वयस्क महिला साक्षरता कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता को दर्शाता है। लेकिन रिपोर्ट में इस बात की भी चर्चा की गई है कि 25 वर्ष और उससे अधिक आयु के वयस्कों में शैक्षिक असमानताएँ बनी हुई हैं। तेलंगाना में, 62.7% पुरुषों ने कम से कम माध्यमिक शिक्षा पूरी की है, जबकि महिलाओं के लिए यह 41.3% है, जिसका कुल औसत 51.7% है।

क्या चीनी सीमा की रक्षा करने में विफल रही मोदी सरकार?

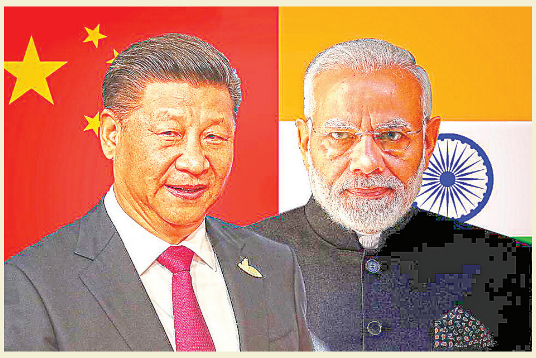

न्यूज़ डेस्क

पूर्व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और कर्नाटक के वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लीपुड़ी मंगपति पल्लम राजू ने आरोप लगाया है कि केंद्र की बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार चीन से लगती भारत की सीमा की रक्षा करने में विफल रही है। पल्लम राजू ने कहा कि "देश की सुरक्षा एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि कांग्रेस ने कभी इसका राजनीतिकरण करने की कोशिश नहीं की। मुझे लगता है कि मोदी सरकार की सबसे बड़ी विफलता चीन के साथ हमारी सीमा की रक्षा करने में उसकी विफलता रही है।"

राजू ने कहा, "2012 में भी हमारे सामने ऐसी ही स्थिति थी, जब चीनी आए और दो सप्ताह तक हमारी सीमा पर बैठे रहे। हमने (यूपीए सरकार) उस समय मौजूद तंत्रों और द्विपक्षीय साधनों और प्रभावी विदेश मामलों की बातचीत के माध्यम से इसे हल किया।" उन्होंने कहा, "यह तथ्य कि चीनी तीन साल से अधिक समय तक सीमा पर बैठे रहे और उन्होंने भारतीय क्षेत्र के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, यह दर्शाता है कि यह एक सुरक्षा विफलता और विदेश नीति की विफलता है।

राजू ने कहा कि ''यही वह बात है जिसे राहुल गांधी ने उजागर किया, जिससे केंद्र सरकार इतनी नाराज हो गई कि उन्होंने उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी... लेकिन अदालतें उनके साथ खड़ी रहीं।" उन्होंने कहा, "यह कोई रहस्य नहीं है कि हम दो मोर्चों पर अपने खतरे का आकलन करते हैं- पाकिस्तान के साथ पश्चिमी मोर्चा और चीन के साथ पूर्वी मोर्चा। अतीत में कई सेना प्रमुखों ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि अगर हमें दो मोर्चों पर युद्ध का सामना करना है तो हमें अपनी क्षमताओं को मजबूत करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे सशस्त्र बल ऐसी स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित हों।"

कांग्रेस कार्य समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य राजू ने सोनिया और राहुल के खिलाफ ईडी की चार्जशीट को बदले की राजनीति बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए मोदी सरकार ने कांग्रेस नेताओं पर ईडी का इस्तेमाल किया है।

पत्रकारिता को नए सिरे से परिभाषित करते हुए न्यू देहली पोस्ट की शानदार प्रस्तुति अब आपके सामने है। इसमें होगी खोजी और जानबूझ कर दबाई गई ख़बरों के उद्भेदन की शानदार प्रस्तुति - न्यू दिल्ली पोस्ट प्रिंट और डिजिटल के सभी मंचो के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है :-

NEW DELHI POST

न्यू देहली पोस्ट
(साप्ताहिक हिंदी)

हमारे ये सभी डिजिटल मंच सभी सोशल प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी उपलब्ध हैं। यहाँ जाकर आप ताजातरीन ख़बरों और विश्लेषण को देख समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और सुन भी सकते हैं।

Website: https://newdelhipost.co.in/
: @NewDelhiPost
: https://www.facebook.com/NewDelhiPosts
: @NewDelhiPost
:newdelhipost_official

न्यू देहली पोस्ट
B-614, 6th Floor Tower B
Noida One Building
Noida Sector 62, Gautam Budh Nagar (UP)
Pin Code -201309

संपर्क करे - Email - postnewdelhi@gmail.com

गांवों से विकसित भारत की ओर पंचायत उन्नति सूचकांक में गुजरात का परचम

न्यूज़ डेस्क

गुजरात ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जब बात जमीनी स्तर पर विकास की होती है, तो वह देश के बाकी राज्यों के लिए प्रेरणा बन जाता है। हाल ही में भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत उन्नति सूचकांक में गुजरात देश का सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाला राज्य बनकर उभरा है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर यह उपलब्धि न केवल प्रशासनिक सफलता है, बल्कि ग्रामीण भारत के लिए एक प्रेरक कहानी भी है।

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर गुजरात की ऐतिहासिक उपलब्धि, सबसे अधिक अग्रणी और बेहतर पंचायतों वाला राज्य बना

सशक्त गांव से समृद्ध राष्ट्र तक की यात्रा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'सशक्त गांव, समृद्ध राष्ट्र' के दृष्टिकोण और मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल के कुशल नेतृत्व के तहत गुजरात ने जो मुकाम हासिल किया है, वह ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक नया मानक स्थापित करता है। देश की 2.16 लाख मान्य ग्राम पंचायतों में से गुजरात की 346 पंचायतों को 'अग्रणी' और 13,781 पंचायतों को 'बेहतर प्रदर्शन' की श्रेणी में स्थान मिला है—जो दोनों ही मामलों में राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा हैं।

क्या है पंचायत उन्नति सूचकांक?

पीएआई , देश की ग्राम पंचायतों के सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में किए गए कार्यों का समग्र मूल्यांकन है। इस सूचकांक के माध्यम से ग्राम पंचायतों की स्थानीय शासन क्षमता, योजनाबद्ध विकास, सामाजिक समावेशिता और डेटा आधारित निर्णय क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। यह देश की 2.5 लाख से अधिक पंचायतों के बीच एक समान रूप से मापने योग्य प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। इसमें 9 प्रमुख विकास विषयों जैसे गरीबी उन्मूलन, जल-संपन्नता, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण, बाल-अनुकूल वातावरण, हरित विकास, सामाजिक न्याय, सुशासन और आधारभूत संरचना के मूल्यांकन हेतु 435 स्थानीय संकेतक और 566 डेटा बिंदुओं का प्रयोग किया गया है।

गुजरात के पंचायत मॉडल की क्या है खासियत?

गुजरात के पंचायत विभाग के एडिशनल डेवलपमेंट कमिश्नर डॉ. गौरव दहिया (IAS) ने बताया कि राज्य ने डेटा आधारित योजना, विभागीय समन्वय, और स्थानीय शासन को सशक्त बनाने के लिए निरंतर क्षमतावर्धन जैसे उपायों को अपनाया है। राज्य सरकार ने पंचायतों को न केवल योजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी दी है, बल्कि उन्हें निर्णायक भूमिका में भी भागीदार बनाया है।

ग्रामीण शासन की यह सफलता क्यों है अहम?

गांव ही भारत की आत्मा हैं। जब गांव विकसित होते हैं, तो देश की समग्र प्रगति सुनिश्चित होती है। पीएआई जैसे सूचकांक सरकार और समाज को यह देखने का अवसर देते हैं कि वास्तविक बदलाव कहां और कैसे हो रहा है। गुजरात का यह प्रदर्शन दर्शाता है कि स्थानीय शासन को जब भरोसा, संसाधन और प्रशिक्षण दिया जाए, तो वह चमत्कारी रूप से कार्य कर सकता है।

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का महत्व

हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाने वाला यह दिवस भारत के संविधान के 73वें संशोधन की याद में मनाया जाता है, जिसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देकर उन्हें लोकतंत्र की जड़ों तक पहुंचाया। इसी अवसर पर जारी किया गया PAI सूचकांक गुजरात की पंचायत व्यवस्था की सफलता को राष्ट्रीय स्तर पर उजागर करता है।

उत्तराखंड में बनी सबसे लंबी सुरंग

न्यूज़ डेस्क

उत्तराखंड में देश की सबसे लंबी सुरंग बनाई गई। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना में सुरंग नंबर–8 को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इसके साथ ही रेलवे के बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल हो चुका है। यह भारत के लिए बड़ी बात है। 14.58 किलोमीटर लंबी यह सुरंग जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में मौजूदा रेल और सड़क सुरंगों को पीछे छोड़ते हुए देश की सबसे लंबी ट्रांसपोर्टेशन सुरंग बनने जा रही है। हिमालय के दुर्गम इलाके में इस सुरंग का निर्माण एक बड़ी इंजीनियरिंग उपलब्धि है। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग परियोजना में 16 मुख्य सुरंगें (104 किमी), 12 एस्केप सुरंगें (97.72 किमी) और 7.05 किमी क्रॉस पैसेज हैं, जो कुल मिलाकर 213.57 किमी सुरंगों की प्रभावशाली लंबाई है। इसमें से 195 किमी का निर्माण पहले ही हो चुका है। यह परियोजना हिमालयी क्षेत्र में भारतीय रेलवे द्वारा टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) के पहले सफल प्रयोग को भी दिखाती है।

यह सुरंग महत्वाकांक्षी ऋषिकेश-कर्णप्रयाग ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का हिस्सा है, जो उत्तराखंड में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण परियोजना है। यह लाइन तीर्थ स्थलों को जोड़ेगी, पर्यटन को बढ़ावा देगी, स्थानीय व्यवसायों को मदद पहुंचाएगी। यात्रा के समय को काफी कम करेगी। देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गौचर और कर्णप्रयाग जैसे शहर सीधे जुड़ेंगे। पूरी परियोजना की देखरेख कर रहे रेल मंत्रालय के अधीन आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम रेल विकास निगम लिमिटेड ने जर्मनी में निर्मित 'शक्ति' नामक टनल बोरिंग मशीन का उपयोग करके यह सफलता हासिल की। सुरंग-8 दोहरी सुरंग है और दूसरी समानांतर सुरंग पर दूसरे टीबीएम की मदद से काम चल रहा है। जुलाई तक इसके दूसरे पार पहुंचने की उम्मीद है। इस सुरंग निर्माण का ठेका एलएंडटी कंपनी के पास है।

राजस्थान के भजनलाल मंत्रिमंडल में फेरबदल संभव

न्यूज़ डेस्क

राजस्थान सरकार में कुछ मंत्रियों के विभाग बदल सकते हैं जबकि कुछ विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल भी किया जा सकता है राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चा के बाद प्रदेश के मंत्रियों के दिल्ली दौरे शुरू हो गए हैं। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा आज दिल्ली दौरे पर हैं। बताया जा रहा है कि भजनलाल मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिल चुकी है। ऐसे में 30 अप्रैल से पहले फेरबदल देखने को मिल सकता है। जिसमें कई चेहरे को मौका मिलेगा तो वहीं, आधा दर्जन मंत्रियों को संगठन में शिफ्ट किया जा सकता है। चूंकि कई मंत्रियों के परफॉर्मेंस से केंद्रीय नेतृत्व नाखुश है।

किरोड़ी लाल का होगा फैसला

मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने लोकसभा चुनाव में पूर्वी राजस्थान की सीटों पर हार के बाद (करीब 11 महीने पहले) मंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया था। जिसके बाद वे लगातार आलाकमान के संपर्क बने हुए हैं। हालांकि कुछ दिन पहले वे हाईकमान के आदेश की बात कहते हुए विभागीय काम करते हुए भी नजर आए। इससे पहले वे संबंधित विभाग की बैठक, विधानसभा की कार्रवाई में शामिल नहीं हो रहे थे। मंत्रिमंडल की चर्चा के बीच किरोड़ी लाल मीणा आज दिल्ली पहुंचे हैं। सूत्रों के मुताबिक उनके विभाग में फेरबदल किया जा सकता है।

इन विधायकों को मिल सकती है जिम्मेदारी

प्रदेश में मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर शीर्ष नेतृत्व की ओर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को फ्री हैंड दिया गया है। ऐसे में सीएम परफॉर्मेंस के अनुसार मंत्रियों को प्रमोट कर सकते हैं। बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह, केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम, निंबाहेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी, फलोदी विधायक पब्बाराम विश्नोई को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इसके अलावा कुछ राज्य मंत्रियों का प्रमोशन भी लगभग तय माना जा रहा है। वहीं, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग को प्रमोट किया जा सकता है। इसके साथ ही कई विधायकों को संसदीय सचिवों की भी जिम्मेदारी दी जाएगी।

सीएम के दिल्ली दौरे के बाद होगा फेरबदल

सियासी हलकों में चर्चा है कि मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा इसी हफ्ते एक बार फिर दिल्ली जा सकते हैं। दिल्ली से ही नामों पर मुहर लगेगी। मुख्यमंत्री के दिल्ली से लौटने के बाद फेरबदल की घोषणा होना तय है। गौरतलब है कि सीएम ने शुक्रवार को दिल्ली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय केशव कुंज में संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाक़ात की। जिसके बाद सीएम ने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पहुंचकर भाजपा संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की थी।

फिर चर्चा में क्यों है पाकिस्तान से भारत आयी सीमा हैदर?

न्यूज़ डेस्क

जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में जहाँ 28 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है वही अब भारत के पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा और कड़ा फैसला लेते हुए सार्क वीजा छूट की नीति के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को दी जा रही सुविधा समाप्त कर दी है। इस निर्णय के अनुसार अब पाकिस्तानी नागरिक इस छूट के अंतर्गत भारत की यात्रा नहीं कर सकेंगे। वहीं, जो पाकिस्तानी नागरिक पहले से इस सुविधा के तहत भारत में मौजूद हैं। उन्हें एक सप्ताह के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। वहीं, इस फैसले के बाद सीमा हैदर एक बार फिर से चर्चाओं में आ गई हैं। पाकिस्तान की सीमा हैदर मई 2023 में नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत आई थीं। सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें पाकिस्तान भेजने की मांग की है।

सीमा हैदर की कहानी सोशल मीडिया से लेकर समाचार चैनलों तक में पहले भी सुर्खियों में रह चुकी है। वह ऑनलाइन गेम पब्जी के जरिए ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन मीणा से जुड़ीं और दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। इसके बाद सीमा अपने चार बच्चों के साथ भारत आ गईं। अब वह सचिन के साथ नोएडा में रह रही हैं और हाल ही में दोनों को एक बच्चा भी हुआ है।

सरकार के फैसले का सीमा हैदर पर क्या होगा असर?

सरकार के ताजा फैसले के बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या इसका असर सीमा हैदर पर भी पड़ेगा। हालांकि, पुलिस के जानकारों के मुताबिक सीमा पर कोई सीधा असर नहीं होगा। क्योंकि सीमा वीजा के जरिए भारत नहीं आई थीं, बल्कि अवैध तरीके से सीमा पार कर भारत में दाखिल हुई थीं। उनके खिलाफ मामला अदालत में विचाराधीन है और जब तक कोर्ट कोई फैसला नहीं देती, तब तक उन्हें देश से निकाला नहीं जा सकता। जेवर कोतवाली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और केंद्र सरकार से कानूनी राय भी मांगी गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए किसी भी तरह का निर्णय पूरी कानूनी प्रक्रिया के बाद ही लिया जाएगा। बता दे कि पुलगाम में हमले के बाद भारत-पाकिस्तान संबंधों में लगातार तनाव है। भारत सरकार का यह निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक अहम और रणनीतिक कदम माना जा रहा है।

न्यू देहली पोस्ट

आखिर किडनी काम करना क्यों बंद कर देती है?

हेल्थ डेस्क

अक्सर हम सुनते हैं कि फलां आदमी का किडनी काम करना बंद कर दिया या फिर किसी की फेल हो गई। आस -पड़ोस में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो किडनी के मरीज हो सकते हैं। ऐसे में आज हमें किडनी के बारे में जानकारी रखने की जरूरत है। आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे शरीर में किडनी का क्या काम है और यह कितनी जरूरी अंग है।

किडनी हमारे शरीर का एक जरूरी अंग है, जो खून को साफ करने, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने और पानी एवं मिनरल्स के संतुलन को बनाए रखने का काम करती है। लेकिन जब किडनी काम करना बंद कर देती है, तो यह गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन जाती है। किडनी फेल होने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ बेहद आम लेकिन खतरनाक हैं।

डायबिटीज

डायबिटीज किडनी फेलियर का सबसे बड़ा कारणों में से एक है। जब ब्लड शुगर लेवल अनियंत्रित होता है, तो यह किडनी की नलियों को नुकसान पहुंचाता है और धीरे-धीरे किडनी की कार्यक्षमता को प्रभावित करता है। इसके लिए जरूरी है बैलेंस डाइट लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें और ब्लड शुगर को कंट्रोल रखें।

हाई ब्लड प्रेशर

हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन किडनी की ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचा सकता है। जब किडनी को पर्याप्त ब्लड फ्लो नहीं मिलता, तो वह धीरे-धीरे कमजोर होने लगती है और सही तरीके से काम करना बंद कर देती है। नियमित रूप से चेकअप करवाएं, नमक का सेवन कम करें और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं।

ज्यादा दवाओं का सेवन

लंबे समय तक पेनकिलर, एंटीबायोटिक्स या स्टेरॉयड का सेवन करने से किडनी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कई दर्द निवारक दवाएं किडनी की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिससे उसका कार्य प्रभावित होता है। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा लंबे समय तक न लें और प्राकृतिक उपचार को प्राथमिकता दें।

किडनी में संक्रमण या पथरी होने से उसका कार्य बाधित हो सकता है। बार-बार होने वाले यूरीनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन और किडनी स्टोन समय के साथ किडनी को कमजोर बना सकते हैं

पानी की कमी

किडनी को सही तरीके से काम करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की जरूरत होती है। जब शरीर में पानी की कमी होती है, तो टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और किडनी पर दबाव बढ़ जाता है। रोजाना कम से कम 8-10 गिलास पानी पिएं और गर्मी के मौसम में ज्यादा हाइड्रेटेड रहें।

संक्रमण और किडनी स्टोन

किडनी में संक्रमण या पथरी होने से उसका कार्य बाधित हो सकता है। बार-बार होने वाले यूरीनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन और किडनी स्टोन समय के साथ किडनी को कमजोर बना सकते हैं. साफ-सफाई का ध्यान रखें, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचें और ज्यादा पानी पिएं।

आखिर क्यों नेक और हेड कैंसर के शिकार हो रहे युवा?

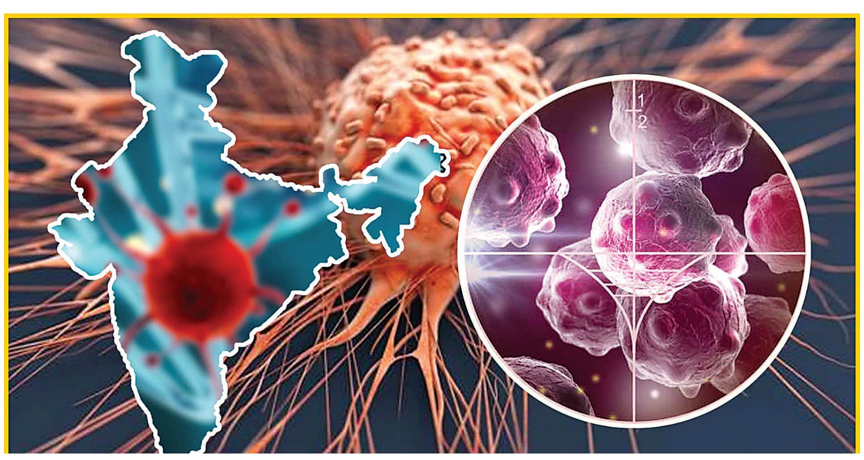

हेल्थ डेस्क

आजकल युवाओं में हेड और नेक कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जो चिंता का विषय बन गया है। इसी को देखते हुए अप्रैल में हेड और नेक कैंसर जागरूकता माह मनाया जाता है, ताकि लोगों को इस कैंसर के बारे में जागरूक किया जा सके। डॉक्टरों का कहना है कि इस कैंसर के पीछे कई कारण हैं, जिनमें सबसे बड़ा है तंबाकू का सेवन। बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, गुटखा, सुपारी, जर्दा या खैनी- ये सभी आदतें युवाओं को कम उम्र में ही कैंसर की बीमारी दे रहे हैं। इसके अलावा शराब का सेवन, वायु और जल प्रदूषण, खाने में कीटनाशकों व रसायनों की मिलावट भी कैंसर के खतरे को बढ़ा रहे हैं। तनाव, अनियमित नींद और अस्वास्थ्यकर खान-पान जैसी आधुनिक जीवनशैली की समस्याएं भी इस बीमारी को बढ़ावा दे रही हैं।

डॉक्टरों की माने तो आजकल युवाओं में अधिकतर कैंसर सिर और गर्दन के हिस्सों में होता है। इसमें मुंह, जीभ, गाल की अंदरूनी त्वचा, गला, टॉन्सिल, आवाज की नली, खाने की नली का ऊपरी हिस्सा, नाक, साइनस और आंखों के आसपास की हड्डियां शामिल हैं। कुछ मामलों में थायराइड और पैरोटिड ग्रंथि का कैंसर भी इसी श्रेणी में आता है। यह बीमारी किसी को भी हो सकती है, लेकिन तंबाकू और शराब का सेवन करने वालों में इसका जोखिम ज्यादा होता है। इस कैंसर के शुरुआती लक्षणों को पहचानना बेहद जरूरी है। विशेषज्ञों का कहना है कि मुंह में छाला जो ठीक न हो, जीभ या गाल में गांठ, आवाज में बदलाव, निगलने में दिक्कत, गले में खराश या दर्द, कान में दर्द, गर्दन में सूजन या गांठ, नाक से खून या काला म्यूकस जैसे लक्षण दिख सकते हैं। अगर ये लक्षण लंबे समय तक रहें, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। शुरुआती जांच से इलाज आसान हो सकता है।

हेड और नेक कैंसर का निदान कैसे होता है? अगर कोई घाव या गांठ ठीक नहीं हो रही, तो बायोप्सी की जाती है। इसमें प्रभावित हिस्से से ऊतक का नमूना लेकर जांच की जाती है। सीटी स्कैन, एमआरआई या पेट स्कैन जैसे टेस्ट से कैंसर की स्टेज और फैलाव का पता लगाया जाता है। अब नई तकनीक 'लिक्विड बायोप्सी' भी आ रही है, जिसमें खून के नमूने से कैंसर का पता लग सकता है। यह उन मामलों में मददगार है, जहां बायोप्सी करना मुश्किल होता है। इलाज के बाद कैंसर दोबारा हो सकता है, खासकर अगर मरीज तंबाकू या शराब जैसी आदतें नहीं छोड़ता। एडवांस स्टेज वाले कैंसर में यह खतरा ज्यादा होता है। मरीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इसमें अहम भूमिका निभाती है। अब लिक्विड बायोप्सी जैसे टेस्ट से इलाज के बाद भी निगरानी की जा सकती है, जिससे कैंसर के दोबारा उभरने की स्थिति का जल्दी पता लगाया जा सकता है।

अचानक हुए हार्ट अटैक से आप बच सकते हैं, बशर्ते

हेल्थ डेस्क

हार्ट अटैक किसी को कहीं भी हो सकता है। आज देश के लाखों लोग हार्ट रोग से पीड़ित हैं और हर साल लाखों लोगों की जाने भी इस बीमारी से चली जाती है। लेकिन अभी हाल में किए गए एक अध्ययन से यह सामने आया है कि दिल के दौरे से बचने का एक सस्ता और प्रभावी तरीका है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले ही एक दिल का दौरा झेला हो।

इस शोध में बताया गया है कि स्टैटिन्स और एजेटिमिब नाम दो कम कीमत वाली दवाइयों का कॉम्बिनेशन हार्ट अटैक के जोखिम को काफी हद तक कम कर सकता है और फिर से हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। स्वीडन और लंदन के के शोधकर्ताओं ने 36,000 से ज्यादा दिल के मरीजों के डेटा का विश्लेषण किया और पाया कि अगर इन दवाइयों का समय पर इस्तेमाल किया जाए, तो यह हार्ट अटैक को रोकने में बेहद प्रभावी हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कोलेस्ट्रॉल को पहले से कंट्रोल किया जाए तो दिल के दौरे का जोखिम काफी कम हो सकता है।

इलाज क्यों ज़रूरी है ?

हार्ट अटैक आने के बाद शरीर एक सेंसिटिव कंडीशन में पहुंच जाता है, जहां आर्टरीज कमजोर हो जाती हैं और दूसरे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि, कई मरीजों को तुरंत कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाइयां नहीं दी जाती। मौजूदा समय में, डॉक्टरों का तरीका 'वेट एंड वॉच' होता है, जिसमें पहले एक दवा दी जाती है और फिर जरूरत के हिसाब से अन्य दवाएं शुरू की जाती हैं, लेकिन इस समय पर दवाइयां न देने से नुकसान हो सकता है।

स्टैटिन्स और एजेटिमिब का संयोजन

स्टैटिन्स पहले से ही दिल की बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां हैं। यह लीवर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करती हैं, खासकर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसे खराब माना जाता है। वहीं, एजेटिमिब आंतों में कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को रोकता है। जब दोनों दवाइयां मिलकर काम करती हैं, तो यह कोलेस्ट्रॉल को जल्दी और प्रभावी तरीके से कम करती हैं।

क्या कहता है अध्ययन ?

स्वीडन और यूके के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए इस अध्ययन में हार्ट अटैक के बाद बचने वाले मरीजों का अध्ययन किया गया। तीन ग्रुप की तुलना की गई. इसमें सिर्फ स्टैटिन्स लेने वाले थे, जो बाद में एजेटिमिब ले रहे थे. जो दोनों दवाइयाँ दिल के दौरे के 12 हफ्ते के अंदर ले रहे थे। रिजल्ट से यह सामने आया कि जिन मरीजों को जल्दी कॉम्बिनेशन इलाज मिल रहा था, उसके पास दिल की समस्याएं भविष्य में कम आई, दूसरी बार हार्ट अटैक का खतरा भी कम था और मृत्यु दर भी कम थी।

पॉपुलर पेड़ की खेती से हो सकती है लाखों की कमाई

कृषि डेस्क

अगर आप कम समय में लखपति बनाना चाहते हैं, तो पॉपुलर पेड़ (जिसे चिनार भी कहते हैं) की खेती कर सकते हैं। इसकी खेती से आप कुछ सालों में 8 से 10 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। किसान भाई गेहूं, धान, मक्का जैसी पारंपरिक फसलों के साथ-साथ आसानी से पॉपुलर की खेती कर सकते हैं। इसके पेड़ की लकड़ी की मांग देश ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी काफी तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है। साथ ही पॉपुलर की लकड़ी बाजारों में अच्छे भाव से भी बिकती है, जिससे किसानों को अच्छा खासा अतिरिक्त मुनाफा मिल जाता है।

लागत कम और मुनाफा अधिक

पॉपुलर की खेती और पौधारोपण से कई किसान मालामाल हुए हैं। बाजार में पॉपुलर पेड़ की डिमांड बहुत है और इसकी खेती में लागत कम और मुनाफा अधिक होता है। किसान अपने खेत की मेढ़ पर पॉपुलर के पौध लगाकर कुछ ही सालों में अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इसके अलावा, पर्यावरण सरंक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। पॉपुलर की खेती किसानों के लिए मुनाफे का सौदा साबित हो रही है, जिससे किसानों का रुझान इसकी खेती में तेजी से बढ़ने लगा है।

कुछ साल में मिलेगी लाखों की कमाई

पॉपुलर की लकड़ी और छाल का उपयोग प्लाइवुड, माचिस की तीलियां, फर्नीचर बोर्ड बनाने और कागज उद्योग में किया जाता है। इसके अलावा, खेल की वस्तुएं और पेंन्सिल बनाने में भी इसकी लकड़ी यूज होती है, जिससे बाजार में पॉपुलर लकड़ी की डिमांड और कीमत काफी हाई बनी रहती है। पॉपुलर का पौधा 4 से 5 साल में पूर्ण तैयार होकर पेड़ बन जाता है। इसके पेड़ की ऊंचाई लगभग 50 से 60 फुट और मोटाई 3 -4 फुट तक हो जाती है। बाजार में पॉपुलर की लकड़ी 700 से 800 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बिकती है। एक हेक्टेयर क्षेत्र में करीब 200 से 250 पौधे लगाएंगे तो आप लगभग कुछ साल में इससे 8 से 10 लाख रुपए की कमाई कर सकते हैं।

पॉपुलर के पौधे फरवरी से अप्रैल महीने तक लगाए जा सकते हैं। पौधरोपण के लिए पहले एक मीटर गहरे गड्ढे तैयार करें। गड्ढों के बीच की दूरी 5 से 6 मीटर की रखें। रोपाई के 4 से 5 साल में इसका पेड़ तैयार हो जाता है। इसके साथ गेहूं, मक्का, धान एवं अन्य फसलों की खेती की जा सकती है।

बड़ी संख्या में किसान कर रहे हैं इसकी खेती

जानकारी के लिए बता दें कि कुछ साल पहले इसकी लकड़ी के दाम कम होने से किसानों ने पॉपुलर की खेती से मुंह मोड़ लिया था, लेकिन अब बाजारों में इसकी लकड़ी के दाम फिर से आसमान छूने लगे हैं, जिससे अब पॉपुलर की खेती में किसानों का रुझान बढ़ने लगा है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में बड़ी संख्या में किसान अब अपने खेत के मेढ़ पर इसके पौधारोपण कर, उत्पादन से मुनाफा कमा रहे हैं। जिला उद्यान अधिकारी की जानकारी के अनुसार, पॉपुलर के पौधों की रोपाई 18-20 डिग्री तापमान के बीच करना चाहिए, जबकि, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री और अधिकतम तापमान 45 डिग्री में पेड़ों का विकास बेहतर होता है।

पॉपुलर के पौधे कैसे लगाएं

पॉपुलर के पौधे फरवरी से अप्रैल महीने तक लगाए जा सकते हैं। पौधरोपण के लिए पहले एक मीटर गहरे गड्ढे तैयार करें। गड्ढों के बीच की दूरी 5 से 6 मीटर की रखें। रोपाई के 4 से 5 साल में इसका पेड़ तैयार हो जाता है। इस दौरान इसके साथ गेहूं, मक्का, धान एवं अन्य फसलों की खेती की जा सकती है। पॉपुलर का एक तैयार पेड़ का वजन करीब तीन से साढ़े तीन क्विंटल के आस-पास होता है। अगर इसका औसत वजन तीन क्विंटल भी निकाला जाए तो भी इसके एक हेक्टेयर खेत से चार साल में लाखों रुपए का मुनाफा कमाया जा सकता है। पॉपुलर की 109 नंबर वैरायटी के पौधे, इसकी कमर्शियल खेती के सबसे उपयुक्त होते हैं। किसान इसे लगाकर इसके उत्पादन से काफी अच्छी कमाई कर सकते हैं।

करें मेंथा और खस जैसी फसलों की खेती होगी अच्छी कमाई

कृषि डेस्क

बिहार के किसान पारम्परिक खेती को छोड़कर अब ब्यावसायिक खेती पर अब ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मेंथा और खस की खेती से बिहार के किसान मालामाल हो रहे हैं। सरकार इस खेती के लिए बड़े स्तर पर अनुदान भी दे रही है। किसान इसका लाभ लेकर मेंथा और खस की खेती से अच्छी कमाई कर रहे हैं। बिहार के किसान कहते हैं कि किसानों को पारंपरिक फसलों की तुलना में मॉडर्न फार्मिंग से ज्यादा लाभ होता है।

किसानों को पारंपरिक फसलों की तुलना में मॉडर्न फार्मिंग से ज्यादा लाभ होता है। ऐसे ही एरोमेटिक फसलों की खेती किसानों के लिए मुनाफेदार होती है। बिहार सरकार के द्वारा कुछ फसलों की खेती के लिए अनुदान दिया जा रहा है और यहाँ के किसान इसका भरपूर लाभ भी ले रहे हैं। मेंथा और खस एक औषधीय खेती है जिससे भारी मुनाफा कमाया जा सकता है।

बिहार में औषधीय खेती करने पर सरकार के द्वारा जोर दिया जा रहा है। राज्य में अभी मेंथा 5,000 हेक्टेयर, खस 500 हेक्टेयर, लेमनग्रास 100 हेक्टेयर और तुलसी 100 से 150 हेक्टेयर में उगाई जा रही है। सबसे ज्यादा सारण, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, दरभंगा, छपरा, समस्तीपुर, सीवान, समस्तीपुर, औरंगाबाद, सहरसा, बेगूसराय जैसे जिलों में औषधीय फसलों की खेती पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है।

बिहार के किसानों से कई कंपनियों के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराई जा रही है। ऐसा माना जाता है कि अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में उगाए जाने वाले मेंथा और खस में खुशबू लगभग सात गुना ज्यादा पाई जाती है। इसलिए इस राज्य के किसानों से कई कंपनियों के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराई जा रही है।

मेंथा की हाई डिमांड के कारण इसकी खेती करने वाले किसानों को भी खूब मुनाफा होता है। मेंथा का इस्तेमाल टूथपेस्ट, दवा, च्विंगम जैसी कई चीजों के निर्माण में किया जाता है। सबसे ज्यादा मेंथा और खस का उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जाता है। इसके बाद बिहार का नंबर आता है। मेंथा की बढती डिमांड के कारण कई बड़ी-बड़ी कम्पनियां भी इसमें निवेश करने लगी है। बाजार में मेंथा के तेल का दाम 1,000 रुपये लीटर है।अब देश भर में कृषि विभाग के द्वारा भी इसका रकबा बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। किसान इसकी खेती करके खूब कमाई कर सकते हैं।

आईआईटी कानपुर की पहल ,खेती हुआ स्मार्ट

कृषि डेस्क

विज्ञान और नवाचार से अब खेती भी स्मार्ट होती जा रही है। इस दिशा में आईआईटी कानपुर के स्टार्टअप इन्क्यूबेटर ने एक अनोखी पहल की है। इससे किसान तो स्मार्ट हो ही रहे हैं ,इससे मिट्टी और पर्यावरण भी सुधारे जा रहे हैं।खास बात यह है कि इस तकनीक की तैयारी में एक ऐसा सामान काम में लिया गया है, जिसे अब तक कचरा समझा जाता था। यह सामग्री है मुर्गियों के पंख।

आईआईटी कानपुर के एसआईआईसी के स्टार्टअप्स के तीन होनहार छात्रों अधीश गुप्ता, मोहम्मद रशीद और ऋषभ ने तीन साल की कड़ी मेहनत के बाद मुर्गियों के पंखों से तैयार एक खास नोवो पॉलिमर प्लास्टिक बनाया है। यह प्लास्टिक पूरी तरह बायोडिग्रेडेबल है और खेतों में पारंपरिक

प्लास्टिक मल्चिंग की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। अब तक खेती में जो प्लास्टिक का इस्तेमाल होता था, वह मिट्टी को कमजोर कर देता था और पर्यावरण के लिए भी खतरा बनता था। लेकिन इस नए पॉलिमर की खासियत यह है कि छह महीने में यह मिट्टी में खुद बायोडिग्रेड हो जाता है। मुर्गियों के पंखों में मौजूद पोषक तत्व जमीन को और उपजाऊ बनाते हैं. पानी का प्रदूषण नहीं होता और मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है। इस तकनीक से खेत की मिट्टी की ताकत बढ़ेगी और किसान बार-बार प्लास्टिक को हटाने के झंझट से बचेंगे। यह स्टार्टअप न केवल किसानों को अधिक फसल उपजाने में मदद करेगा, बल्कि खेती के पारंपरिक तरीकों को आधुनिक पर्यावरण-अनुकूल और टिकाऊ बनाएगा। मुर्गियों के पंख, जिन्हें अब तक सिर्फ कचरा समझा जाता था. अब खेती में वरदान साबित होंगे।

...और ट्रंप के खिलाफ कोर्ट पहुँच गई हावर्ड यूनिवर्सिटी

इंटरनेशनल डेस्क

अमेरिका में ट्रंप प्रशासन और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बीच शुरू हुए विवाद अब बढ़ता जा रहा है। विवाद इतना बढ़ गया है कि अब पूरा मामला कोर्ट में पहुंच चुका है। दरअसल, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन पर 2.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 18 हजार करोड़ रुपये) की फंडिंग रोकने को लेकर मुकदमा दायर किया है। यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट एलन एम गार्बर ने ट्रंप प्रशासन पर अभूतपूर्व और अनुचित नियंत्रण करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि सरकार की कार्रवाई के गंभीर और लॉन्ग टर्म परिणाम होंगे।

हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा फेडरल कोर्ट में दायर मुकदमे में कहा गया है कि ट्रंप प्रशासन ने फेडरल फंडिंग के रूप में अरबों डॉलर रोककर संस्थान के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। यह मुकदमा ट्रंप प्रशासन की उस कार्रवाई के जवाब में दायर किया गया है, जिसमें उसने हार्वर्ड को दी जाने वाली 9 अरब डॉलर की फंडिंग की समीक्षा शुरू की थी और 2.3 अरब डॉलर की फंडिंग को पहले ही फ्रीज कर दिया था। हार्वर्ड का दावा है कि यह कार्रवाई यूनिवर्सिटी की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कमजोर करती है। रिपोर्ट के अनुसार, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट एलन गार्बर

ने कम्युनिटी मैसेज में कहा, सरकार के अतिक्रमण के परिणाम गंभीर और दीर्घकालिक होंगे। गार्बर ने तर्क दिया कि फंडिंग में कटौती के कारण चाइल्ड कैंसर, संक्रामक रोग प्रकोप और और घायल सैनिकों की पीड़ा कम करना समेत कई रिसर्च रिस्क में हैं।

उन्होंने कहा कि फेडरल रिसर्च फंडिंग में अरबों डॉलर की रोक से हार्वर्ड के रिसर्च कार्यक्रमों, इसके लाभार्थियों, इनोवेशन और प्रगति को लेकर अहम परिणाम होंगे। हार्वर्ड ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने फंडिंग को हथियार बनाकर यूनिवर्सिटी के शैक्षणिक निर्णयों पर नियंत्रण करने की कोशिश की है।

आपको बता दें, ट्रंप प्रशासन ने 11 अप्रैल को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को पत्र लिखकर कहा था कि विश्वविद्यालय में बड़े पैमाने पर सुधार करने

ट्रंप प्रशासन ने 11 अप्रैल को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को पत्र लिखकर कहा था कि विश्वविद्यालय में बड़े पैमाने पर सुधार करने और एडमिशन के लिए बनी नीतियों में बदलाव किए जाने की जरूरत है।

और एडमिशन के लिए बनी नीतियों में बदलाव किए जाने की जरूरत है। प्रशासन ने कहा था कि यूनिवर्सिटी में कुछ स्टूडेंट्स क्लब को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को एक चिट्ठी लिखकर मांग की थी कि विश्वविद्यालय परिसर में विविधता पर विचारों का ऑडिट करे और कुछ छात्र क्लबों को मान्यता देना बंद करें। इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने 3 अप्रैल को यूनिवर्सिटी के सामने मांग रखी थी कि यूनिवर्सिटी के गवर्नेंस, एडमिशन और हायरिंग प्रोसेस पर सरकार को नियंत्रण दिया जाए और इनमें बड़ा बदलाव किया जाए। इसके अलावा डाइवर्सिटी ऑफिस बंद करने और अंतरराष्ट्रीय छात्रों की जांच में इमिग्रेशन अफसरों की मदद करने की मांग भी रखी गई थी। हार्वर्ड ने इन मांगों को गैरकानूनी और असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया था। इसके बाद ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को मिलने वाली 2.2 बिलियन डॉलर से अधिक की ग्रांट को रोक दिया था।

ड्रैगन की लूट का अड्डा बना नेपाल का पोखरा एयरपोर्ट

इंटरनेशनल डेस्क

पड़ोसी देश नेपाल में चीन एक बड़ा खेल करते नजर आ रहा है। चीन का यह खेल नेपाल के पोखरा एयरपोर्ट बनाने के नाम पर करोडो डॉलर की लूट से जुड़ा है। लेकिन चीन के इस लूट कांड का खुलासा हो गया है। नेपाल के भीतर अब इस लूट कांड की चर्चा आम लोगों तक पहुँच गई है और स्थानीय लोग अब चीन को यहाँ से भगाने की बात भी करने लगे हैं। खुलासा के मुताबिक नेपाल की सरकारी जांच में पता चला है कि पोखरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण में चीन ने जमकर धांधली की है। चीनी सरकारी कंपनी ने हवाई अड्डे के निर्माण में घटिया सामान का इस्तेमाल किया और मंजूरी के लिए अधिकारियों और नेताओं को जमकर रिश्वत खिलाई। रिपोर्ट में ऐक्शन की सिफारिश की गई है।

हवाई अड्डे की सरकारी जांच में पाया गया है कि चीनी सरकारी कंपनी ने इसके निर्माण में घटिया उपकरणों का इस्तेमाल किया और मानकों के अनुसार पूरा नहीं किया। प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए चीनी कंपनी ने नेपाल में अधिकारियों और सांसदों को रिश्वत दी। यही नहीं, इसने उन कामों के लिए भी मंजूरी हासिल कर ली, जो उसने कभी किया ही नहीं। पोखरा हवाई अड्डे को लेकर संसदीय समिति की गुरुवार को जारी 36 पेज की जांच रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, संसदीय समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की सरकारी कंपनी सीएएमसी इंजीनियरिंग ने परियोजना को निर्देश के अनुसार पूरा नहीं किया और खराब गुणवत्ता वाले निर्माण का उपयोग किया। इसके पहले न्यूयॉर्क टाइम्स साल 2023 में अपनी रिपोर्ट में बताया था कि सीएएमसी ने परियोजना की लागत बढ़ा दी थी और अपने स्वयं के व्यावसायिक हितों को प्राथमिकता देते हुए गुणवत्ता नियंत्रण बनाए रखने के नेपाल के प्रयासों को कमजोर कर दिया था। इसके तुरंत बाद, 11 सदस्यीय संसदीय समिति ने हवाई अड्डे के निर्माण की जांच शुरू कर दी।

हिमालय की तलहटी में स्थित पर्यटन स्थल पोखरा में बना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नेपाल के लिए सफेद हाथी साबित हुआ है। यह चीन के कर्ज में गरीब देशों के फंसने का सीधा उदाहरण है। नेपाल को उम्मीद थी कि पोखरा हवाई अड्डा पर्यटन को बढ़ावा देगा और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को आकर्षित करेगा, लेकिन अब तक इस दिशा में नाकामी ही मिली है। पोखरा के लिए सप्ताह में केवल एक अंतराष्ट्रीय उड़ान है। भारत ने पोखरा के लिए किसी भी अंतराष्ट्रीय मार्ग को मंजूरी नहीं दी है। हवाई अड्डे का निर्माण चीन के निर्यात-आयात बैंक से 20 साल के कर्ज के साथ किया गया था। इसके पहले नेपाली मीडिया में रिपोर्ट आई थी कि चीन ने पोखरा हवाई अड्डे के कर्ज के लिए पहले जो ब्याज दर रखी थी, उसे अब बढ़ा दिया है। इस तरह नेपाल को कर्ज जाल में फंसाने के बाद अब चीन उस पर शिकंजा बढ़ा रहा है। कर्ज जाल में फंसने के बाद केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट सरकार ने बीजिंग से औपचारिक रूप से अनुरोध किया कि वह 21.6 करोड़ डॉलर के हवाई अड्डे के कर्ज को अनुदान में बदल दे।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नेपाली अधिकारियों ने सीएएमसी के लिए 16 मिलियन डॉलर का कर माफ कर दिया, जबकि अनुबंध में कहा गया था कि कंपनी चीन से आयातित उपकरणों पर सीमा शुल्क और मूल्य वर्धित कर का भुगतान करने के लिए बाध्य थी। अनुबंध में टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए दो रनवे की बात कही गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि हवाई अड्डे पर प्रभावी रूप से केवल एक ही ऑपरेटिंग रनवे है, क्योंकि दूसरा रनवे सुरक्षा कारणों से बंद है। जांच का नेतृत्व करने वाले राजेंद्र लिंगडेन ने कहा, 'यह भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला है। इस घोटाले में शामिल भ्रष्ट नौकरशाहों और राजनेताओं को दंडित किया जाना चाहिए।'

पोप फ्रांसिस का निधन दुनिया के लिए बड़ी क्षति

इंटरनेशनल डेस्क

पोप फ्रांसिस का बीते सोमवार को निधन हो गया। वह 88 वर्ष के थे। वेटिकन एक्सपर्ट प्रोफेसर फ्रांसेस्को सिस्की मानते हैं कि पोप फ्रांसिस का जाना कैथोलिक चर्च और मानवता के लिए एक झटका है, क्योंकि इस दौर में शायद किसी ने भी उनकी तरह दुनिया से जुड़ने की कोशिश नहीं की। प्रोफेसर सिस्की ने कहा, "उन्होंने सिर्फ कैथोलिक ही नहीं बल्कि सभी पुरुषों और महिलाओं से जुड़ने की कोशिश की चाहे उनकी जाति, नस्ल या राजनीतिक सोच कुछ भी हो। पोप फ्रांसिस का निधन इसलिए भी एक झटका है क्योंकि इस समय दुनिया में दो युद्ध चल रहे हैं, एक मध्य पूर्व में और दूसरा यूक्रेन में। इसलिए मुझे लगता है कि उनका जाना सभी के लिए एक बड़ी क्षति है।"

पोप फ्रांसिस के बाद कैथोलिक चर्च की क्या दशा और दिशा होगी इस संबंध में प्रोफेसर सिस्की ने कहा, "चर्च को कुछ हफ्तों में फैसला करना होगा। इसके लिए सम्मेलन होगा हालांकि हमें नहीं पता कि यह कितने समय तक चलेगा। यह एक बहुत बड़ा सम्मेलन होगा क्योंकि इसमें 137-138 कार्डिनल (कैथोलिक चर्च के पादरी वर्ग के वरिष्ठ सदस्य) इसमें भाग लेंगे। यह संख्या आमतौर पर 120 से कम होती है। दुनिया भर से लोग इसमें शामिल होंगे। तेहरान, लाओस, कार्डिनल, मंगोलिया सभी जगहों से कार्डिनल होंगे। यह अतीत में किसी भी अन्य सम्मेलन की तुलना में बहुत विविधतापूर्ण और ऐतिहासिक रूप से वैश्विक होगा।"

इतालवी लेखक और स्तंभकार ने कहा, "सम्मेलन के सामने संभवतः यह सवाल होगा कि हम किस तरह का पोप चाहते हैं? क्या हम एक ऐसे व्यक्ति को चाहते हैं जो चर्च की परेशानियों पर ध्यान केंद्रित करे या एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया की परेशानियों पर ध्यान केंद्रित करे?" बता दें कि पोप फ्रांसिस का निधन सोमवार यानी 21 अप्रैल सुबह वेटिकन के कासा सांता मार्टा स्थित उनके निवास स्थान पर हुआ। उनके निधन के समाचार से दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई। विश्व नेताओं ने उन्हें अपनी श्रद्धांजली दी और उन्हें ऐसे शख्स के रुप में याद किया जो गरीबों, कमजोरों के पक्ष में मजबूती से खड़ा रहा।

पोप फ्रांसिस ने मृत्यु से एक दिन पहले सेंट पीटर्स स्क्वायर में हजारों श्रद्धालुओं को 'हैप्पी ईस्टर' की शुभकामनाएं दी थीं। बेसिलिका की बालकनी से 35,000 से अधिक लोगों की भीड़ को ईस्टर की शुभकामनाएं देने के बाद, फ्रांसिस ने अपने पारंपरिक 'उर्बी एट ओर्बी' ('शहर और दुनिया के लिए') आशीर्वाद को पढ़ने का काम एक सहयोगी को सौंप दिया। उन्होंने भाषण में कहा, "धर्म की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और दूसरों के विचारों के प्रति सम्मान के बिना शांति नहीं हो सकती है।" उन्होंने "चिंताजनक" यहूदी-विरोध और गाजा में 'नाटकीय और निंदनीय' स्थिति की भी निंदा की।

सचिन के लिए मिडल स्टंप पर सिक्का क्यों रखते थे गुरु रमाकांत आचरेकर?

खेल डेस्क

सर्वकालिक महान बल्लेबाजों में शुमार 'क्रिकेट के भगवान' सचिन तेंदुलकर 24 अप्रैल को 53 वर्ष के होने जा रहे हैं। क्रिकेट के इस बेशकीमती नगीने को उनके बचपन के कोच रमाकांत आचरेकर ने तराशा था। वह हर दिन फाइनल प्रैक्टिस सेशन में मिडल स्टंप पर एक रुपये का सिक्का रखा करते थे। जानिए वो दिलचस्प किस्सा।

सचिन तेंदुलकर। लोग उन्हें क्रिकेट का भगवान कहते हैं। इकलौते खिलाड़ी जिनमें महानतम बल्लेबाज सर डॉन ब्रेडमैन को अपना अक्स दिखा। ऐसा खिलाड़ी जिसने क्रिकेट के रिकॉर्ड बुक को तहस-नहस कर डाला। सबसे ज्यादा रन। सबसे ज्यादा शतक। और भी न जाने कितने रिकॉर्ड। बेमिसाल अनुशासन और विनम्रता उनकी महानता को चार चांद लगाती हैं। सचिन तेंदुलकर गुरुवार यानी 24 अप्रैल को 53 वर्ष के हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि उनके गुरु रमाकांत आचरेकर उनकी बल्लेबाजी के दौरान मिडल स्टंप पर सिक्का क्यों रखते थे?

सचिन तेंदुलकरजिसे बयां करने के लिए शब्द भी कम पड़ जाए

सचिन की बात हो तो उन्हें बयां करने के लिए शब्दकोश के शब्द भी जैसे कम लगने लगते हैं। सच तो यही है कि यूं ही कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बन जाता है। उसके लिए चुनौतियों को अवसर बनाना पड़ता है। लगन, मेहनत, दृढ़ता, जिद, जुनून, जज्बा, प्रेरणा, अनुशासन, विनम्रता, सफलता की कभी न मिटने वाली भूख...इन तमाम विशेषणों, तमाम गुणों को अगर परिभाषित करना हो तो बस सचिन को देख लीजिए। ये शब्द, ये विशेषताएं भी जैसे उनका शुक्रगुजार हों कि उनकी शख्सियत ने दुनिया को दिखाया कि इन शब्दों के असली अर्थ क्या हैं। सचिन तेंदुलकर को उनके गुरु रमाकांत आचरेकर ने तराशा और क्या खूब तराशा।

यूं ही कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बन जाता

सचिन तेंदुलकर 10-11 की उम्र में प्रैक्टिस के लिए बांद्रा ईस्ट से 315 नंबर की बस पकड़कर शिवाजी पार्क जाया करते थे। वह 11 वर्ष की उम्र में पहली बार रमाकांत आचरेकर से मिले थे। कोच उन्हें एक मैदान से दूसरे मैदान तक ले जाते थे। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ ने अपनी न्यूज वेबसाइट पर सचिन तेंदुलकर से बातचीत पर आधारित एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसमें शुरुआती दिनों में मास्टर ब्लास्टर की दिनचर्या के बारे में बताया गया है। सचिन को कई बार एक ही दिन में 10-12 गेम तक खेलने पड़ते थे। गर्मियों में वह साढ़े 7 बजे सुबह से 2 घंटे तक नेट प्रैक्टिस कर बल्लेबाजी में पसीना बहाते थे। उसके बाद वह सीधे शिवाजी पार्क जाते थे। गर्मी के मौसम में 60 दिनों में वह 55 गेम खेलते थे।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ सचिन तेंदुलकर

ये मैच आम तौर पर दोपहर बाद साढ़े 4 बजे तक खत्म होते थे। उसके बाद 5 बजते-बजते तेंदुलकर एक बार फिर नेट में पहुंच जाते थे और अगले 2 घंटे तक फिर पसीना बहाते थे। इस दौरान वह 5 छोटे-छोटे ब्रेक लेते थे।

मिडल स्टंप पर सिक्का रखने का वो किस्सा

कोच रमाकांत आचरेकर अपने प्रिय शिष्य के लिए प्रैक्टिस के आखिरी 15 मिनट के सेशन में कुछ ऐसा करते थे जिसने सचिन को और ज्यादा निखारा। इसे मनोविज्ञान की भाषा में रिवॉर्ड ऐंड मॉटिवेशन सेशन कह सकते हैं। इस दौरान सचिन विकेट पर बल्लेबाजी का प्रैक्टिस किया करते थे। गुरु आचरेकर मिडल स्टंप पर एक रुपये का सिक्का रख दिया करते थे। सचिन अगर बिना आउट हुए पूरा सेशन निकाल लेते थे तो वह सिक्का उनका। यह बड़ी चुनौती थी क्योंकि 11 नहीं, 25-50 और कभी-कभी 70 तक फील्डर्स हुआ करते थे। खेल के हर बड़े पुरस्कार और देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान

'भारत रत्न' से नवाजे जा चुके सचिन तेंदुलकर के लिए उस एक रुपये के सिक्के को पाना सबसे बड़े पुरस्कार के जैसे था।

क्रिकेट के आसमान में सूरज के उगने का जब हो गया ऐलान

आचरेकर रूपी गुरु द्रोण का ये 'अर्जुन' सचिन तेंदुलकर जब 14 साल का हुआ तो बल्ले से ऐसा धमाका किया जो क्रिकेट के आकाश के सूरज के उगने की मुनादी थी। फरवरी 1988 का एक दिन। शिवाजी मैदान से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आजाद मैदान। एनुअल इंटर-स्कूल टूर्नामेंट हैरिस शील्ड का सेमीफाइनल मैच। शारदाश्रम विद्यामंदिर और सेंट जेवियर्स हाई स्कूल के बीच मुकाबला।

'क्रिकेट का भगवान'

विद्यामंदिर का 84 रन पर दूसरा विकेट गिरा तो सचिन तेंदुलकर बैटिंग के लिए आए। दूसरे छोर पर उनसे करीब 15 महीने बड़ा एक और लड़का था- विनोद कांबली। इन दोनों लड़कों ने दूसरे दिन लंच तक बल्लेबाजी की। टीम ने 748-2 के स्कोर पर पारी घोषित कर दी। कांबली ने नाबाद 349 और सचिन तेंदुलकर ने नाबाद 326 रन ठोके। दोनों के बीच 664 रनों की रिकॉर्ड और नाबाद साझेदारी हुई। उसके बाद तो जो हुआ वह इतिहास है। खेल का यह सूरज अंतरराष्ट्रीय फलक पर ऐसे चमका कि लोगों ने उसे 'क्रिकेट के भगवान' का दर्जा दे दिया।

दीपिका, अमिताभ बच्चन अभिनीत 'पीकू' मई में फिर से होगी रिलीज

फिल्मी डेस्क

शूजित सरकार द्वारा निर्देशित, पीकू फिल्म 8 मई, 2015 को मूल रूप में रिलीज हुई थी। दर्शकों ने इस फिल्म को खूब सराहा था। अब दस वर्षों के बाद यह फिल्म 9 मई को फिर से रिलीज होने जा रही है। इस साल पीकू अपनी 10वीं वर्षगांठ मनाएगी।इस फिल्म में दिवंगत इरफान खान, मौसमी चटर्जी और जीशु सेनगुप्ता भी हैं। पादुकोण ने भी पिछले शनिवार को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर इस खबर की घोषणा करते हुए एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने कहा कि "पीकू" हमेशा उनके दिल के करीब रहेगी और उन्होंने खान को याद किया। "एक फिल्म जो हमेशा मेरे दिल में रहेगी - 'पीकू' 9 मई, 2025 को अपनी 10वीं वर्षगांठ मनाने के लिए सिनेमाघरों में वापस आ रही है! इरफान, हमें आपकी याद आती है! और हम हर बार आपके बारे में सोचते हैं," कैप्शन में लिखा है।

फिल्म ने अपनी रिलीज के दौरान बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कारोबार किया और दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 140 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की। इसने बच्चन और पादुकोण द्वारा निभाए गए एक पिता और बेटी की दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाई। अब देखना होगा की दस साल बाद यह फिल्म दर्शकों को अपनी तरफ कैसे आकर्षित करती है।

सोनाक्षी सिन्हा अभिनीत थ्रिलर फिल्म 'निकिता रॉय' का पोस्टर रिलीज

फिल्मी डेस्क

हाल ही में सोनाक्षी सिन्हा अभिनीत साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म 'निकिता रॉय' का पोस्टर रिलीज हुआ है। अभिनेत्री के इस फिल्म के पोस्टर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। सोनाक्षी के तनाव और सीरियस लुक ने सभी को हैरान कर दिया है। फिल्म निर्माताओं द्वारा फिल्म की रिलीज डेट की भी घोषणा कर दी गई है। सोनाक्षी सिन्हा अपने दमदार लुक के साथ इस बार सिनेमाई पर्दे पर नजर आने वाली हैं। अभिनेत्री की आगामी फिल्म निकिता रॉय' के पोस्टर ने उनके लुक के बारे में कई सवाल पैदा कर दिए हैं। इस पोस्टर में सोनाक्षी सिन्हा के अलावा अर्जुन रामपाल, परेश रावल और सुहैल नय्यर भी नजर आ रहे हैं। फिल्म के पोस्टर में सभी किरदार सस्पेंस लुक में दिख रहे हैं। यह फिल्म एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है।

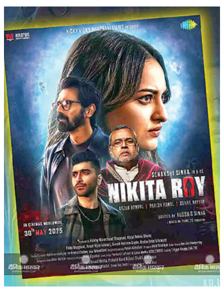

कब रिलीज होगी फिल्म?

'निकिता रॉय' फिल्म का निर्देशन कुश एस सिन्हा कर रहे हैं, जो इस फिल्म से डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू कर रहे हैं। यह फिल्म रहस्य, मनोवैज्ञानिक थ्रिलर की कहानी के साथ दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार है। सोनाक्षी सिन्हा की ये फिल्म 30 मई को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। इस फिल्म को निक्की विक्की भगनानी फिल्म्स और निकिता पाई फिल्म्स लिमिटेड के बैनर तले बनाया जा रहा है। वहीं, इस फिल्म का प्रोडक्शन निक्की खेमचंद भगनानी, किंजल आहूजा घोन और विक्की भगनानी ने किया है।

फिल्म निर्माताओं ने दी प्रतिक्रिया

सोनाक्षी सिन्हा अभिनीत फिल्म 'निकिता रॉय' को लेकर फिल्म निर्माता निक्की और विक्की भगनानी ने कहा है कि यह फिल्म उनके दिल के बहुत करीब है। यह फिल्म दर्शकों को वहां ले जाएगी, जहां मुख्यधारा की फिल्में नहीं ले जा पाती हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस फिल्म के कलाकार अपने शानदार अभिनय से दर्शकों का मनोरंजन करने को तैयार है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म रिलीज के समय पर सिनेमाघरों में क्या कमाल करती है।